



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 289]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 27, 2006/पौष 6, 1928

No. 289]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 27, 2006/PAUSA 6, 1928

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2006

अंतिम जांच परिणाम

विषय : इण्डोनेशिया, कोरिया, मलेशिया और ताईवान से पूर्णतः बटा हुआ अथवा पूर्णतः विन्यासित यार्न/स्पिन ड्रॉ यार्न/प्लैट यार्न के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

सं. 14/3/2005-डीजीएडी.—1995 में यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिन्हें एतदपश्चात् अधिनियम कहा जायेगा) और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 (जिन्हें एतदपश्चात् नियम कहा जाएगा) को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा जाएगा)

ने दिनांक 27 जून, 2005 की अधिसूचना के द्वारा इण्डोनेशिया, कोरिया गणराज्य, मलेशिया और चीनी-ताइपेई (जिन्हें एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) से पूर्णतः बटा हुआ अथवा पूर्णतः विन्यासित यार्न / (जिन्हें ड्रॉ यार्न/ पॉलिस्टर्स का प्लैट यार्न जिन्हें एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के कथित पाटन की जांच की शुरुआत की थी जो घरेलू उत्पादकों नामतः मैसर्स सेंट्रल इण्डिया पॉलिस्टर्स लि. मैसर्स सेंचुरी एन्का लि. मैसर्स गार्डन सिल्क मिल्स लि., मै. नौवा पेट्रोकेमिकल्स लि. मै. रेकॉन सिंथेटिक्स लि. और मै. सेलस्पन सिन्टेक्स लि. की ओर से मै. एसोसिएशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर इण्डस्ट्रीज (जिन्हें एतदपश्चात् याचिककर्ता कहा गया है) से एक

पूर्णतः प्राप्त प्रलेखित अभ्यावेदन के आधार पर थी और जिसमें संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के कथित पाटन का आरोप लगाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योग की क्षति हुई है।

2. प्राधिकारी ने दिनांक 3 जुलाई, 2006 की अधिसूचना के द्वारा अपने प्रारंभिक जांच परिणामों को अधिसूचित किया है और राजस्व विभाग ने दिनांक 21, अगस्त, 2006 की अपनी अधिसूचना सं. 82/2006 सी.शु. के द्वारा प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिश पर संबद्ध वस्तु पर अनंतिम शुल्क लगाया है।
3. नियमावली के नियम 17 (1) के अनुसार केन्द्र सरकार ने जांच को पूरा करने की समयावधि को 26 दिसम्बर, 2006 तक बढ़ा दिया है।

क. प्रक्रिया

4. प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच परिणामों को अधिसूचित करने के बाद जांच के संबंध में पालन की जाने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा निम्नानुसार है:—
1. विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के सहयोगी निर्यातकों, घरेलू उद्योग तथा जांच में भाग ले रहे आयातकों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से प्रारंभिक जांच परिणामों को अधिसूचित किये जाने के 40 दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध करते हुए उन्हें दिनांक 27 अप्रैल 2006 के प्रारंभिक जांच परिणामों की प्रति भेजी है।
2. प्रारंभिक जांच परिणामों पर प्रतिक्रिया स्वरूप हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई टिप्पणियों को रिकार्ड में रखा गया है और प्राधिकारी ने इस पश्य प्रकटन विवरण में उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच की है।
3. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अवलोकन के लिए रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया है।
4. संक्षिप्तता के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों, तथा प्रारंभिक जांच परिणामों से पूर्व उठाए गए एवं उसमें समाधान किए गए मुद्दों को इस पश्य प्रकट विवरण में दोहराया नहीं गया है।

5. सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकारी ने 18.8.2006 को सार्वजनिक सुनवाई की। सार्वजनिक सुनवाई के दौरान पक्षकारों द्वारा किए गए मौखिक अभ्यावेदनों, जिन्हें लिखित में पुनः प्रस्तुत किया गया, को इस जांच के प्रयोजनायें रिकार्ड में रखा गया है।
 6. प्राधिकारी ने अपने द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के संबंध में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता संबंधी दावों की जांच की है। सूचना जिसकी प्रकृति गोपनीय है अथवा जिसे अगोपनीय सारांश के साथ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत किया गया, को गोपनीय माना गया है। इस प्रकटन में.... याचिकाकर्ता द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना को दर्शाता है और उस प्राधिकारी द्वारा नियमों के तहत गोपनीय ही गया है।
 7. यह जांच 1 जनवरी 2004 से 31 दिसम्बर 2004 (12 महीने) अर्थात् जांच की अवधि (पी.ओ.आई.) के लिए की गई थी। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच की अवधि में अप्रैल 2001 मार्च 2002, अप्रैल 2002 मार्च 2003 और अप्रैल 2003 मार्च 2004 और जांच की अवधि शामिल थी।
- ख. विचाराधीन उत्पाद समान वस्तु और घरेलु उद्योग
- ख1. विचाराधीन उत्पाद एवं समान उत्पाद।
5. वर्तमान जांच में शामिल उत्पाद पूर्णतः बटा हुआ और पूर्णतः विन्यासित यार्न/स्पिन ड्रॉ यार्न/ पालिस्टर का फलैट यार्न (गैर विन्यासित और गैर पी ओ वाई) तथा सीमाशुल्क शीर्ष 5402.43 के टैरिफ विवरणों से संगत अन्य यार्न (जिन्हें रुतदपश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) वाणिज्यिक बाजार में बोलचाल की भाषा में ऊपर लिखित उत्पाद को सामान्यतः "पूर्णतः बटे हुए यार्न" के रूप में जाना जाता है। संबद्ध वस्तु का उपयोग परिधानों घर में उपयोग किए जाने वाले कपड़ों और अन्य औद्योगिक वस्त्रों के विनिर्माण हेतु किया जाता है। संबद्ध वस्तुओं की तकनीकी विनिर्देशनों को उनके डेनियरों, सशक्ति, चमक, रंग (जैसे अर्धधूसर, चमकदार, अत्यंत चमकदार, पूर्णतः धूसर, रोगन किया हुआ), अनुप्रस्थीय काट और संकुचन के आधार पर परिभाषित किया जाता है। जांच के दौरान यह

नोटिस किया गया है कि सीमा शुल्क शीर्ष 5402-42 के तहत भी संबद्ध वस्तु की अत्यधिक मात्रा का आयात किया गया है। अतः इस जांच के प्रयोजनार्थ सीमाशुल्क शीर्ष 5402.42 तथा 5402 के तहत आयातित वस्तुओं पर विचार किया गया है। तथापि ये वर्गीकरण सांकेतिक मात्र हैं और इस जांच के क्षेत्र पर किसी भी प्रकार बाध्यकारी नहीं है।

कोरिया गणराज्य के निर्यातकों ने यह तर्क दिया है कि एफ.डी.वाई. की अनेक किस्मों का जांच अवधि के दौरान भारत में विनिमय तथा बिक्री नहीं की जाती थी और इसलिए इन ग्रंडो को विचाराधीन उत्पाद से बाहर रखा जा सकता है। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि भारत में कुछेक अन्य ग्रेडो का उत्पादन कम मात्रा में किया गया था और इसलिए इसे सार्थक क्षति निर्धारण और संभावित सीमित बाजार के कारण बाहर रखना चाहिए।

घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि विचाराधीन उत्पाद फल्ली ड्रॉन यार्न है और जांच अवधि के दौरान निर्यातकों ने भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। अतः विचाराधीन उत्पाद पर बिना किसी ग्रेड को बाहर रखे, शुल्क लगाए जाने चाहिए।

8. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद वह उत्पाद है जिसका नियतिक देश के उत्पादको/ निर्यातकों द्वारा आयातक देश में कथित तौर पर पाटन किया जा रहा है तथा जिससे आयातक देश और समान उत्पाद के उत्पादक घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। अतः इस मुद्दे पर निर्णय लेना है कि क्या घरेलू उद्योग समान वस्तु का उत्पादन करता है जिस पर जांचाधीन उत्पाद के पाटन द्वारा क्षतिकारी प्रभाव पड़ा है।

9. आवेदकों का यह दावा है कि भारत में पाटन की जा रही संबद्ध वस्तुएं घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान वस्तु है। पाटित आयातों और घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तुओं के बीच न तो तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता, कार्यों की दृष्टि से और न ही अंतिम उपयोगों की दृष्टि से कोई अंतर है। कोरिया गणराज्य के निर्यातकों ने यह तर्क दिया है कि प्राधिकारी को इस बात

पर ध्यान देना चाहिए कि आयातों और घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तुओं के बीच तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता, कार्यों या अंतिम उपयोगों में कुछ अंतर है। यह भी तर्क दिया गया है कि प्राधिकारी को यह भी नोट करना चाहिए कि बताए गए बाजार समूहों में अंतर है। तथापि यह प्रदर्शित करने के लिए प्राधिकारी के समक्ष कोई वास्तविक तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि संबद्ध देशों में नियतित और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं हैं।

10. जैसाकि प्रारंभिक जांच परिणामों में नोट किया गया है आल इण्डिया यार्न इम्पोर्टर्स एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ इण्डियन आर्ट सिल्क एण्ड वीविंग इण्डस्ट्री ने तर्क किदया है कि याचिकाकर्ताओं ने घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित इसी नाम, गुणवत्ता तथा किस्म के किसी यार्न को बाहर नहीं रखा है। यह भी तर्क किदया गया है कि आंकड़ों का कोई सार्थक पृथकरण नहीं किया गया है। यार्न की काफी किस्मों जैसे 4.5 डेनियर से 3 अधिक उच्च दृढ़ता वाले पॉलिएस्टर, पालिएस्टर अग्नि रोधी यार्न, टेफलान ट्रिटेड पालिएस्टर यार्न, का आयात किया जाता है। जिनका भारत में विनिर्माण नहीं किया जाता है। इन एसोसिएशनों ने यह भी तर्क किदया कि आवेदकों ने विभिन्न प्रवृत्तियों और उनसे संबद्ध लागत प्रभावित के बीच अंतर नहीं किया गया है क्योंकि इस उत्पाद का उत्पादन पीटीए एम.ई.जी. चिप्स, पी ओ वाई/ एल ओ वाई स्तरों से शुरू हो सकता है और भिन्न-भिन्न तरीकों के लिए लागत संरचना अलग-अलग होगी। यह भी तर्क किदया गया है कि गुणवत्ता और प्रौद्योगिकी संबंधी पहलुओं पर ध्यान दिए बिना तथा आयात और घरेलू उत्पादन के आंकड़ों को अलग-अलग किए बिना संबद्ध वस्तुओं की तुलना से अत्यधिक विसंगति वाले परिणाम प्राप्त होंगे। तथापि इन तर्कों के समर्थन में इन एसोसिएशनों ने कोई आंकड़े या प्रश्नवली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि लागत इन कीमतों के लाभ जांच तथा निर्धारण के विषय और इनकी समान वस्तु के निर्धारण में कोई भूमिका नहीं है।

11. जहां तक घरेलू उद्योग के निर्धारण तथा क्षति निर्धारण के प्रयोजनार्थ समान वस्तु के निर्धारण के मुद्दे का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के विनिमणि का प्रारंभिक बिन्दु मूलभूत पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया है जिसमें पीटीए या टीपीए और एमईजी या ईजी शामिल है। कुछेक उत्पादन इकाईयां संबद्ध वस्तु के उत्पादन हेतु मूलभूत पॉलीमराइजेशन स्तर या बाई पालिस्टर चिप्स से शुरू करती है जिसमें स्पिनिंग और ड्राईंग प्रक्रिया का प्रयोग होता है। विनिमणि की प्रक्रिया कॉफी मानकीकृत है और गुणवत्ता और ग्रेडों में बदलाव स्पिनिंग और ड्राईंग मानदण्डों में परिवर्तन या उन्हें नियंत्रित करके किया जाता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में घरेलू उद्योग समान उत्पादन प्रक्रिया का प्रयोग करता है और घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित वस्तुओं तथा संबद्ध देशों से नियतित वस्तुओं में समान भौतिक तथा रासायनिक विशेषताएं हैं पारित वस्तुओं और घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद के बीच कोई खास अंतर नहीं है। प्रयोक्ता उद्योग द्वारा आयातित वस्तुओं और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। चूंकि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं और वाजिणिज्यक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। इसलिए ये पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत समान वस्तुएं हैं। अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि इस जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद में पालिस्टर सभी फुल्ली ड्रान यार्न और टैक्सचर्ड और गैर-पीओवाई शामिल है और भारत में आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देशों से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु है।

ग. घरेलू उद्योग

12. यह आवेदन मै. एसोसिएशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली द्वारा भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित उत्पादकों के साथ प्रस्तुत किया गया है:-

- (i) मै. सेंट्रल इण्डिया पॉलिस्टर लि., नागपुर, महाराष्ट्र
- (ii) मै. सैचुरी इका लि. रायगढ़, महाराष्ट्र
- (iii) मै. गार्डन सिल्क मिल्स लि. सूरत गुजरात

(IV) मै. नोवा पेट्रोकेमिकल्स लि. अहमदाबाद, गुजरात

(V) मै. रेक्रोन सिंथेटिक्स लि. इलाहाबाद, उ.प्र.

(VI) मै.वेल्लस्पन सिंटेक्स लि. थाणे, महाराष्ट्र

13. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध वस्तु के तीन अन्य ज्ञात घरेलू उत्पादक हैं। तथापि पूर्वोक्त उत्पादकों समग्र उत्पादन का घरेलू समान वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। तदनुसार प्रारंभिक जांच परिणामों में प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया था कि कि पूर्वोक्त आवेदक नियम 5 (3) (क) के अनुसार घरेलू उद्योग को पूरा करते हैं और संबंधित नियमों के नियम 2(ख) के अर्थों के भतीर घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तथापि हितबद्ध पक्षकारों ने अपने अनुरोधों में यह तर्क दिए हैं कि प्राधिकारी को पहले ये निर्णय लेना चाहिए कि क्या वे उन उत्पादकों जो आयात भी करते हैं को घरेलू उद्योग के दायरे में शामिल या उससे बाहर रखेंगे। केवल तभी आवेदकों की घरेलू उद्योग संबंधी योग्यता का निर्धारण किया जा सकता है। यह भी तर्क दिया गया है कि सार्वजनिक फाइल में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे यह प्रदर्शित होता हो कि प्रक्रिया पूरी की गई है यद्यपि भारत में संबद्ध वस्तु के अन्य उत्पादक हैं। यह भी ज्ञात नहीं है कि क्या प्राधिकारी ने कैप्टिव खपत या आवेदकों के साथ संबद्ध संग्रह कंपनियों द्वारा आयातों के मुद्दों पर ध्यान दिया है।
14. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि हितबद्ध पक्षकारों के लिए किसी भी समय कोई भी मुद्दा उठाने का विकल्प खुला नहीं है। हितबद्ध पक्षकार जांच शुरुआत से संबंधित मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां उसी स्तर पर दे सकते हैं जो समय सीमा जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना में दी गई हो। कुछ माह बाद जांच शुरुआत के संबंध में प्राधिकारी के आकलन पर टिप्पणियां करके हितबद्ध पक्षकारों ने केवल जांच में बाधा डालने का प्रयास किया है।
15. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत इस आवेदन को प्रस्तुत करने वाले घरेलू उत्पादकों की पात्रता विस्तृत जांच के बाद और उनके समग्र

उत्पादन, संबंधों की स्थिति और उनमें से एक आवेदक द्वारा किए गए आयातों की मात्रा को ध्यान में रखते हुए की गई थी। हितबद्ध पक्षकारों ने आवेदकों की पात्रता के बारे में उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों के संबंध में प्राधिकारी के समक्ष कोई वास्तविक तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक नियमावली के अंतर्गत यथा निर्धारित पात्रता संबंधी मानदण्डों को पूरा करते हैं और पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अनुसार इस जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग हैं।

घ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दे।

घ.1 आयातक

16. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के किसी आयातक ने प्रश्नावली का कोई उत्तर नहीं दिया है। ऑल इण्डिया यार्न इंपोर्टर्स एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ इण्डियन आर्ट सिल्क एण्ड वीविंग इण्डस्ट्रीज ने कुछेक अनुरोध। अनुरोध किए हैं, जिनमें किए गए दावों को सही साबित करने संबंधी तथ्य उन्होंने नहीं दिए हैं। इन पक्षकारों से उनके इस दावे को साबित करने के लिए कहा गया था कि वे सदस्यों की सूची तथा साक्ष्य प्रस्तुत करें कि इस एसोसिएशन के अधिकांश सदस्य संबद्ध वस्तु के आयातक हैं और नियम 2 (ग) के अर्थ के भीतर आयातक एसोसिएशन एक हितबद्ध पक्षकार है। तथापि ये एसोसिएशन कोई उत्तर देने में विफल रही थीं। अतः इस जांच के प्रयोजनार्थ सभी आयातकों और उनकी एसोसिएशनों को असहयोगी माना गया है। इसके होते हुए भी प्रारंभिक जांच परिणामों में उनके विचारों को रिकार्ड में लिया गया था और संगत सीमा तक उनका समाधान किया गया था। इन पक्षकारों ने आवश्यक रूप से यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामग्री और संबद्ध देशों के नियतिको की सामग्री के ग्रेडो जिनका भारत में उत्पादन नहीं किया जाता है, को जांच से बाहर रखा जाना चाहिए। प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पादक और समान वस्तु के निर्धारण के लिए इस मुद्दे की जांच की है और यह मानते हैं कि संबद्ध देशों से नियतित वस्तुएं और घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित वस्तुएं इन उत्पादकों की तकनीकी और वाणिज्यिक प्रति स्थापनीयता को ध्यान में रखते हुए समान वस्तुएं हैं।

घ.2 निर्यातक

17. इस जांच में भाग ले रहे संबद्ध देशों के निर्यातकों ने अपने प्रारंभिक जांच परिणाम पश्चात के अभ्यावेदनों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मुद्दे उठाए हैं :-

18. कोरिया के निर्यातकों ने तर्क दिया है कि प्राधिकारी ने जांच पूरी करने के लिए 12 महीनों की अवधि से आगे समय-विस्तार को अधिसूचित नहीं किया है और ऐसी किसी अधिकारिक सूचना के बिना कानूनी रूप से जांच 26 जून, 2006 को समाप्त हो चुकी है क्योंकि अधिकारिक नोटिस के बिना कानूनन जांच नहीं हो सकती है।

19. विनिर्दिष्ट प्राधिकारी बनाम हाल्डर टॉपसो 2000 (120) ई.एल.टी. 11, (एस.सी.) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को उद्धृत करते हुए घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि कानून के तहत ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि प्राधिकारी द्वारा जांच की समयावधि के विस्तार का नोटिस दिया जाना अपेक्षित है।

20. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 17 में यह प्रावधान है कि प्राधिकारी जांच प्रारंभ करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर निर्धारित करेंगे कि क्या जांचाधीन वस्तु का भारत में पाटन किया जा रहा है अथवा नहीं और केन्द्र सरकार को अपने अंतिम जांच परिणाम प्रस्तुत करेंगे। उक्त नियम में यह भी प्रावधान है कि विशेष परिस्थितियों में केन्द्र सरकार स्वविवेक से पूर्वोक्त एक वर्ष की अवधि को छह महीने और बढ़ा सकती है। जैसा कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा तर्क दिया गया है, न तो नियम और न ही करार में किसी हितबद्ध पक्षकार को ऐसे विस्तार का नोटिस देने की परिकल्पना की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह मत है कि मामले की अपेक्षाओं के आधार पर प्रश्नगत निर्णय एक प्रशासनिक निर्णय है। अतः इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्क वैध नहीं हैं।

21. निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी तर्क दिया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई अगोपनीय सूचना पूर्णतः अपर्याप्त और गलत है तथा प्रस्तुत की गई सूचना भारतीय कानून की अपेक्षाओं के सुसंगत नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि पाटन के अपने आरोप के लिए अनुमानों के आधार पर आवेदकों ने संबद्ध देशों में परिकलित सामान्य मूल्य पर विश्वास किया है परन्तु इन अनुमानों, जो पारिभाषिक रूप से आवेदक का स्वामित्व या उसके व्यवसाय के लिए संवेदनशील नहीं हो सकते हैं, को प्रकट नहीं किया है। इसी प्रकार, प्रतिकूल मात्रात्मक प्रभाव को दर्शाने के लिए विश्वास किए गए व्यापार आंकड़े अविश्वसनीय प्रतीत होते हैं। निर्यातकों ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक को प्रदान की गई गोपनीयता अवांछित है क्योंकि आवेदकों ने ऐसी सूचना को गुप्त रखा है जिसे अन्यथा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना चाहिए था और आवेदक ने प्रत्येक उत्पादक के लिए सूचीबद्ध रूप से अपनी लागत सूचना प्रस्तुत नहीं की है।

22. अपने विभिन्न अभ्यावेदनों में घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा सूचना के समय पर प्रस्तुतीकरण के मुद्दे को उठाया है। उन्होंने तर्क दिया है कि इन निर्यातकों ने जांच प्रारंभ करने से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर आपत्ति नहीं की है और इसलिए इन मुद्दों पर अनुवर्ती आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि इन निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर अपूर्ण थे और उनके द्वारा अनुवर्ती प्रस्तुतीकरण बहुत विलंब से अर्थात् प्रारंभिक जांच परिणामों की समाप्ति के निकट प्रस्तुत किए गए थे। घरेलू उद्योग ने उत्तरदाता निर्यातकों द्वारा अपर्याप्त अगोपनीय प्रकटीकरणों के बारे में भी कई मुद्दे उठाए हैं।

23. प्राधिकारी ने जांच शुरुआत तथा गोपनीयता से संबंधित मुद्दों पर नियंत्रकों, आयातकों, चरलू डेवेलप तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों की जांच की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी जांच एक सतत प्रक्रिया है और जांच प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होने वाली सूचनाओं के आधार पर प्राधिकारी को निर्धारण करना होता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि ग्वाटेमाला-मैक्सिको-सीमेंट मामले में पैनल ने निर्णय लिया कि यह साक्ष्य की पर्याप्तता, न कि उसकी उपयुक्तता और यथातथ्यता है जो किसी जांच की शुरुआत किए जाने अथवा न किए जाने के निर्धारण के मामले में लागू होने वाले विधिक मानकों को बसाती है। उक्त विवाद में पैनल ने निर्णय लिया कि पाटनरोधी जांच एक प्रक्रिया है जिसमें किसी उपाय को अपनाने के लिए आवश्यक सभी संघटकों की उपस्थिति की निश्चितता की जांच के आगे बढ़ने की प्रक्रिया में धीरे-धीरे प्राप्त किया जाता है। तथापि, साक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि किसी गैर-पक्षधारी तथा संतुलित निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यह निर्धारित किया जा सके कि किसी जांच की शुरुआत को तर्कसंगत ठहराने के लिए अनुच्छेद 2 के अर्थ के भीतर पाटन के पर्याप्त साक्ष्य थे। वर्तमान मामले में आवेदकों द्वारा पाटन, क्षति तथा कारणात्मक संबंध की प्रथम दृष्ट्या उपस्थिति को दर्शाने वाले पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे। आवेदकों के पास उचित रूप से उपलब्ध एवं आवेदन में उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की उपयुक्तता एवं यथातथ्यता सहित मामले के विभिन्न पहलुओं की उचित जांच के बाद प्राधिकारी द्वारा जांच शुरु की गई थी। अतः, इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्क वैध नहीं हैं।

24. जहाँ तक गोपनीयता और जांच के पक्षकारों द्वारा सूचना के अपर्याप्त अगोपनीय प्रकट का संबंध है, उठाए गए मुद्दों की जांच की गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि समय तथा व्यवहार्य सीमा तक सूचना प्रस्तुत करने वाले विभिन्न पक्षकारों के गोपनीयता संबंधी दावों की जांच की गई है और पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की प्रकृति के आधार पर गोपनीयता संबंधी दावों की स्वीकार किया गया।

ड. पाटन तथा पाटन मार्जिन का निर्धारण

25. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस मामले में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित निर्यातकों ने प्रश्नावली के अपने उत्तर प्रस्तुत किए :-

1. मै. पी. टी. भूत गार्डिंग तकस्टिल (इंडोनेशिया)
2. मै. एच. के. कॉर्पोरेशन (कोरिया)
3. मै. ह्योसंग कॉर्पोरेशन (कोरिया)
4. मै. सेहान इंडस्ट्री (कोरिया)
5. मै. ह्योविस कॉर्पोरेशन (कोरिया)
6. मै. हालान कॉर्पोरेशन (मलेशिया)
7. मै. नान या प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन (चीनी ताइपेई)
8. मै. चाइना मेन-मेड फाइबर कॉर्पोरेशन (चीनी ताइपेई)

26. तथापि, प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए जाने के बाद मै. चाइना मेन-मेड फाइबर कॉर्पोरेशन, चीनी ताइपेई ने प्राधिकारी के किसी भी पत्रादि का उत्तर नहीं दिया है और अपने संस्थापन की पेशकश नहीं की। तदनुसार, इस जांच के प्रयोजनार्थ इस निर्यातक को असहयोगी माना गया है।

27. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि मै. एच. के. कॉर्पोरेशन, कोरिया गणराज्य ने स्वच्छिक कीमत वचनबद्धता की पेशकश की है और पाटनरोधी नियम के नियम 15 के अनुसार अपने विरुद्ध जांच को स्थगित करने का अनुरोध किया है। प्राधिकारी ने नियम के नियम 15 के अनुसार कीमत वचनबद्धता को स्वीकार

कर लिये है और उसी नियम 15(4) के अनुसार इसी जीव परिणाम के अनुबंध के रूप में अधिसूचित किया गया है।

28. इस जांच में अन्य सहयोगी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का सत्यापन नियम के अनुसार किया गया और प्राधिकारी द्वारा इस सत्यापन की रिपोर्टों को टिप्पणी हेतु निर्यातकों को उपलब्ध कराया गया था। सत्यापन रिपोर्टों पर निर्यातकों की टिप्पणियों पर उनकी संगतता एवं वैधता की सीमा तक विचार किया गया है।

29. अपने प्रारंभिक जांच प्रणिमापश्चात् की अभ्यावेदनों में घरेलू उद्योग ने सहयोगी निर्यातकों की निर्यात कीमत को मुद्रा को उठाया है और यह निवेदन किया गया है कि इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि क्या वस्तु का क्रय कसोवाले संबंधित उत्पादक के कारण उचित बैंकिंग चैनल से आय प्राप्त की गई है, और निर्यातकों द्वारा प्राप्त करने का वादा की गई आय पर प्राधिकारी को विचार नहीं करना चाहिए। यह स्पष्ट दिया गया है कि निर्यात कीमत के परिकलन के प्रयोजनार्थ टीटी सौदों के जरिए प्राप्त कुछेक निर्यातकों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए और निर्यात कीमत के निर्धारण के प्रयोजनार्थ भारत के सीमांत प्राधिकारियों को समक्ष प्रकट की गई निर्यात कीमत पर विचार किया जाना चाहिए। अपने प्रकटन पश्चात् अभ्यावेदनों में घरेलू उद्योग ने इस संबंध में अवसरों को दोहराया है।

30. अपने अभ्यावेदनों में निर्यातकों ने अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया है कि पाटनरोधी अधिनियम की सीमांत अधिकार का विकल्प अर्थात् सीमांत अधिकार को लागू करने का समर्थन नहीं है और आयतकों द्वारा किए गए राजस्व प्रवचन यदि कोई हो, के लिए निर्यात कीमत के परिकलन हेतु उचित प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यह तर्क दिया गया है कि पाटनरोधी अधिनियम या नियमों में निर्यात कीमत के सम्पादन अथवा नियम के अनुसार को छोड़कर संबंधित सौदों के संबंध में निर्यातकों द्वारा प्राप्त आय को छोड़कर संबंधित सौदों के संबंध में निर्यातकों द्वारा प्राप्त आय के किसी हिस्से को छेड़कर प्रावधान नहीं है। न तो पाटनरोधी अधिनियम और न ही नियम में यह परिकल्पना की गई है कि निर्यात सौदों के लिए केवल एक ही भुगतान प्राप्त किया जाएगा। यह भी तर्क दिया गया है कि यदि पाटनरोधी अधिनियम के अनुच्छेद 23 के तहत निर्यात कीमत को परिकलन किया ही जाना है तो यह निर्यात कीमत जाना चाहिए कि निर्यात और आयतक या किसी तीसरे पक्ष के बीच किसी प्रकार के संबंध अथवा प्रतिपूर्ति व्यवस्था है और ऐसी स्थिति में निर्यात कीमत का परिकलन उस कीमत के अतिरिक्त किया जाना चाहिए जिस पर स्वतंत्र क्रय वस्तु की प्रथम पुनर्विक्री की गई है। अतः घरेलू उद्योगों के समक्ष आलोक में निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए किसी अन्य कीमत या प्रक्रिया को अपमानजनक और स्थिति अधिनियम के अनुच्छेद 9(क)(ख) के विपरीत होना। अतः ऐसे सभी भुगतानों में निर्यातकों द्वारा प्राधिकार को संतुष्ट कर सकता है कि वे सुने किसी निर्यात सौदे के संबंध में प्राधिकार को की संबंधित सौदे के लिए उसकी निर्यात कीमत के निर्धारण में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। अतः निर्यातकों ने यह तर्क दिया गया है कि किसी पाटनरोधी जांच में आयतकों द्वारा असहयोग को नहीं अनुमानित किया जाना चाहिए कि बीजकों में कम या अधिक भुगतान दिखाया गया है कि असहयोगिता द्वारा असहयोग, जिस पर निर्यातक का कोई नियंत्रण नहीं है, के लिए प्राधिकारी निर्यातक द्वारा प्रस्तुत निर्यात कीमत को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। यदि निर्यातक द्वारा प्रस्तुत की गई निर्यात कीमत को अस्वीकार करने के लिए किसी जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा आयतकों के सहयोग पर निर्भर प्रक्रिया को प्रस्तुत किया गया है तो निर्यातक पर अनुचित भार पड़ेगा। निर्यातक तथा आयतक के एक दूसरे से संबंधित होने की स्थिति को छोड़कर किसी भी पाटनरोधी जांच में ऐसा कोई प्रस्ताव अनुसृत नहीं है। अतः निर्यातकों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योगों का दावा अतर्क संगत और अस्वीकार किए जाने योग्य है।

31. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों में निर्यातकों द्वारा वस्तुओं का सीधे तथा विभिन्न देशों में असंबद्ध व्यापारियों के जरिए निर्यात किया जाता है। वस्तुएं भारत को सीधे भेजी जाती हैं और उन्हें ऑर्डर देने वाले व्यापारियों के नाम दर्ज किया जाता है। भुगतान भी इन्हीं व्यापारियों से प्राप्त किया जाता है। निर्यातक सीधे भारत को वस्तु भेजते हैं और सभी शिपिंग दस्तावेज निर्यातक द्वारा तैयार किए जाते हैं। तथापि, उत्पादक/निर्यातकों को व्यापारियों एवं वास्तविक आयातकों के बीच सौदे की जानकारी प्रतीत नहीं होती है। निर्यातकों ने तर्क दिया है कि इस संबंध में अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे कई न्यायाधिकरणों में पूर्व निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार भारत को वास्तव में भेजी गई वस्तु के लिए व्यापारियों को उनकी कीमत ही उनकी निर्यात कीमत है। यह तर्क दिया गया है कि जांचकर्ता देश को पुनर्निर्यात करने वाले किसी व्यापारी को उत्पादक/निर्यातकों की सत्यापित कीमत को, यदि ऐसे व्यापारी ने सहयोग न किया हो तो भी संबंधित उत्पादक/निर्यातकों की निर्यात कीमत माना जाएगा बशर्ते संबंधित कंपनी इस बात के लिए प्राधिकारी को संतुष्ट कर सके कि संबंधित सौदे के लिए वस्तु का जांचकर्ता देश को वास्तव में निर्यात किया गया था। ऐसी स्थिति में व्यापारी को असहयोग के प्रतिकूल परिणामों का सामना करना ही पड़ेगा। यह निवेदन किया गया है कि ईयू विनियम के अनुसार निर्यात कीमत को "निर्यातक देश से समुदाय को निर्यातों के लिए बिक्री किए जाने के समय उत्पाद के लिए वास्तव में भुगतान की गई अथवा भुगतान योग्य कीमत" के रूप में परिभाषित किया गया है। इन देशों में विकसित एक लागू किए गए विधिशस्त्र में स्थानीय व्यापार कंपनी से उत्पादक द्वारा वसूल की गई प्रथम कीमत के निम्न कीमत के रूप में प्रयोग की अनुमति दी गई है यदि उत्पादक को खेप के अंतिम गंतव्य स्थल की जानकारी हो क्योंकि उत्पादक की वह कीमत आयातक देश को निर्यात के निमित्त थी। यह भी तर्क दिया गया है कि इन विधिशस्त्रों की पद्धतियों में निर्यातक देश के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा ऐसे सभी सौदों, जिनके लिए उन्हें इन देशों को निर्यात किए जाने की जानकारी है, को सूचित करना अपेक्षित है। अतः यह तर्क दिया गया है कि व्यापारियों के जरिए उनकी सीधी तथा अप्रत्यक्ष बिक्रियों के संबंध में निर्यातकों द्वारा रिपोर्ट की गई सौदा कीमतों को निर्यात कीमतों के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। तथापि, असंबद्ध व्यापारियों को अपने असहयोग के कारण प्रतिकूल हस्तक्षेप का सामना करना होगा क्योंकि उनके माध्यम से किए गए सौदों के संबंध में उत्तर प्रस्तुत करने के लिए उत्पादकों/निर्यातकों का उन पर कोई नियंत्रण नहीं है।

32. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की प्रकटन पद्धति टिप्पणियों सहित विभिन्न अभ्यावेदनों में उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच की है। जहाँ तक निर्यातों के सौदा मूल्य और भुगतान की पद्धति के मुद्दे का संबंध है, न तो पाटनरोधी अधिनियम और न ही भारतीय पाटनरोधी नियम में इस समस्या के समाधान के लिए कोई प्रावधान है। निर्यात कीमत के परिकलन का सहारा लेने हेतु यह सिद्ध करने के लिए रिकॉर्ड में कोई साक्ष्य नहीं है कि इस मामले में शामिल उत्पादक/निर्यातक तथा व्यापारी/आयातक एक दूसरे से संबंधित हैं और उनके बीच कोई प्रतिपूर्ति व्यवस्था है। अधिनियम के अनुच्छेद 9क(ख) के अनुसार यदि परिकलन का सहारा लेना भी पड़े तो उसे आयातक देश के बाजार में प्रथम पुनर्बिक्री कीमत पर आधारित करना होगा जिसके लिए किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः प्राधिकारी ने उत्पादकों/निर्यातकों के रिकॉर्डों के अनुसार उनके द्वारा वास्तव में प्राप्त की गई कीमत के आधार पर निर्यात कीमत का निर्धारण किया है।

33. व्यापारियों को बिक्री कीमत और निर्यात कीमत के निर्धारण के मुद्दे के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रमुख उपयोक्ताओं द्वारा विकसित एवं अनुपालन किए जा रहे न्यायाधिकरण में निर्यातकों द्वारा सभी सौदों को रिपोर्ट किए जाने की स्पष्ट अपेक्षा की गई है और इस आंकड़े के आधार पर निर्यातक/उत्पादक के लिए निर्यातक कीमत का निर्धारण किया जाता है तथा असहयोगी व्यापारी को प्रतिकूल साक्ष्य परिणाम का सामना करना पड़ता है। तथापि, निर्यातकों के सौदे-द्वारा आंकड़ों की जांच से किसी निश्चित पैटर्न के बिना प्रत्यक्ष कीमतों और व्यापारियों के जरिए बिक्रियों के बीच कीमत संरचना में अत्यधिक अंतर प्रदर्शित होता है।

इसलिए, प्रत्येक निर्यातक की निर्यात कीमतों के निर्धारण के लिए सभी निर्यात बिक्रियों पर विचार किया गया है।

ड.2. निर्धारण की प्रणाली

34. प्राधिकारी नोट करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. बनाम विनिर्दिष्ट प्राधिकारी व अन्य की वर्ष 2001 की सिविल अपील सं. 1294 में यह निर्णय लिया है कि सामान्य मूल्य निर्यातक विशिष्ट नहीं बल्कि निर्यातक देश विशिष्ट होता है।

35. अपने प्रकटन पश्चात अभ्यावेदनों में घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि प्राधिकारी ने रिलायंस उद्योग लि. के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की गलत व्याख्या के आधार पर एकल देश विशिष्ट सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। यह तर्क दिया गया है कि हाल्डर- टॉपसो मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अपने लिए अलग सामान्य मूल्य के निर्धारण की मांग करने वाले निर्यातक के असहयोग पर आधारित था और वर्तमान मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने रिलायंस मामले के अनुपात का पूर्णतः गलत अर्थ निकाला है। यह तर्क दिया गया है कि आरआईएल मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने असहयोग के उदाहरण के लिए हाल्डर- टॉपसो मामले के अनुपात का केवल दोहराया है। अतः, आरआईएल निर्णय के पठन से यह संकेत मिलेगा कि उन मामलों को छोड़कर जहाँ निर्यातक ने सहयोग किया है और प्राधिकारी को पूर्ण सूचना उपलब्ध कराई है, सामान्य मूल्य देश विशिष्ट होता है। कोरिया गणराज्य के निर्यातकों ने भी यह तर्क दिया है कि निर्यातक देश के लिए एक ही सामान्य मूल्य का निर्धारण किए जाने की कोई प्रथा नहीं है और ऐसे परिकलन का अर्थ निर्यातक देश को बाजार पहुँच प्रदान करने से इनकार करना होगा जिसके गंभीर परिणाम होंगे।

36. तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर उद्धृत निर्णय में ऐसी परिस्थितियों को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है जिनमें जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा तर्क दिया गया है, ऐसे निर्धारण किए जा सकते हैं। प्राधिकारी ने इस निर्णय के स्पष्टीकरण एवं संशोधन की मांग करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष एक समीक्षा आवेदन भी प्रस्तुत किया है। तथापि, समीक्षा आवेदन को माननीय न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। अतः प्राधिकारी का यह मत है कि माननीय न्यायालय के इस निर्णय से स्पष्ट रूप से प्राधिकारी पर एकल देश- विशिष्ट सामान्य मूल्य का निर्धारण करने का दायित्व आ गया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने एकल देश विशिष्ट भारत औसत सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।

37. पहले व्यक्तिगत सहयोगी निर्यातकों के लिए व्यक्तिगत उत्पाद किस्मों (पीसीएन) के सामान्य मूल्यों का निर्धारण और फिर सहयोगी निर्यातकों के लिए निर्धारित सामान्य मूल्यों के आधार पर समग्र रूप से निर्यातक देश के लिए पीसीएन स्तर पर विवासाधीन उत्पाद की प्रत्येक उत्पाद किस्मों के लिए एक ही भारत औसत सामान्य मूल्य का परिकलन किया गया है। निर्यातकों के पीसीएन स्तर पर व्यक्तिगत पाटन मार्जिनों का निर्धारण करने के लिए उन्हीं पीसीएन स्तरों पर इन देश विशिष्ट सामान्य मूल्यों की तुलना व्यक्तिगत निर्यातकों के अपने पीसीएन के लिए निर्यात कीमत सं की गई है। प्रत्येक निर्यातक हेतु पीसीएन स्तर पर पाटन मार्जिनों के आधार पर उस निर्यातक के लिए भारत औसत पाटन मार्जिन का परिकलन किया गया है।

38. प्रासंगिक वेंचरों की अंतर्देशीय निर्यातकों के उपरान्त मार्जिन के तर्जुनीकरण के तत्परता को अंतर्देशीय निर्यातों हेतु उत्पाद के प्रकार-वार निर्यात कीमत के अभाव में सहयोगी निर्यातकों के भारत औसत है। प्रासंगिक मूल्य की तुलना सहयोगी निर्यातकों की न्यूनतम निर्यात कीमत से की गई है।

निर्माण कि निर्माण 5.8

3.1 इंडोनेशिया

39. प्राथमिक जांच परिणाम अधिसूचना के उत्तर में इंडोनेशिया में संबद्ध वस्तुओं के केवल एक निर्माता की पहचान की गई है। निर्माण कि निर्माण 5.8

40. प्राथमिक जांच परिणाम अधिसूचना के उत्तर में इंडोनेशिया में संबद्ध वस्तुओं के केवल एक निर्माता की पहचान की गई है। निर्माण कि निर्माण 5.8

(ख) निर्यात कीमत एवं पाटन मार्जिन

41. प्राथमिक जांच परिणाम अधिसूचना के उत्तर में इंडोनेशिया में संबद्ध वस्तुओं के केवल एक निर्माता की पहचान की गई है। निर्माण कि निर्माण 5.8

दौरान भारत को केवल कुछेक पी सी एन का निर्यात किया है। अतः समान वस्तुओं की तुलना के प्रयोजनार्थ घरेलू बाजार में बेचे जाने वाले उक्त पी सी एन पर विचार किया गया है। कंपनी की अधिकांश घरेलू बिक्रियां कारखाना द्वार आधार पर की गई है अतः निर्यातक ने जहां प्रयोज्य हो वहां केवल घरेलू सौदों पर ऋण व्यय, बैंक प्रभार तथा पैकिंग लागत एवं अंतर्देशीय भाड़ा व्यय पर समायोजनों का दावा किया है तथा कुछेक सौदों पर वारंटी दावों पर व्यय में समायोजन का दावा किया है। उपर्युक्त रीति से अभिज्ञात घरेलू बिक्री सौदों की उनके अलग-अलग सत्यापित उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य क्रम में व्यापार जांच की गई है तथा घरेलू बिक्री कीमतों के आधार पर अलग-अलग पी सी एनो के सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है।

(ii) मै0 सेहान इंडस्ट्री, कोरिया गणराज्य

49. कंपनी ने जांच अवधि के दौरान अपने घरेलू बाजार में संबद्ध उत्पाद के **** मी.टन की बिक्री की है जिसमें पी सी एनो की एक बड़ी संख्या शामिल है। तथापि, कंपनी ने जांच अवधि के दौरान भारत को केवल कुछेक उत्पाद कोडों के अंतर्गत आने वाले एफ डी वाई का निर्यात किया है। अतः समान वस्तुओं की तुलना के प्रयोजनार्थ, घरेलू बाजार में बेचे जाने वाले उक्त पी सी एनो पर विचार किया गया है। घरेलू बिक्रियां एक संबद्ध ग्राहक मै0 टोरे सेहान को छोड़कर अंतिम प्रयोक्ताओं तथा व्यापारियों सहित असंबद्ध क्रेताओं को की गई है। तथापि, संबद्ध ग्राहकों को हुई बिक्री केवल *** मी.टन है, जिसका हिस्सा कुल घरेलू बिक्री मात्रा में नगण्य है।

50. घरेलू बिक्रियां अधिकतर सुपुर्दगी आधार पर की जाती हैं यद्यपि कुछेक सौदे कारखाना-द्वार आधार पर किए जाते हैं। भुगतान की वसूली स्थानीय एल सी के जरिए अथवा कंपनी द्वारा अपने नियमित ग्राहकों हेतु रखे गए मुक्त खाता प्रणाली के जरिए की गई है। कारखाना-द्वार स्तर पर सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु अंतर्देशीय भाड़े घरेलू सौदों पर ऋण व्ययों तथा पैकिंग लागतों में समायोजन करने की अनुमति दी गई है। उपर्युक्त रीति से अभिज्ञात घरेलू बिक्री सौदों की उनकी अलग-अलग सत्यापित उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य क्रम में व्यापार जांच की गई है तथा घरेलू बिक्री कीमतों के आधार पर अलग-अलग पी सी एनो के सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है।

(iii) मै0 हविस कॉर्पोरेशन, कोरिया गणराज्य

51. कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार तथा उनके द्वारा विभिन्न उपांगों में दी गई सूचना के अनुसार हविस ने अनेक पी सी एनो को शामिल करते हुए *** मी.टन की कुल मात्रा की संबद्ध वस्तुओं के *** घरेलू बिक्री सौदे किए हैं। तथापि जांच अवधि के दौरान केवल कुछेक पी सी एनो के अंतर्गत आने वाले एफ डी वाई का ही भारत को निर्यात किया गया है। अतः उचित तुलना के प्रयोजनार्थ सामान्य मूल्य का निर्धारण इन पी सी एनो के आधार पर किया जाना अपेक्षित है। निर्यातक ने अंतर्देशीय भाड़ा, घरेलू सौदों पर ऋण व्ययों, बैंक प्रभारों तथा पैकिंग लागतों हेतु समायोजनों का दावा किया है। चूंकि घरेलू एवं निर्यात पैकिंग में कोई अंतर नहीं है इसलिए कुल उत्पादन पर कुल पैकिंग व्यय दिया गया है, तथा औसत पैकिंग व्यय *** प्रति किग्रा. बनता है। उपर्युक्त पी सी एनो की घरेलू बिक्री पी सी एनो की अलग-अलग उत्पादन लागत के आधार पर व्यापार जांच की साधारण प्रक्रिया के अधीन है तथा अलग-अलग पी सी एनो के सामान्य मूल्यों का निर्धारण कारखाना द्वार स्तर पर किया गया है।

(iv) सामान्य मूल्य: कोरिया गणराज्य

52. जैसा कि उपर उद्धरित किया गया है, माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार, उपर निर्धारित अलग-अलग सामान्य मूल्यों के भारत औसत की तरह कोरिया के लिए समग्र रूप से एक सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है। पी सी एन स्तर पर सहयोगी निर्यातकों हेतु निर्धारित सामान्य मूल्यों के आधार पर पी सी एन स्तर पर कोरिया के सभी निर्यातकों हेतु भारत औसत सामान्य मूल्यों का निर्धारण किया गया है।

(ख) निर्यात कीमतें एवं पाटन मार्जिन:**(i) मै0 ह्योसंग कॉर्पोरेशन, कोरिया गणराज्य**

53. कंपनी ने जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं के *** मी.टन का निर्यात किया है। तथापि, उनके द्वारा केवल *** मी.टन ही भारत को प्रत्यक्षतः निर्यात किया गया था तथा शेष सौदे सिंगापुर, हांगकांग तथा कोरिया के व्यापारियों के जरिए किये गये थे। भारत को किए गए प्रत्यक्ष निर्यात तथा सिंगापुर एवं हांगकांग के व्यापारियों के जरिए किए गए निर्यात "साइट टर्म" पर एल सी में मौजूद हैं। ह्योसंग एवं कोरियाई व्यापारी के बीच सौदे टी टी आधार पर किए गए हैं। शामिल व्यापारियों ने उनके जरिए ह्योसंग द्वारा निर्यातित वस्तुओं के संबंध में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है और इसलिए इन सौदों हेतु उनकी वास्तविक निर्यात कीमतें ज्ञात नहीं हैं। तथापि ह्योसंग के लिए निर्यात कीमत के निर्धारण के प्रयोजनार्थ उनकी कीमतों पर विचार किया गया है और व्यापारियों को उपलब्ध प्रतिकूल तथ्यों तथा अवशिष्ट पाटन मार्जिन का सामना करना पड़ेगा।

54. अलग-अलग पी सी एन हेतु निवल कारखाना-द्वार निर्यात कीमतों का निर्धारण करने के लिए भारत को निर्यात सौदे, अंतर्देशीय तथा समुद्री भाड़े, ऋण संबंधी व्ययों, समुद्री बीमा भाड़े, हैंडलिंग शुल्क तथा बैंक व्ययों, निर्यात लदानों हेतु पैकिंग लागत तथा निर्यात सौदों पर वापसी में एफ ओ बी/सी आई एफ तथा सी एन एफ के संदर्भ में समायोजन किया गया है।

55. कोरिया गणराज्य के लिए उपर्युक्त कारखाना द्वार भारत औसत सामान्य मूल्यों तथा इस निर्यातक हेतु पी सी एन स्तरों पर निर्धारित निवल कारखाना द्वार निर्यात कीमतों के आधार पर इस निर्यातक हेतु पी सी एन स्तर पर पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है। तदनुसार, इस निर्यातक के लिए भारत औसत पाटन मार्जिन, **** अम.डा./किग्रा. (17.42 %) बनता है।

(ii) मै0 सेहान इंडस्ट्री, कोरिया गणराज्य

56. कंपनी ने जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं के *** मी.टन का निर्यात किया है। तथापि, उनके द्वारा केवल *** मी.टन ही भारत को प्रत्यक्षतः निर्यात किया गया था तथा शेष सौदे सिंगापुर, हांगकांग तथा कोरिया के व्यापारियों के जरिए किये गये थे। भारत को किए गए प्रत्यक्ष निर्यात तथा सिंगापुर एवं हांगकांग के व्यापारियों के जरिए किए गए निर्यात एल सी आधार पर किए गए हैं। सेहान तथा कोरियाई व्यापारी के बीच सौदे स्थानीय एल सी आधार पर

किए गए हैं। शामिल व्यापारियों ने उनके जरिए सेहान द्वारा निर्यातित वस्तुओं के संबंध में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है और इसलिए इन सौदों हेतु उनकी वास्तविक निर्यात कीमतें ज्ञात नहीं हैं। तथापि ह्यूयोसंग के लिए निर्यात कीमत के निर्धारण के प्रयोजनार्थ उनकी कीमतों पर विचार किया गया है और व्यापारियों को उपलब्ध प्रतिकूल तथ्यों तथा अवशिष्ट पाटन मार्जिन का सामना करना पड़ेगा।

57. भारत को निर्यात सौदे एफ ओ बी तथा सी आई एफ आधार पर किए गए हैं। निर्यातक ने कुछेक सौदों पर कमीशन का भी भुगतान किया है। तदनुसार यथा सत्यापित अंतर्देशीय एवं समुद्री भाड़े, बीमा व्ययों, हैंडलिंग शुल्क तथा बैंक व्यय संबंधी दस्तावेजों, निर्यात लदानों हेतु पैकिंग लागत, ऋण व्ययों तथा शुल्क वापसी में समायोजन हेतु अनुमति दी गई है। तदनुसार अलग-अलग पी सी एन हेतु औसत निवल कारखाना द्वार निर्यात कीमत निर्धारित की गई है।

58. कोरिया गणराज्य के लिए उपर्युक्त कारखाना द्वार भारत औसत सामान्य मूल्यों तथा इस निर्यातक हेतु पी सी एन स्तरों पर निर्धारित निवल कारखाना द्वार निर्यात कीमतों के आधार पर इस निर्यातक हेतु पी सी एन स्तर पर पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है। तदनुसार, इस निर्यातक के लिए भारत औसत पाटन मार्जिन ***** अम.डा./किग्रा. (4.2 %) बनता है।

(iii) मै0 हूविस कॉर्पोरेशन, कोरिया गणराज्य

59. कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार यह प्रदर्शित होता है कि उन्होंने जांच अवधि के दौरान ऊपर उल्लिखित पी सी एन को शामिल करते हुए भारत को संबद्ध वस्तुओं के *** मी.टन का निर्यात किया है। भारत को किए गए कुल निर्यातों में से भारत को *** मी.टन के प्रत्यक्ष निर्यात किए गए थे तथा ये निर्यात एल सी एट साइट आधार पर किए गए हैं। शेष निर्यात कोरिया और तीसरे देशों के व्यापारियों के जरिए किए गए हैं। इन सौदों हेतु उनके क्रेताओं/व्यापारियों के दिशा-निर्देशों के आधार पर उत्पादक/निर्यातक द्वारा वस्तुओं को सीधे जहाज द्वारा भेजा गया था जिसमें कोरियाई व्यापारी को छोड़कर, जिसको अनुमोदन आधार पर वस्तुओं की आपूर्ति की जाती है तथा भुगतान उनके मुक्त खातों से प्राप्त किए जाते हैं, भुगतान की प्राप्ति इन व्यापारियों से एल सी एट साइट आधार पर प्राप्त की गयी थी। शामिल व्यापारियों ने अपने माध्यम से हूविस द्वारा निर्यातित वस्तुओं के संबंध में कोई अन्य उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है और इसलिए, इन सौदों के लिए उनकी वास्तविक निर्यात कीमत ज्ञात नहीं है। तथापि, हूविस के लिए निर्यात कीमत के निर्धारण के प्रयोजनार्थ उनकी कीमतों पर विचार किया गया है तथा व्यापारियों को उपलब्ध प्रतिकूल तथ्यों एवं अवशिष्ट पाटन मार्जिन का सामना करना पड़ेगा।

60. कारखाना द्वार स्तर पर पी सी एन वार औसत निवल निर्यात बिक्री का निर्धारण करने के लिए इन निर्यातों हेतु निर्यातक द्वारा प्राप्त समुद्री भाड़े, अंतर्देशीय तथा समुद्री बीमा, पैकिंग व्ययों, हैंडलिंग एवं दस्तावेजीकरण प्रभार, बैंक प्रभार, ऋण संबंधी व्यय तथा शुल्क वापसी में समायोजनों पर विचार किया गया है।

कोरिया जन. गण. के लिए उपर्युक्त कारखाना द्वारा भारत औसत सामान्य मूल्य तथा इस निर्यातक के लिए पीसीएन स्तरों पर निर्धारित निवल कारखाना द्वारा निर्यात कीमत के आधार पर इस निर्यातक का पाटन मार्जिन पीसीएन स्तरों पर परिकलित किया गया है। तदनुसार, इस निर्यातक के लिए भारत औसत पाटन मार्जिन *****अम. डा./ कि.ग्रा. (0.7%) बनता है। इस निर्यातक का पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर पर पाया गया है।

सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन के निर्धारण का अलग से गोपनीय प्रकटन इस निर्यातक को उपलब्ध कराया गया है।

(iv) कोरिया जन. गण. से अन्य निर्यातक

61. संबद्ध देश के अन्य असहयोगी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण उनके द्वारा भारत को निर्यातित पीसीएनों के लिए सहयोगी निर्यातकों की न्यूनतम सौदा कीमत के आधार पर किया गया है।

62. असहयोगी निर्यातकों के लिए भारत औसत पाटन मार्जिन ज्ञात करने के लिए कोरिया के लिए निर्धारित भारत औसत सामान्य मूल्य की तुलना को संबद्ध देश से असहयोगी निर्यातकों के लिए निवल निर्यात कीमत से की गई थी, जो ***/कि.ग्रा. अम. डा. (73%) बनता है।

63. कोरिया के निर्यातकों ने अपनी पश्च प्रकटन संबंधी टिप्पणियों में यह तर्क दिया है कि एकल सामान्य मूल्य की कानूनी वैधता के प्रश्न के अलावा पीसीएन वार परिकलन ने भी ग्रेडों में अंतर तथा ऐसे ग्रेडों की लागत तथा कीमतों के कारण एकल सामान्य मूल्य को विकृत किया होगा। इस प्रक्रिया में कुछेक निर्यातकों के नियमित ग्रेड कुछ अन्य निर्यातकों के मूल्यवर्धित ग्रेडों के साथ मिल गए हैं जिससे सभी समग्र सामान्य मूल्य तथा पाटन मार्जिन भी विकृत हो गए हैं।

64. इस सम्बन्ध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीसीएन निर्मित किए गए थे तथा सभी निर्यातकों को काफी पहले अधिसूचित किए गए थे तथा इसी प्रारूप में आंकड़े प्राप्त किए गए थे। इसलिए, पीसीएन पर आधारित निर्धारण, कोरिया जन. गण. के निर्यातकों सहित, निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार विधिवत रूप से किए गए हैं। इन निर्यातकों को सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत का निर्धारण भी समूचे परिकलन पत्रकों के साथ सत्यापन रिपोर्ट के जरिए प्रकट किया गया था। निर्यातकों ने कुछेक विसंगतियां दर्शाई थीं तथा इनके निराकरण हेतु एक बैठक बुलाने का अनुरोध किया था। निर्यातकों को बैठक का अवसर दिया गया था तथा उन्होंने अपने वकील तथा चार्टर्ड एकाउंटेंटों के साथ इस अवसर का उपयोग किया था। निर्धारण तथा परिकलनों को प्रकटन विवरण में अंगीकृत करने से पूर्व इसकी विधि की जांच तथा इसका समाधान उनकी उपस्थिति में उनकी पूर्ण संतुष्टि के साथ किया गया था। इसलिए, उत्पाद कोड पृथक्करण पर आधारित सामान्य मूल्य तथा पाटन मार्जिन के निर्धारणों के संबंध में निर्यातकों के अतिरिक्त तर्कों को स्वीकार नहीं किया गया है।

इ.3. मलेशिया**(क) सामान्य मूल्य**

65. मलेशिया से केवल एक निर्यातक अर्थात् मै. हुआलून कार्पोरेशन ने इस जांच में सहयोग किया है तथा प्रश्नावली का एक विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया है। इस सहयोगी निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों की यथासंभव जांच की गई थी। मलेशिया में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य इस सहयोगी निर्यातक के सत्यापित आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

66. जांचाधीन अवधि के दौरान इस कंपनी की कुल घरेलू बिक्री केवल *** मी. टन थी जो विचाराधीन उत्पाद के लिए कंपनी की कुल बिक्री की तुलना में नगण्य थी। इसलिए घरेलू बिक्री सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचारणीय पर्याप्तता परीक्षण को पूरा नहीं करती है। सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए तीसरे देश को निर्यात कीमत के विचाराणार्थ निर्यातक के दावे की अन्य देशों को निर्यातों की मात्रा के आधार पर जांच की गई थी। यह पाया गया था कि तुर्की को हुए निर्यात अन्य तीसरे देशों को निर्यात के संबंध में सर्वोच्च थे। इसलिए तुर्की को निर्यातों के संबंध में निर्यात रॉदे सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ सत्यापित किए गए थे। यद्यपि भारत को निर्यातित अधिकांश पीसीएनों का तुर्की को भी निर्यात किया गया था इसलिए भारत को निर्यातित कतिपय पीसीएनों का जांच अवधि के दौरान तुर्की को निर्यात नहीं किया गया था। ऐसे पीसीएनों के लिए, कंपनी के अभिलेख के अनुसार संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत जमा उपयुक्त लाभ के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया था। संबद्ध वस्तुओं की निवल कारखाना द्वार कीमत पर पहुंचने के लिए कमीशन तथा छूट, अंतर्देशीय तथा समुद्री भाड़े, बीमा तथा प्रहस्तन प्रभारों के लिए समायोजन को लागू किया गया था। तीसरे देश को निर्यात बिक्री के सौदे संबंधित पीसीएनों के उत्पादन की लागत के आधार पर व्यापार परीक्षण के सामान्य दौर के अध्यधीन थे तथा पीसीएन स्तर पर सामान्य मूल्यों को परिकलित किया गया था। इस प्रकार परिकलित सामान्य मूल्य को संबद्ध देश के लिए सामान्य मूल्य के रूप में अंगीकृत किया गया है। तदनुसार, मलेशिया में सभी निर्यातकों के लिए निवल कारखाना द्वार भारत औसत सामान्य मूल्य परिकलित किया गया है।

(ख) निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन**(i) मै. हुआलून कार्पोरेशन**

67. इस निर्यातक ने अनेक पीसीएनों को शामिल करते हुए जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं के लगभग *** मी. टन का निर्यात किया है। इसमें से केवल *** मी. टन का भारत को सीधे निर्यात किया गया है तथा शेष निर्यात विभिन्न व्यापारियों के जरिए हुए थे। निर्यातकों ने तर्क दिया है कि प्राधिकारी सीधे निर्यातों के आधार पर अपनी निर्यात कीमत का निर्धारण कर सकते हैं क्योंकि व्यापारियों ने सहयोग नहीं किया है तथा वे हर स्थिति में असहयोग के प्रतिकूल परिणाम भुगतेंगे। तथापि, समग्र निर्यात आंकड़ों की जांच से पता चलता है कि व्यापारियों के जरिए बिक्रियों सहित निर्यातों की औसत बिक्री कीमतें सीधे बिक्री की तुलना में कम हैं। इसलिए, इस निर्यातक की निर्यात कीमत के निर्धारण के प्रयोजनार्थ भारत को की गई सभी बिक्रियों पर विचार करना उपयुक्त है। अंतर्देशीय एवं समुद्री भाड़े तथा बीमा, साख लागत, बट्टा तथा छूट, पैकिंग लागत हेतु समायोजन, निर्यातक के सत्यापित आंकड़ों पर आधारित अलग-

अलग पीसीएनों के लिए निवल कारखाना द्वार निर्यात कीमत पर पहुंचने के लिए किए गए हैं। तदनुसार, कारखाना द्वार निवल निर्यात कीमतों को परिकलित किया गया है।

68. उपर्युक्त कारखाना द्वार सामान्य मूल्य तथा निवल कारखाना द्वार निर्यात कीमतें जिन्हें पीसीएन स्तर पर निर्धारित किया गया है, के आधार पर इस निर्यातक के लिए भारित औसत पाटन मार्जिन *** अम. डा./कि.ग्रा. (12.38%) परिकलित होता है।

(ii) मलेशिया से अन्य निर्यातक

69. संबद्ध देश से अन्य असहयोगी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत को सहयोगी निर्यातकों की सबसे कम सौदा कीमतों के आधार पर तय किया गया है।

70. संबद्ध देश के लिए निर्धारित भारित औसत सामान्य मूल्य की असहयोगी निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन पर पहुंचने हेतु संबद्ध देश से असहयोगी निर्यातकों के लिए निर्धारित निवल निर्यात कीमतों से तुलना की गई जो *** अम. डा./कि.ग्रा. (44%) बनता है।

71. मै. हुआलून कार्पोरेशन ने अपने पश्च प्रकटन अनुरोधों में यह तर्क दिया है कि उत्पाद कोड- वार तथा न कि प्राधिकारी द्वारा निर्णीत पीसीएन के आधार पर उचित तुलना करनी चाहिए क्योंकि पीसीएन अनेक उत्पाद कोडों को कवर करता है जो लागत तथा कीमतों में भिन्न- भिन्न हैं। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस तथ्य के मद्देनजर कि बाजार में उत्पादों की बहुत व्यापक रेंज उपलब्ध है, पीसीएन तैयार किए गए थे तथा उचित तुलना के प्रयोजनार्थ सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किए गए थे तथा निर्यातकों ने इन पीसीएनों के आधार पर उनकी लागत तथा कीमत संबंधी सूचना उपलब्ध कराई है। इसलिए इन पीसीएनों के आधार पर भी तुलना की गई है जो उचित तुलना के प्रयोजनार्थ एक मानक पद्धति है।

ड.4. चीनी ताइपेई

72. चीनी ताइपेई में संबद्ध वस्तुओं के केवल दो निर्यातकों अर्थात् मै. नान या प्लास्टिक्स कार्पोरेशन तथा मै. चीन मैन-मेड फाइबर कार्पोरेशन, चीनी ताइपेई ने इस जांच के उत्तर में अपना प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत किया है। तथापि, मै. मैन-मेड फाइबर कार्पोरेशन ने प्रारंभिक सहयोग के पश्चात् जांच से स्वयं को पृथक् कर लिया है। इसलिए इस कंपनी को इस जांच के प्रयोजनार्थ एक असहयोगी निर्यातक माना गया है।

(क) सामान्य मूल्य

73. संबद्ध देश से सहयोगी निर्यातक अर्थात् मै. नान या प्लास्टिक्स कार्पोरेशन के अभिलेखानुसार उत्पादक ने अनेक प्रकार के विचाराधीन उत्पाद को शामिल करते हुए घरेलू बाजार में *** मी. टन वस्तुओं की बिक्री की। 650 मी. टन की बिक्रियों को छोड़कर जो इसकी संबद्ध कंपनी मै. फार्मोसा केमिकल फाइबर कार्पोरेशन को की गई थी, शेष बिक्रियां असंबंधित उपभोक्ताओं को की गई थीं। संबद्ध कंपनी को की गई

बिक्रियों का हिस्सा कुल बिक्री में ***% से थोड़ा ज्यादा बनता है तथा इसलिए यह सामान्य कीमत संरचना का प्रभावित नहीं करता। इसलिए समूचे घरेलू बिक्री सौदों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया गया है। यह भी नोट किया गया था कि कंपनी घरेलू बाजार में अनेक किस्म की एफडीवाई का उत्पादन तथा बिक्री करती है। तथापि, समान-समान तुलना के प्रयोजनार्थ भारत को निर्यातित केवल उन उत्पाद प्रकारों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया गया है।

74. वस्तुओं को घरेलू बाजार में सुपुर्दगी के आधार पर बेचा गया है तथा कंपनी ने अंतर्देशीय परिवहन, छूट तथा पैकिंग व्ययों के संबंध में प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी व्ययों के लिए समायोजनों का दावा किया है। घरेलू बिक्री सौदे उत्पादन की उनकी संबंधित लागत के आधार पर व्यापार परीक्षण के सामान्य दौर के अध्यधीन थे तथा उपर्युक्त आंकड़ों के आधार पर पीसीएन स्तर पर निवल कारखाना द्वारा सामान्य मूल्य का परिकलन किया गया है। सहयोगी निर्यातक के लिए पीसीएन स्तरों पर निर्धारित सामान्य मूल्य को संबद्ध देश के लिए सामान्य मूल्य के रूप में अंगीकार किया गया है।

(ख) निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन

(i) मै, नान या प्लास्टिक्स कार्पोरेशन

75. इस कंपनी ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के *** मी. टन का निर्यात किया। तथापि, समग्र निर्यात बिक्री सौदे हांगकांग/कोरिया तथा थाईलैण्ड में दो वितरकों के जरिए हुए थे। यह नोटिस किया गया था कि वस्तुओं को सीधे भारत को निर्यात किया गया था यद्यपि बीजक उस वितरक को भेजा गया था जिसने भुगतान प्राप्त किया था। तथापि, इन वितरकों ने जांच में सहयोग नहीं किया है न ही भारत को अपने वास्तविक निर्यात तथा अपने एसजीए व्यय, यदि कोई हो, के ब्यौरे प्रदान किए हैं। इसलिए इन व्यापारियों से भारत को निर्यात कीमत ज्ञात नहीं है। निर्यातक ने यह दलील दी है कि चूंकि वस्तुओं को उनके द्वारा भारत को सीधे भेजा गया है तथा ये निर्यात उनके द्वारा किए गए हैं तथा इन सौदों के लिए उनके द्वारा वसूल किया गया भुगतान उनकी निर्यात कीमत है। चूंकि व्यापारियों ने जांच में सहयोग नहीं किया है इसलिए प्राधिकारी को ऐसे व्यापारियों के लिए उनके सहयोग से पाटन मार्जिन का निर्धारण करने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु नान या के पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ समग्र सौदों पर किसी व्यापारी से उन्हें संबंधित किए बिना विचार किया जाना चाहिए। असहयोगी निर्यातक/व्यापारी के प्रतिकूल जांच परिणाम मिल सकते हैं तथा अवशिष्ट शुल्क प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं यदि नान या के उत्पाद को भारतीय बाजार में निर्यात करना जारी रखने की इच्छा रखते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं। नान या को असंबंधित व्यापारियों, जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है, के असहयोग के लिए दण्डित नहीं किया जाना चाहिए।

76. भारत को निर्यात सौदे, 5 सौदों जो सीआईएफ के रूप में हैं, को छोड़कर एफओबी रूप में है। कमीशन, अंतर्देशीय तथा समुद्री भाड़ा; साख व्यय; समुद्रपारीय बीमा व्यय; प्रहस्तन शुल्क तथा बैंक व्यय; पैकिंग लागत; सीमाशुल्क प्रशासनिक फीस, व्यापार संवर्धन फीस तथा सरकार को प्रदत्त पत्तन निर्माण फीस के लिए समायोजनों को कंपनी के अभिलेखों से सत्यापित किया गया तथा अलग-अलग पीसीएन के लिए निवल कारखाना द्वारा निर्यात कीमत पर पहुंचने के लिए लागू किया गया।

77. उपर्युक्त कारखाना द्वार सामान्य मूल्य तथा पीसीएन स्तर पर निर्धारित निवल कारखाना द्वार निर्यात कीमत के आधार पर इस निर्यातक के लिए भारित औसत पाटन मार्जिन *** अम. डा./कि.ग्रा. (2.89%) परिकलित किया गया है।

(ii) चीनी ताइपेई से अन्य निर्यातक

78. संबद्ध देश से अन्य असहयोगी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत को सहयोगी निर्यातकों की सबसे कम सौदा कीमतों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

79. असहयोगी निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन पर पहुंचने के लिए संबद्ध देश हेतु निर्धारित भारित औसत सामान्य मूल्य की संबद्ध देश से असहयोगी निर्यातकों के लिए निवल निर्यात कीमत से तुलना की गई है जो *** अम. डा./कि.ग्रा. (25%) परिकलित होता है।

80. निर्यातक ने अपने पञ्च प्रकटन संबंधी अनुरोधों में साधारण दौर संबंधी परीक्षण करने की विधि तथा कंपनी से सभी निर्यातों की समेकित सीआईएफ कीमत के प्रतिशत के रूप में पाटन मार्जिन की अभिव्यक्ति में कतिपय संशोधन करने का अनुरोध किया है तथापि, प्राधिकारी ने पाया कि इन दलीलों में कोई दम नहीं है तथा इसलिए इस संबंध में जांच परिणामों की पुष्टि होती है।

ड.5. पाटन मार्जिन का सारांश

81. उपर्युक्त निर्धारण के आधार पर संबद्ध देश में निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार परिकलित होता है :-

देश/राज्य क्षेत्र	निर्यातक/विनिर्माता	पाटन मार्जिन अम.डा./मी. टन	पाटन मार्जिन (%)
इंडोनेशिया	मै. पी. टी. मुतु गार्डिंग टेक्सटिल	*****	1.29%
इंडोनेशिया	सभी अन्य	*****	39%
कोरिया गणराज्य	मै. एच. के. कॉर्पोरेशन	कीमत वचनबद्धता	
कोरिया गणराज्य	मै. ह्यूसुंग कॉर्पोरेशन	*****	17.42%
कोरिया गणराज्य	मै. सेहान इंडस्ट्री	*****	4.2%
कोरिया गणराज्य	मै. हुवीस कॉर्पोरेशन	*****	0.7%
कोरिया गणराज्य	सभी अन्य	*****	73%
मलेशिया	मै. हुआलोन कॉर्पोरेशन	*****	12.38%
मलेशिया	सभी अन्य	*****	44%
चीनी ताइपेई	मै. नान या प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन	*****	2.89%
चीनी ताइपेई	सभी अन्य	*****	37%

च. क्षति तथा कारणात्मक संबंध की जांच

च.1. हितबद्ध पक्षकारों के विचार

82. कोरिया के निर्यातक ने अपने प्रारंभिक जांच परिणाम के बाद के अनुराधों में यह दलील दी है कि इण्डोनेशिया तथा मलेशिया की संबद्ध वस्तुएं भारत में विनिर्मित संबद्ध वस्तुओं के साथ सबसे कड़ी प्रतिस्पर्धा करती हैं जो इन देशों द्वारा भारत को निर्यातित पीसीएन की व्यापक रेंज से भी प्रतिदर्शित होता है। यह तर्क दिया गया है कि इसमें उल्लेखनीय अंतर है तथा सेवित बाजार खण्ड वास्तविक रूप से भिन्न हैं। यह तर्क भी दिया गया है कि प्रत्येक संबद्ध देश के लिए प्रतिस्पर्धा की मात्रा भिन्न-भिन्न है तथा इसीलिए प्रत्येक देश के लिए क्षति का निर्धारण पृथक्-पृथक् किया जा सकता है क्योंकि संचयित करने से इन देशों द्वारा हुई क्षति का प्रभाव नकारात्मक हो जाएगा जो कोरियाई निर्यातकों को अनुचित रूप से दण्डित करेगा तथा पाटन के मामले में इण्डोनेशियन तथा मलेशियन संबद्ध वस्तुओं की और नजदीक प्रतिस्पर्धा से भारतीय उत्पादकों की अपर्याप्त रूप से रक्षा करेगा। इसलिए, प्राधिकारी प्रत्येक संबद्ध देश के लिए पृथक्-पृथक् क्षति विश्लेषण कर सकते हैं।

83. कोरियाई-निर्यातकों ने भी तर्क दिया है कि डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़े गलत हैं जिससे यह पता चलता है कि कथित प्रतिकूल मात्रात्मक प्रभाव त्रुटिपूर्ण आंकड़ों पर आधारित हो सकता है। यह तर्क दिया गया है कि समूची विचारित क्षति अवधि के दौरान भारत में क्षमता, उत्पादन तथा उपयोग में समुचित वृद्धि हुई है तथा घरेलू बिक्री का कार्य निष्पादन आधार वर्ष की तुलना में काफी अच्छा रहा है। उत्पादकों द्वारा घरेलू बिक्री में मामूली गिरावट का कारण अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री में लगभग इतनी ही वृद्धि है जो उच्च घरेलू प्रतिस्पर्धा का संकेत है। आगे यह तर्क दिया गया है कि कीमत से संबंधित समस्याएं जांच अवधि के अद्वितीय नहीं हैं, वरन् पहले से ही हैं जब संबद्ध देशों से आयात कम थे। कीमतों में कुछेक मानदण्डों में जांच अवधि के दौरान सुधार हुआ जो आयातों में वृद्धि के बावजूद पाटन के विरुद्ध संकेत देता है। पहुंच कीमतों में आधार वर्ष से गिरावट भारतीय टैरिफ में गिरावट की तुलना में स्पष्ट रूप से कम है।

84. इंडोनेशिया एवं मलेशिया के निर्यातकों ने तर्क दिया है कि कीमत कटौती तथा कम कीमत पर बिक्री तथा संपूर्ण क्षति विश्लेषण तथा एनआईपी की जांच भी उत्पाद नियंत्रण संख्याओं के आधार पर की जानी है।

85. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि न केवल याचिकाकर्ता उत्पादक बल्कि सभी घरेलू उत्पादकों की जांच की जानी चाहिए। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि हरेक घरेलू उत्पादक समान स्थिति में नहीं हैं और सभी गैर-आवेदनकर्ता उत्पादकों की जांच की जानी आवश्यक नहीं है जब तक कि आवेदनकर्ता उत्पादक नियम 2(ख) में निहित घरेलू उद्योग की परिभाषा के अनुसार घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हों। इसके अलावा, यदि भिन्न स्थितियों वाले गौण उत्पादकों के कारण अधिकांश घरेलू उत्पादकों को संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है तो घरेलू उद्योग की परिभाषा व्यर्थ हो जाएगी।

86. कुछेक मानदंडों में घरेलू उद्योग के निष्पादन के विषय में घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि यह निश्चित किया जा चुका है कि यह आवश्यक नहीं है कि इनमें से कोई एक अथवा एक से अधिक कारकों

से कोई निर्यातात्मक दिशा निर्देश प्राप्त हो सके। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा एक या अधिक मानदण्ड के आधार पर क्षति संबंधी परिणाम रिकॉर्ड करना उचित माना जाएगा तथा उन पर यह बाध्यत नहीं होगी कि वे केवल तब ही क्षति की मौजूदगी रिकॉर्ड कर सकते हैं जब अधिकांश कारकों से क्षति प्रवर्धित होती हो। अतः यह तर्क दिया गया है कि इन कारकों के संबंध में निर्यातकों के विवरणों पर ध्यान दिया जाना अपेक्षित नहीं है।

घ.2. प्राधिकारी द्वारा जांच

87. पाटनरोधी नियमावली के अनुच्छेद 3.1 तथा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II में (क) पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में मूल्यों पर उनका प्रभाव, (ख) पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभावों की वस्तुनिष्ठ जांच का प्रावधान है। प्राधिकारी द्वारा इस बात की जांच की जानी अपेक्षित है कि क्या अनात्मक संवर्धित देश में समग्र रूप से अथवा उत्पादन अथवा खपत की तुलना में आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मूल्यों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात की जांच करनी आवश्यक समझी जाती है कि क्या भारत में समान वस्तु के मूल्य की तुलना में पाटित आयातों से मूल्यों में पर्याप्त गिरावट आई है अथवा क्या अन्यथा ऐसे आयातों का उद्देश्य मूल्यों को काफी हद तक कम करना है अथवा ऐसी मूल्य वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी हद तक बढ़ गई होती।

88. प्राधिकारी ने क्षति जांच संबंधी पहलू के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों को नोट किया है तथा इस प्रकटन विवरण में उचित स्थानों पर उठाए गए मुद्दों का उस सीमा तक उल्लेख किया है जहाँ तक वे तर्कसंगत हैं। प्राधिकारी ने अपने पास उपलब्ध तथ्यों तथा हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों पर विचार करके क्षति मानदण्डों पर विचार किया है।

घ.2.1. क्षति संबंधी संचयी जांच

89. अनुबंध II (iii) के अनुसार, ऐसे मामलों में जहाँ उत्पाद का आयात एक से अधिक देशों से साथ-साथ चल रही पाटनरोधी जांच के अध्येक्षित है तब निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करेगा यदि यह निर्धारित होता है कि (क) प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में स्थापित पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में यथाव्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है तथा प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयात का तीन प्रतिशत है अथवा जहाँ अलग-अलग देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है वहाँ आयात संचयी रूप से समान वस्तु के आयात के सात प्रतिशत से अधिक का बनता है, और (ख) आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन आयातित वस्तु तथा समान घरेलू उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की शक्तों के आलोक में उचित है।

90. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन का मार्जिन 2 प्रतिशत से अधिक है तथा प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा 3 प्रतिशत से अधिक है।

91. जहाँ तक आयातित उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों तथा आयातित उत्पादों तथा समान घरेलू उत्पाद के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि :

- (i) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात समान टैरिफ वर्गीकरणों के तहत किया गया है;
- (ii) आयातित संबद्ध वस्तुएं, घरेलू रूप से उत्पादित पूर्णतः विन्यासित यार्न का वाणिज्यिक एवं तकनीकी प्रतिस्थापन है।
- (iii) संबद्ध वस्तुओं का आयात अंतिम प्रयोक्ताओं तथा अन्य आयातकों द्वारा किया गया है तथा वस्तुएं, समान चैनलों के जरिए देश के वाणिज्य में प्रविष्ट हुई हैं;

92. अतः प्राधिकारी का यह विचार है कि संबद्ध देशों से किए गए आयात समान बाजार में प्रतिस्पर्धा करते हैं, क्योंकि ये समान उत्पाद हैं। अतः कोरिया गणराज्य के निर्यातकों द्वारा दिया गया तर्क कि क्षति की असंघयी जांच की जानी चाहिए, मान्य नहीं है।

93. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी का मानना है कि आयातित उत्पादों तथा समान घरेलू उत्पाद के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के घरेलू रूप से उत्पादित समान उत्पाद पर प्रभाव की संघयी जांच करना उचित है। अतः जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, क्षति एवं कारणात्मक संबंध विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, संबद्ध देशों से पाटित आयातों को, घरेलू उद्योग पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों की मात्रा एवं कीमत के प्रभाव की जांच करने तथा पाटन एवं क्षति के बीच पाटन की मीजदूगी तथा कारणात्मक संबंध, यदि कोई हो, की जांच करने हेतु कीमत एवं लाभप्रवृत्ता पर उसके प्रभाव की जांच करने के लिए संघित किया गया है। नियमों में सभी संगत आर्थिक कारकों एवं सूचकांकों, जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, के मूल्यांकन के आधार पर घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच का प्रावधान है। इस जांच के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ता नियमावली के नियम 2 (ख) के तहत यथापरिभाषित घरेलू उद्योग के अर्थों के भीतर घरेलू उद्योग है।

94. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार, रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में प्राधिकारी द्वारा समस्त घरेलू उद्योग हेतु क्षति एवं एनआईपी का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है और केवल किसी विशेष कंपनी अथवा उद्यम के संबंध में नहीं। अतः उपर्युक्त आदेशों के अनुपालन में प्राधिकारी ने सभी ज्ञात घरेलू उत्पादकों हेतु लागत एवं क्षति संबंधी सूचना मांगवाई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह रेखांकित किया था कि "घरेलू उद्योग का अभिप्राय" समग्र रूप से घरेलू उत्पादकों से है। तथापि, इन उत्पादकों ने, उक्त निर्णय के विषय में स्वयं की व्याख्या के आधार पर उपर्युक्त विषय के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध कराने से मना कर दिया है। घरेलू उद्योग तथा अन्य ज्ञात उत्पादकों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय में, एनआईपी तथा क्षति निर्धारण के लिए सभी घरेलू उत्पादकों को शामिल करना अपेक्षित नहीं है।

95. अपने प्रकटन पश्चात निवेदन में घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में प्रयुक्त "समग्र रूप से घरेलू उद्योग" शब्दों के अर्थ की व्याख्या "समग्र घरेलू उत्पादकों" के रूप में कर रहे हैं। इस संबंध में, यह निवेदन किया गया है कि माननीय न्यायालय ने उस निर्णय में कहा था कि क्षति एवं एनआईपी का निर्धारण "समग्र घरेलू उद्योग" के लिए

किया जाना चाहिए न कि किसी विशेष कंपनी अथवा उधम के लिए । उसी पैराग्राफ में माननीय उच्चतम न्यायालय ने नियम 2 (ख) के तहत घरेलू उधोग की परिभाषा का उल्लेख किया है । पूरी बातचीत के दौरान उच्चतम न्यायालय ने "समग्र घरेलू उधोग" शब्दों का उपयोग किया है न कि "समग्र घरेलू उत्पादकों" का । इसके अतिरिक्त, किसी भी समय पर उच्चतम न्यायालय ने यह नहीं कहा है कि "घरेलू उधोग" शब्द की व्याख्या नियम 2 (ख) में दी गई परिभाषा से किसी भी अलग प्रकार से की जानी चाहिए । दूसरी ओर, जैसा कि पहले कहा गया है, न्यायालय ने उसी पैराग्राफ में "घरेलू उधोग" की परिभाषा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है ।

96. प्राधिकारी नोट करते हैं कि माननीय न्यायालय के निर्णय की उपर्युक्त व्याख्या, उक्त निर्णय के अनुरूप नहीं है । अतः प्राधिकारी ने क्षति एवं एनआईपी के निर्धारण हेतु समग्र घरेलू उधोग को उस सीमा तक शामिल किया है जहां तक वे संगत एवं आसानी से उपलब्ध हैं । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अभिमतों में यह व्यक्त किया है कि "घरेलू उधोग" का अभिप्राय "समग्र रूप से घरेलू उत्पादकों" से है । संबद्ध वस्तुओं के दो प्रमुख उत्पादकों अर्थात् मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. तथा मै. इंडोसिमा की लागत एवं क्षति संबंधी सूचना की जांच कंपनी मामले मंत्रालय की लागत लेखा शाखा के पास उपलब्ध लागत लेखा रिपोर्टों के संदर्भ में की है । संबद्ध वस्तुओं के तीसरे ज्ञात उत्पादक, मै. पारस पेट्रोफिन्स की लागत एवं क्षति संबंधी सूचना लागत लेखा रिपोर्टों अथवा किसी अन्य स्वरूप में उपलब्ध नहीं है । तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कंपनी द्वारा भेजे गए समर्थन पत्र में दी गई सूचना के अनुसार जांच अवधि के दौरान उन्होंने 2000 मी. टन का उत्पादन किया था, जो संबद्ध वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का 3% से कम है । अतः क्षति जांच, संबद्ध वस्तुओं के 8 ज्ञात उत्पादकों के संबंध में उपलब्ध सूचना के आधार पर की गई है जिनका कुल घरेलू उत्पादन तथा संबद्ध वस्तुओं की बिक्री में 97% हिस्सा बनता है ।

च.3.2. मात्रात्मक प्रभाव: पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव तथा घरेलू उधोग पर उसका प्रभाव

97. संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा तथा अन्य देशों से पाटित आयातों की मात्रा निम्नानुसार की गई है:

(I) संबद्ध देशों की आयात मात्राएं एवं हिस्से:

98. क्षति जांच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों, सहयोगी निर्यातकों के निर्यात आंकड़ों तथा घरेलू उधोग द्वारा अन्य गौण स्रोतों से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की जांच की है । प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांचों में नोट किया है कि डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों में सीमाशुल्क 5402.43 के तहत सूचित आयातों की मात्रा तथा संबद्ध देशों से उत्तरदाता निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में काफी अंतर है । इसके मद्देनजर, अन्य सीमाशुल्क शीर्षों के तहत सूचित आयात की भी जांच की गई है तथा यह नोट किया गया है कि सीमाशुल्क 5402.43 के तहत आयातित संबद्ध उत्पादों की पर्याप्त मात्रा का आयात किया गया है । अतः मात्रात्मक विश्लेषण के प्रयोजनार्थ आयात आंकड़ों का निर्धारण उपर्युक्त शीर्षों के तहत डीजीसीआईएंडएस आयात आंकड़ों तथा सहयोगी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर किया गया है । इस आंकड़े के आधार पर संबद्ध देशों की आयात मात्रा निम्नानुसार है:

	2001-02	2002-03	2003-04	मात्रा मी. टन में जॉय अवधि
देश				
इंडोनेशिया	2697	8189	8243	6035
कोरिया गणराज्य	1454	4775	13359	13359
मलेशिया	14314	18612	22380	36883
ताइपेई	3358	4495	5128	5128
कुल संबद्ध देश	21824	38052	49090	61405
प्रवृत्ति	100	165	225	281
अन्य	4235	4693	3335	2013
प्रवृत्ति	100	111	79	48
कुल	26059	40745	52425	63418
प्रवृत्ति	100	156	201	243
हिस्सा	83.75%	88.48%	93.64%	96.83%

99. उपर्युक्त आँकड़ों से यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में आधार वर्ष की तुलना में 181% और पिछले वर्ष की तुलना में 25% वृद्धि हुई है, जबकि कुल आयात आधार वर्ष की तुलना में 143% और पिछले वर्ष की तुलना में 21% बढ़ गए हैं। कुल आयातों में संबद्ध देशों से आयातों के हिस्से में आधार वर्ष की तुलना में 13% और पिछले वर्ष की तुलना में 3% वृद्धि हुई है।

(ii) घरेलू क्षमता एवं क्षमता उपयोग

100. प्राधिकारी के पास उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर, घरेलू उद्योग तथा समग्र रूप से घरेलू उद्योग की कुल क्षमता, उत्पादन तथा क्षमता उपयोग का परिकलन निम्नानुसार है :-

	2001-02	2002-03	2003-04	मात्रा मी. टन में जॉय अवधि
घरेलू उद्योग की क्षमता	40340	61430	61490	64170
प्रवृत्ति	100	152	152	159
अन्य उत्पादकों की क्षमता	21300	21300	32971	34754
प्रवृत्ति	100	100	155	163
कुल क्षमता	61640	82730	94461	98924
प्रवृत्ति	100	134	153	160
घरेलू उद्योग का उत्पादन	27141	48986	50666	46780
प्रवृत्ति	100	180	187	172
घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग	87%	80%	82%	73%
अन्य का उत्पादन	13830	18495	29184	29898
प्रवृत्ति	100	134	211	216
अन्य का क्षमता उपयोग	65%	87%	89%	86%
कुल घरेलू उत्पादन	40971	67481	79850	76678
प्रवृत्ति	100	165	195	187
समग्र रूप से क्षमता उपयोग	86%	82%	85%	78%

101. उपर्युक्त आँकड़े दर्शाते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में देश में क्षमता में लगभग 60% तक की अत्यधिक वृद्धि हुई है। तथापि, पिछले वर्षों में कामी वृद्धि दर्शाने के बाद संबद्ध वस्तु के उत्पादन के साथ-साथ क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। कुल क्षमता उपयोग में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग

4% गिरावट आई है। वर्ष 2003-2004 में 65% के स्तर तक पहुँचने के बाद समग्र रूप से घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6% गिरावट आई है। तथापि, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि जाँच अवधि के दौरान कुल घरेलू क्षमता में भी लगभग 3000 मी. टन की वृद्धि हुई है और आधार वर्ष की तुलना में क्षमता में लगभग 60% वृद्धि हुई है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि क्षमता और क्षमता उपयोग पर माँग तथा अन्य मापदण्डों के साथ विचार किए जाने की आवश्यकता है।

(iii) माँग, उत्पादन एवं बाजार हिस्सा

102. माँग एवं बाजार हिस्सों में वृद्धि के संबंध में भी आयात मात्रा में वृद्धि का विश्लेषण किया गया है।

(क) बिक्रियाँ

103. समग्र रूप से घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध वस्तु की घरेलू बिक्रियों की जाँच निम्नानुसार की गई है:-

				मात्रा मी. टन में
बिक्रियाँ	2001-02	2002-03	2003-04	जाँच अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्रियाँ	23586	39481	46653	44674
प्रवृत्ति	100	167	198	169
अन्य घरेलू उत्पादक	12776	17906	26408	31416
प्रवृत्ति	100	140	207	246
कुल घरेलू बिक्रियाँ	36362	57387	73061	76090
प्रवृत्ति	100	158	201	209
आबद्ध खपत	396	647	1423	1281
कुल माँग	62616	96979	126909	140789
प्रवृत्ति	100	158	202	224

104. उपर्युक्त आँकड़े दर्शाते हैं कि समग्र रूप से घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध वस्तु की बिक्रियों में 100% से अधिक की वृद्धि हुई है। तथापि, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि समग्र रूप से घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध वस्तु की बिक्रियों में वृद्धि की तुलना में घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की माँग और अधिक वृद्धि हुई है।

105. प्राधिकारी नोट करते हैं कि माँग में आधार वर्ष की तुलना में 124% और पिछले वर्ष की तुलना में 11% वृद्धि हुई है। समग्र रूप से घरेलू उद्योग की बिक्रियों में आधार वर्ष की तुलना में 109% और पिछले वर्ष की तुलना में 4% वृद्धि हुई है।

(ख) माँग एवं बाजार हिस्सा

माँग में हिस्सा	2001-02	2002-03	2003-04	जाँच अवधि
घरेलू उद्योग	38%	40%	37%	32%
प्रवृत्ति	100	106	98	85
अन्य घरेलू उत्पादक	20%	18%	21%	22%
प्रवृत्ति	100	89	102	110
कुल घरेलू बिक्री	58%	58%	58%	54%
प्रवृत्ति	100	100	99	93
संबद्ध देश	35%	38%	39%	44%
प्रवृत्ति	100	105	111	126
अन्य देश	7%	6%	4%	2%
प्रवृत्ति	100	76	51	32

106. कुल माँग में घरेलू उद्योग का हिस्सा 38% से घटकर 32% और सभी घरेलू उत्पादकों का हिस्सा 48% से घटकर 54% हो गया है। संबद्ध देशों से आयातों का बाजार हिस्सा वर्ष 2001-2002 में 35% से बढ़कर जाँच अवधि के दौरान 44% हो गया है। कुल माँग में अन्य देशों का हिस्सा 7% से बहुत अधिक घटकर 2% हो गया है। अतः, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि जाँच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों में न केवल सापेक्ष रूप से बल्कि भारत में कुल आयात, कुल माँग और घरेलू उत्पादन की तुलना में भी वृद्धि हुई है।

च.2.3 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

107. संबद्ध देशों/क्षेत्रों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जाँच कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत अवमूल्यन तथा कीमत ह्रास, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में निर्धारित घरेलू उद्योग की भारत औसत निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) और गैर क्षतिकारक कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देशों से आयातों की पहुँच लागत से की गई है।

(i) कीमत कटौती तथा कम कीमत पर बिक्री के प्रभाव

	2001-02	2002-03	2003-04	जाँच अवधि
घरेलू बिक्री कीमत	*****	*****	*****	*****
प्रवृत्ति	100	94	98	101
विनिर्माण एवं बिक्री की लागत	*****	*****	*****	*****
प्रवृत्ति	100	98	100	109
पहुँच मूल्य				
इंडोनेशिया	83280	78776	65780	62251
कोरिया गण.	93564	85308	65839	64580
मलेशिया	81834	79177	61834	58399
ताइपेई	81877	74169	61599	60310
संबद्ध देश	82801	79274	63562	60588
प्रवृत्ति	100	96	77	73
कीमत कटौती				
इंडोनेशिया				30-40%
कोरिया गण.				25-35%
मलेशिया				40-50%
ताइपेई				35-45%
संबद्ध देश				35-45%
कम कीमत पर बिक्री				
इंडोनेशिया				45-55%
कोरिया गण.				40-50%
मलेशिया				50-60%
ताइपेई				50-60%
संबद्ध देश				45-55%

108. जैसा कि पहले रिपोर्ट किया गया है समग्र रूप में घरेलू उद्योगों की लिए निर्मित एवं बिक्री लागत और बिक्री एवं बिक्री कीमत (निवल बिक्री वसूली) का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना और अन्य प्राप्त उत्पादकों की लागत परीक्षा रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर किया गया है। उपर्युक्त आंकड़ों से आधार वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में बिक्री लागत में अत्यधिक वृद्धि प्रदर्शित होती है। तथापि, घरेलू उद्योगों की समग्र रूप में निवल बिक्री वसूली में केवल 1% की वृद्धि हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत पर्याप्त कमी को दर्शाती है।

109. जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिमत है, संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कीमत कटौती प्रभाव का निर्धारण समूची जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से पाटित आयातों के भारत आसत पहुंच मूल्य की उसी अवधि के लिए समग्र रूप में घरेलू उद्योग की भारत आसत निवल बिक्री वसूली के साथ तुलना करके किया गया है। इस प्रयोजनार्थ आयातों के पहुंच मूल्य की गणना संबद्ध देशों से आयातों के सीआईएफ मूल्य में 1% डडलिंग प्रभाव और लागू मूल सीमाशुल्क जोड़कर की गई है।

110. घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली का निर्धारण करने में घरेलू उद्योग द्वारा दी गई छूटों, कटौतियों और कमीशनों और भुगतान किए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को घटा दिया गया है। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिमत है, कम कीमत पर बिक्री के निर्धारण के प्रयोजनार्थ संबद्ध देशों से आयातों की भारत आसत पहुंच कीमतों की जांच अवधि के लिए निर्धारित घरेलू उद्योग की क्षतिरहित बिक्री कीमत के साथ समग्र रूप में तुलना की गई है।

111. जहां तक कीमत कटौती का संबंध है, संबद्ध देशों से आयातों में अत्यधिक कीमत कटौती प्रदर्शित हुई है। सभी संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्य को प्राधिकारी द्वारा निर्धारित घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से अलग-अलग और संघयी रूप से बहुत कम पाया गया है जिससे घरेलू उद्योग पर कम कीमत पर बिक्री का अत्यधिक प्रभाव पड़ने का संकेत मिलता है।

(II) पाटित आयातों के कीमत ह्रास और न्यूनीकरण संबंधी प्रभाव

112. पाटित आयातों के कीमत ह्रास/न्यूनीकरण संबंधी प्रभावों की भी घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री वसूली और संबद्ध देशों से पहुंच मूल्यों के संदर्भ में जांच की गई है। क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की समग्र रूप में उत्पादन लागत की प्रवृत्ति में लगभग 9% की वृद्धि प्रदर्शित होती है। तथापि, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में समग्र रूप में केवल 1% की मामूली वृद्धि प्रदर्शित होती है। बिक्री लागत और बिक्री कीमत की आयात कीमतों की प्रवृत्ति के साथ तुलना यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से हुए पाटित आयातों के कीमत प्रभावों के कारण उत्पादन लागत में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए अपनी कीमतों को बढ़ाने से रोक रखा गया है, जो पर्याप्त कीमत ह्रास को प्रदर्शित करता है।

च.2.4 क्षति के अन्य मापदंडों की जांच

113. घरेलू उद्योग की मात्राओं और कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव और क्षति के प्रमुख संकेतकों जैसे आयातों की मात्रा एवं मूल्य, क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग एवं घरेलू उद्योग की बिक्री तथा विभिन्न खंडों के बाजार हिस्सों के साथ मांग की पद्धति की जांच करने के पश्चात् अन्य आर्थिक मापदंडों, जिनसे

घरेलू उद्योग की क्षति की मौजूदगी का संकेत मिल सकता था, का प्राधिकारी द्वारा विश्लेषण किया गया है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की गैर-भागीदार घरेलू उद्योग के लिए विचाराधीन उत्पाद के संबंध में सभी क्षति संबंधी मापदंडों पर दी गई सुनिश्चित सूचना लागत लेखा परीक्षा रिपोर्टों या कोई अन्य सार्वजनिक/गोपनीय दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं है ताकि समग्र रूप में घरेलू उद्योग के लिए सभी क्षति संबंधी मापदंडों की उद्देश्यात्मक जांच की जा सके। इसलिए, जहां तक संभव है भागीदार घरेलू उद्योग के आंकड़ों पर निम्नलिखित मापदंडों की जांच हेतु विचार किया गया है :-

(i) उत्पादकता पर वास्तविक एवं संभावित प्रभाव

114. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु का कुल उत्पादन और आवेदक घरेलू उद्योग का उत्पादन पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में लगभग क्रमशः 87% और 72% बढ़ा है। तथापि, भागीदार घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या में पर्याप्त कमी आई है जो यह दर्शाती है कि क्षति जांच अवधि की तुलना में घरेलू उद्योग के उत्पादन में पर्याप्त सुधार हुआ है।

ii. लाभ पर वास्तविक एवं संभावित प्रभाव

115. घरेलू उद्योग की संबद्ध वस्तु की लागत एवं कीमतों के समग्र रूप में आंकड़ों के आधार पर उद्योग के लाभ को निम्न प्रकार से निकाला गया है :-

लाभप्रवृत्ता	2001-02	2002-03	2003-04	जांच अवधि
समग्र रूप में घरेलू उद्योग की भारित औसत एमएसआर	*****	*****	*****	*****
प्रवृत्ति	100	94	98	101
समग्र रूप में घरेलू उद्योग की भारित औसत बिजली लागत	*****	*****	*****	*****
प्रवृत्ति	100	98	100	109
लाभ/हानि/एमटी	*****	*****	*****	(*****)
प्रवृत्ति	100	20	59	-33

116. उपरोक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता समग्र रूप में में पर्याप्त कमी आई है और क्षति जांच अवधि के दौरान उत्पादन और बिक्रियों में वृद्धि के बावजूद पर्याप्त लाभ के स्तर से हानि तक पहुँचने से घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन की स्थिति में एक निर्धारित स्तर तक गिरावट आई है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की पहुंच मूल्य में कमी लाभ में आई गिरावट के कारण हुई है।

iii. नकद प्रवाह संबंधी वास्तविक एवं संभावित प्रभाव

117. गैर-भागीदार घरेलू उत्पादकों के संबंध में नकद प्रवाह स्थिति उपलब्ध नहीं है। तथापि, भागीदार घरेलू उद्योग के आंकड़े क्षति संबंधी जांच अवधि की तुलना में घरेलू उद्योग की बिगड़ती नकद प्रवाह स्थिति को दर्शाती है।

iv. रोजगार तथा मजदूरी

118. भागीदार घरेलू उद्योग के संदर्भ में रोजगार एवं मजदूरी पर पाटित आयातों से पड़े प्रभावों की जांच की गई है। आंकड़े दर्शाते हैं कि कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है और उसी अवधि के दौरान मजदूरी में वृद्धि हुई है।

	2001-02	2002-03	2003-04	जांच अवधि
घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या	556	596	575	476
सूची	100	107	103	86
मजदूरी कुल (लाख रु.)	*****	*****	*****	*****
सूची	100	148	160	182

v. निवेश पर आय तथा पूंजी जुटाने की क्षमता

119. घरेलू उद्योग के वित्तीय निष्पादन की जांच करने पर इसमें उसके नकद लाभों और निवेश पर आय की दृष्टि से काफी विकृति आई है। घरेलू उद्योग अपने निवेशों पर लगभग 5% की सकारात्मक आय से नकारात्मक आय की स्थिति में आ गया है। यद्यपि घरेलू प्रचालनों में लगाई गई पूंजी में वृद्धि हुई है तथापि, संबद्ध देशों से पाटित आयातों के दबाव के कारण आधार वर्ष की तुलना में लाभ और निवेशों से आय में भारी गिरावट आई है।

निवेश पर आय	2001-02	2002-03	2003-04	जांच अवधि
लाभ/हानि (लाख रु.)	*****	*****	*****	*****
जमा: ब्याज	*****	*****	*****	*****
ब्याज पूर्व लाभ/हानि	*****	*****	*****	*****
लगाई गई पूंजी	*****	*****	*****	*****
निवेश पर प्राप्ति	4.67%	4.23%	-0.64%	-8.49%

vi. निवेश तथा पूंजीगत निवेश जुटाने की क्षमता

120. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान क्षमता में मामूली वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग ने इस व्यवसाय में कोई बड़ा पूंजी निवेश नहीं किया है। प्राधिकारी ने यह पाया है कि क्षमता में और वृद्धि करने के लिए घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर जांच अवधि के दौरान नकारात्मक आय को ध्यान में रखते हुए प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

vii. पाटन की मात्रा

121. उस सीमा के संकेतक के रूप में जहाँ तक पाटित आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा सकते हैं, पाटन की मात्रा यह दर्शाती है कि संबद्ध देश के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन काफी अधिक पाए गए हैं।

viii. कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

122. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदकों को छोड़कर भारत के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु के कुछ अन्य घरेलू उत्पादक हैं जो कुल बाजार मांग का लगभग 22% हिस्से को पूरा करते हैं। इन उत्पादकों के आंकड़े घरेलू उत्पादकों के बीच लागत और कीमत के बीच पर्याप्त अंतर को दर्शाते हैं। तथापि, अन्य ज्ञात उत्पादकों सहित घरेलू उद्योग के लिए समग्र रूप में क्षति संबंधी जांच की गई है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से हुए पाटित आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों पर भारी कीमत कटौती एवं कम बिक्री प्रभाव पड़ा है जो यह दर्शाते हैं कि भारत की घरेलू कीमतों पर पाटित आयातों से पर्याप्त प्रभाव पड़ा है।

ix. स्टॉक

स्टॉक	2001-02	2002-03	2003-04	जांच अवधि
घरेलू उद्योग	*****	*****	*****	*****
प्रवृत्त	100	125	103	73

123. घरेलू उद्योग के स्टॉक संबंधी आंकड़े दर्शाते हैं कि पड़े हुए स्टॉक में पर्याप्त कमी आई है।

x. वृद्धि

124. प्राधिकारी पाते हैं कि देश में संबद्ध वस्तु की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और मांग में क्षति/संबंधी जांच अवधि में पर्याप्त वृद्धि हुई है और यह सकारात्मक वृद्धि दर्शाती है। तथापि, उत्पादन और बिक्रियों का बढ़ती हुई मांग के साथ मेल नहीं हो पाया है। मांग में वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में समग्र रूप में उसी अवधि के दौरान 4% से ज्यादा कमी आई है।

6. अन्य कारक एवं कारात्मक संबंध

125. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से पारित आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में समग्र रूप से अत्यधिक कमी आयी है। पारित आयातों में समग्र रूप से और आयातों की मात्रा उत्पादन और भारत में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री के संबंध में दोनों कयों में बढ़ोतरी हुई है।

126. पारित आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में भी अत्यधिक कटौती हुई है जिसके कारण घरेलू बाजार में कीमतों में अत्यधिक मंदी आयी है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को समग्र रूप से घाटा हुआ है।

127. अतः प्राधिकरण का मानना है कि पारित आयातों का घरेलू उद्योग पर मात्रा एवं कीमत संबंधी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है।

128. नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग की स्थिति और पारित आयातों के प्रभाव की जांच करने के पश्चात प्राधिकारी ने पारित आयातों से इतर अन्य कारकों की भी जांच की है। जिनका घरेलू उद्योग पर अत्यधिक अभाव पड़ सकता था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हित बद्ध पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार द्वारा प्राधिकारी के ध्यान में कोई अन्य कारक नहीं लाया गया है। जिससे घरेलू उद्योग पर प्रभाव पड़ सकता था। इसलिए उस संबंध में निम्नलिखित अनिवार्य कारकों की जांच की गई है।

i) अन्य देशों से आयात

129. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से आयात संबद्ध वस्तुओं के कुल आयातों का लगभग 97 प्रतिशत हिस्सा बनता है और वर्ष 2001-02 और

पीओआई के बीच संबद्ध देशों पारित आयात कुल आयातों के एक हिस्से के रूप में 82 प्रतिशत से बढ़ कर 97 प्रतिशत हो गए हैं। अन्य श्रोतों से आयात कुल आयातों और बाजार में मांग का एक बहुत छोटा हिस्सा बनता है। इसलिए अन्य श्रोतों से आयातों का घरेलू उद्योग पर कोई खास प्रभाव पड़ा हुआ नहीं मालूम होता है।

ii) व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा और विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

130. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु मुक्त रूप से आयात योग्य है तथा भारतीय उत्पादकों तथा अन्य प्रतिस्पर्धा की उद्योगों द्वारा कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धति नहीं अपनायी जाती है। अधिकारी यह यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के लिए समग्र रूप से क्षति की जांच संचयी स्तर पर लेखा लागत और सभी घरेलू उत्पादकों की कीमतों को ध्यान में रख कर की गई है। इसलिए विभिन्न घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा को घरेलू उद्योग की क्षति का कारण नहीं माना जा सकता है।

iii) मांग में संकुचन अथवा खपत के ढंग में परिवर्तन

131. यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन अवधि के दौरान समूची मांग में कोई संकुचन नहीं हुआ है। इसके विपरीत, समग्र मांग जांच अवधि के दौरान बढ़कर 124 प्रतिशत हो गई। इसीलिए मांग में संभावित गिरावट, घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकने वाला एक कारक नहीं है।

iv) प्रौद्योगिकी

132. हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग तथा संबद्ध देशों में निर्यातकों द्वारा अंगीकृत प्रौद्योगिकी में अंतर के संबंध में मुद्दे उठाए हैं। जिसके परिणामस्वरूप निर्यातकों के लिए लागत क्षमता बनी है। तथापि, पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में प्राधिकारी का यह मत है कि प्रौद्योगिकी में अंतर, यदि कोई हो, से घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव प्रदर्शित नहीं हुआ है।

v) अन्य देशों से आयात निर्यात निष्पादन

133. घरेलू उद्योग के पास जांच अवधि के दौरान साथ ही साथ पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान संबद्ध वस्तु का बिल्कुल नगण्य निर्यात है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के नियति निष्पादन में सुधार प्रदर्शित हुआ है।

vi) उत्पादकता

134. जहां तक घरेलू उद्योग की उत्पादकता का संबंध है प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान उत्पादकता में सुधार हुआ है।

135. उपर्युक्त जांच से यह प्रदर्शित होता है कि कोई अन्य महत्वपूर्ण कारक नहीं है जिससे घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रभाव पड़ सकता था और घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी। इसलिए प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि पारित आयातों से मात्रा एवं कीमत प्रस्तावों के जरिए घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

ज. क्षति एवं कारणात्मक संबंध संबंधी निष्कर्ष

136. पूर्ववर्ति खण्ड में घरेलू उद्योग की स्थितियों और गैर-आरोप्य कारकों की जांच के आधार पर प्राधिकारी पाते हैं कि

क. संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में समग्र रूप से और भारत में कुल मांग एवं घरेलू उत्पादन के संबंध में वृद्धि हुई है।

ख. पूर्ववर्ती वर्षों में स्वस्थ वृद्धि के पश्चात घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में समग्र रूप से कमी आयी है जबकि आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है।

ग. जांच अवधि में लाभप्रदत्व निवेश पर आय और नकदी प्रवाह आधार वर्ष में सकारात्मक स्तर से नकारात्मक हो गई हैं।

घ. चूंकि घरेलू उद्योग के लिए आर ओ सीई नकारात्मक है, इसलिए उनकी पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता बुरी तरह से प्रभावित हुई है।

ड. घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग और बिजी मात्रा में पूर्ववर्ती वर्षों में पर्याप्त वृद्धि के पश्चात कमी आयी है।

च. अत्यधिक तीव्र कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री हुई है।

छ. प्राधिकारी के ध्यान में पारित आयातों में इतर कोई अन्य कारक नहीं लाया गया है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।

137. उपर्युक्त के परिप्रेष्य में प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है और यह क्षति संबद्ध देशों से पारित आयातों के कारण हुई है।

ज. क्षति मार्जिन की मात्रा

ज.1. क्षतिरहित कीमत का निर्धारण

138. अधिकारी यह कहते हैं कि घरेलू उद्योग में जो क्षति-रहित मूल्य दिये गये हैं वह भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार हैं जैसा कि पहले कहा गया है। और मूल्य गणना की जो पद्धती जो एन.आई.पी. के लिए बनाई गई है वह घरेलू उद्योग के अनुसार है। घरेलू उद्योग द्वारा इस बात पर बहस की गई है कि जो एन.आई.पी. के लिए जो मूल्य के गणना की पद्धती को अपनाया गया है वह माननीय न्यायालय के फैसले के सिद्धांतों के अनुसार नहीं है जैसा कि विधि संहिता में कहा गया है। अधिकारी द्वारा जो पद्धती अपनाई गई है, क्षति-रहित मूल्य घरेलू उद्योग की टिप्पणी है कि उसे अभिलेखों में लिया गया है।
139. अधिकारी इस बात पर संकेत देते हैं कि जो क्षति-रहित मूल्य घरेलू उद्योग के लिए निश्चय किये गये हैं वह सभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार हैं और वह भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये मार्गदर्शन और पद्धती के अनुसार हैं। एन.आई.पी. का वजन औसतन, घरेलू उद्योग के लिए रुपये प्रति टन निश्चित किया गया है।
140. अधिकारी द्वारा जो क्षति-रहित मूल्य की गणना कि गई है वह सभी प्रकार के घरेलू उद्योगों के सभी प्रकार के उत्पादनों के लिए औसतन सामान्य हैं जिस प्रदेश को विषय वस्तु को निर्यात किया जाना है उसमें क्षति गुंजाईश के निश्चयके अनुसार है। और वह सभी तुलतात्मक वजन औसत के अनुसार भी है। निर्यात के लिए वजन औसत मूल्य और क्षति गुंजाईश जिस प्रदेश को विषय वस्तु निर्यात करनी है वह निम्न प्रकार से है:-

क्षति गुंजाईश की गणना		
कम्पनी का नाम	क्षति गुंजाईश यू एस डौलर्स /किलो में	क्षति गुंजाईश प्रतिशत में
मैसर्स पी.टी. मूटू गैडिंग टैक्सटील, इण्डोनेशिया	*****	-5 से 15%
अन्य निर्यातक, इण्डोनेशिया	*****	40-50%
मैसर्स एच. के. कोरपोरेशन, कोरिया	मूल्यों की वचनबद्धता	
मैसर्स हयोसंग कोरपोरेशन, कोरिया	*****	0-10%
मैसर्स सेहन इन्डस्ट्री, कोरिया	*****	-20-30%
मैसर्स हूसिव कोरपोरेशन, कोरिया	*****	-15-20%
अन्य निर्यातक, कोरिया	*****	40-50%
मैसर्स हयूलोन कोरपोरेशन, मलेशिया	*****	20-30%
अन्य निर्यातक, मलेशिया	*****	50-60%
मैसर्स नान या प्लास्टिकस कोरपोरेशन, चाईनिश टाईपाई	*****	20-30%
अन्य निर्यातक, चाईनिश टाईपाई	*****	45-55%

एच-2.

भारतीय उद्योगों का लाभ और अन्य अन्तर्हित प्रश्न

141. अधिकारीयों का यह कदम पाटन निवारण के लिए शुल्क के लिए है, सामान्य में, इससे घरेलू उद्योगों को क्षति पहुंचती हैं और यह पाटन जैसा अनुचित कदम है, इसलिए इन हालातों से उभरने के लिए और खुले रूप से बाजार में आने के लिए और उनकी बहाली के लिए यह कदम है।

142. अधिकारी यह भी मानते हैं कि यदि पाटन निवारण पर शुल्क लगाया जाता है तो वह उत्पादन के मूल्य के स्तर को भी प्रभावित कर सकता है और साथ ही इससे मिलते जुलते उत्पादनों के मूल्यों को भी प्रभावित करेगा, इसलिए, भारत के बजार में स्पष्ट प्रतियोगिता के लिए पाटन की मात्रा को कम नहीं किया जा सकता। इसके प्रतिकूल, यदि पाटन उपायों को लगाया जाता है तो उससे अनुचित ढंग से लाभ उठाने वाले रवैये को रोका जा सकता है और उससे घरेलू उद्योगों को भी बचाया जा सकता है और ऐसा करने से विषय वस्तु को जारी रखने के लिए ग्राहकों के पास अच्छा विकल्प होगा।

जे. निष्कर्ष

143. उपरोक्त हालातों को मध्येजनर रखते हुए अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि :-

- a. विषय वस्तु जहां उत्पन्न हुई है या किसी अन्य देश से भारत में निर्यात की गई है वह अपने सामान्य मूल्य से कम आयेगी।
- b. घरेलू उद्योग आर्थिक क्षति से पीड़ित होगी।
- c. पाटन निर्यातकों द्वारा जिनके द्वारा माल उत्पन्न किया जाता है या निर्यात किया जाता है के अनुसार यह क्षति घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुंचा सकती है।

के. अनुशंसा

144. पाटन की प्रक्रिया पर जांच की गई, इसमें क्षति और संबंध पाए गए पाटन और क्षति के घरेलू उद्योगों के नियम व शर्तों में जो कि विधि संहिता में दिये

गये हैं और सकारात्मक पाटन गुंजाई को विषय-प्रदेश के प्रति स्थापित किया जा सकेगा और उसी तरह से माल क्षति को भी रोका जा सकता है जो पाटन निर्यातकों द्वारा की जाती है इसलिए अधिकारियों का यह मत है कि पाटन शुल्क से इसको एक मोड़ दिया सकता है जिससे कि घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुंचता है।

145. इसलिए, अधिकारी इस नतिजे पर पहुंचे हैं कि निर्यात पर और विषय वस्तु जहां से विषय वस्तु का निर्यात होना है पर पाटन की प्रक्रिया पर शुल्क लगाया जाना अति आवश्यक है इस ढंग से कि निर्यातको के सिवाय जिस अधिकारी द्वारा मूल्यों की वचनबद्धता का वर्णन किया गया है या उनको स्वीकार किया गया है।

146. प्राधिकारी द्वारा अनुसरण किए गए कम शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन जो भी कम हो, के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग की क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी सिफारिश करते हैं कि इंडोनेशिया, कोरिया गणराज्य, मलेशिया और चीनी ताइपेई के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित सीमाशुल्क टैरिफ वर्गीकरण अधिनियम 1975 के अध्याय 54 के अंतर्गत आने वाले फुली ड्रॉन यार्न के सभी आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए। पाटनरोधी शुल्क निम्नलिखित तालिका के कॉलम सं. 9 में उल्लिखित राशि होगी।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	उप-श्रेणी	माल का विवरण	निर्देशन	उद्गम देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	माप की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	5402.43 और 5402.42	फुली ड्रॉन यार्न	कोई	इंडोनेशिया	कोई	मै.पी. टी. मुटु ग्रेडिंग टेक्सटिल, इंडोनेशिया	मै.पी. टी. मुटु ग्रेडिंग टेक्सटिल, इंडोनेशिया	शून्य	मी. टन	अम. डॉलर
2.	-वही-	-वही-	कोई	इंडोनेशिया	कोई	मै.पी. टी. मुटु ग्रेडिंग टेक्सटिल, इंडोनेशिया	उपर्युक्त से इतर कोई अन्य	490	मी. टन	अम. डॉलर
3.	-वही-	-वही-	कोई	इंडोनेशिया	कोई	उपर्युक्त से इतर कोई अन्य	कोई	490	मी. टन	अम. डॉलर
4.	-वही-	फुली ड्रॉन यार्न	कोई	इंडोनेशिया से इतर	इंडोनेशिया	कोई	कोई	490	मी. टन	अम. डॉलर
5.	-वही-	फुली ड्रॉन यार्न	कोई	कोरिया गणराज्य	कोई	मै. एच. के. कॉपरिशन, कोरिया	मै. एच. के. कॉपरिशन, कोरिया	कीमत वचनबद्धता		

6.	-वही-	फुली झून यार्न	कोई	कोरिया गणराज्य	कोई	मै. एच. के. कॉर्पोरेशन, कोरिया	उपर्युक्त से इतर कोई अन्य	588	मी. टन	अम. डॉलर
7.	-वही-	फुली झून यार्न	कोई	कोरिया गणराज्य	कोई	मै. हयोसुंग कॉर्पोरेशन	मै. हयोसुंग कॉर्पोरेशन	64	मी. टन	अम. डॉलर
8.	-वही-	फुली झून यार्न	कोई	कोरिया गणराज्य	कोई	मै. हयोसुंग कॉर्पोरेशन	उपर्युक्त से इतर कोई अन्य	588	मी. टन	अम. डॉलर
9.	-वही-	फुली झून यार्न	कोई	कोरिया गणराज्य	कोई	मै. सीहन इंडस्ट्री, कोरिया	मै. सीहन इंडस्ट्री, कोरिया	शून्य	मी. टन	अम. डॉलर
10.	-वही-	फुली झून यार्न	कोई	कोरिया गणराज्य	कोई	मै. सीहन इंडस्ट्री, कोरिया	उपर्युक्त से इतर कोई अन्य	588	मी. टन	अम. डॉलर
11.	-वही-	फुली झून यार्न	कोई	कोरिया गणराज्य	कोई	मै. ह्यूविस कॉर्पोरेशन, कोरिया	मै. ह्यूविस कॉर्पोरेशन, कोरिया	शून्य	मी. टन	अम. डॉलर
12.	-वही-	फुली झून यार्न	कोई	कोरिया गणराज्य	कोई	मै. ह्यूविस कॉर्पोरेशन, कोरिया	उपर्युक्त से इतर कोई अन्य	588	मी. टन	अम. डॉलर
13.	-वही-	फुली झून यार्न	कोई	कोरिया गणराज्य	कोई	उपर्युक्त से इतर कोई अन्य	कोई	588	मी. टन	अम. डॉलर
14.	-वही-	फुली झून यार्न	कोई	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य से इतर	कोई	कोई	588	मी. टन	अम. डॉलर
15.	-वही-	-वही-	कोई	मलेशिया	कोई	मै. हुआलून कापेरेशन	मै. हुआलून कापेरेशन	163	मी. टन	अम. डॉलर
16.	-वही-	-वही-	कोई	मलेशिया	कोई	मै. हुआलून कापेरेशन	उपर्युक्त से इतर कोई अन्य	456	मी. टन	अम. डॉलर
17.		-वही-	कोई	मलेशिया	कोई	उपर्युक्त से इतर कोई अन्य	कोई	456	मी. टन	अम. डॉलर
18.		-वही-	कोई	मलेशिया से इतर	मलेशिया	कोई	कोई	456	मी. टन	अम. डॉलर
19.		-वही-	कोई	चीनी ताइपेई	कोई	मै. नान या प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन	मै. नान या प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन	40	मी. टन	अम. डॉलर
20.		-वही-	कोई	चीनी ताइपेई	कोई	मै. नान या प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन	उपर्युक्त से इतर कोई अन्य	390	मी. टन	अम. डॉलर
21.		-वही-	कोई	चीनी ताइपेई	कोई	उपर्युक्त से इतर कोई अन्य	कोई	390	मी. टन	अम. डॉलर
22.		-वही-	कोई	चीनी ताइपेई से इतर	चीनी ताइपेई	कोई	कोई	390	मी. टन	अम. डॉलर

ठ. आगे की प्रक्रिया

147. केन्द्र सरकार के आदेशों के विरुद्ध कोई अपील जो इस सिफारिश से उत्पन्न हो सकती है, इस अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जा सकेगी।

148. प्राधिकारी यहाँ यथा- अनुशंसित निश्चयात्मक उपाय को जारी रखने, इसमें परिवर्तन करने अथवा इसे समाप्त करने की जरूरत की अधिनियम के संगत प्रावधानों और इस संबंध में समय-समय पर जारी सार्वजनिक सूचनाओं के अनुसार समय-समय पर समीक्षा कर सकते हैं। ऐसी किसी समीक्षा के लिए कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक इसे किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ निर्धारित समय सीमा के अनुसार दाखिल न किया गया हो।

क्रिस्टी फेर्नांडेज, निर्दिष्ट प्राधिकारी

अनबंध-1

कीमत वचनबद्धता

विषय:- कोरिया गणराज्य, चीनी ताईपेई, मलेशिया और इंडोनेशिया से एफडीवाई के आयात संबंधी पाटनरोधी जांच में मै0 एच.के. कार्पोरेशन, कोरिया द्वारा की गई कीमत वचनबद्धता।

सं. 14/3/2005-डीजीएडी :- यतः 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा गया है) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क का अभिज्ञान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात नियमावली कहा गया है), को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) ने घरेलू उत्पादकों अर्थात् मै0 सेंट्रल इंडिया पोलिस्टर्स लि0, मै0 सेन्चुरी एनको लि0, मै0 गार्डन सिल्क मिल्स लि0, मै0 नोवा पेट्रोकेमिकल्स लि0, मै0 रिक्रॉन सिंथेटिक लि0 और मै0 वेलस्पन सिंटेक्स लि0 की ओर से एसोसिएशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज (जिसे एतदपश्चात आवेदक कहा गया है) से दस्तावेजों सहित प्राप्त आवेदन जिसमें संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति का आरोप लगाया गया था, के आधार पर दिनांक 27 जून, 2005 की अधिसूचना के द्वारा इंडोनेशिया, कोरिया गणराज्य, मलेशिया और चीनी ताईपेई (जिन्हें एतदपश्चात संबद्ध देश कहा गया है) से फुलीड्रान अथवा फुली ओरिएंटिड यार्न/स्पिन ड्रा यार्न/पोलिस्टर का फ्लैट यार्न (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के कथित पाटन की जांच शुरू की थी।

2. प्राधिकारी ने दिनांक 3 जुलाई, 2006 की अधिसूचना के द्वारा अपने प्रारंभिक जांच परिणाम अधिसूचित किए थे और राजस्व विभाग ने दिनांक 21 अगस्त, 2006 की अपनी अधिसूचना सं. 82/2006-सीमाशुल्क के द्वारा संबद्ध वस्तु पर प्राधिकारी द्वारा यथा अनुशंसित अनंतिम शुल्क लगाया था।

3. और चूँकि मै0 एच0के0 कार्पोरेशन, 19 एफ कुकडोंम बी/डी 60-1, 3केए, चुंगमुरु चुंग गु दियोल, कोरिया ने इसके साथ संलग्न कीमत वचनबद्धता के अगोपनीय अंश में विनिर्दिष्ट निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार उक्त नियमावली के नियम 15 के अनुसार एक स्वैच्छिक कीमत वचनबद्धता दी है।

4. निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त वचनबद्धता में विनिर्दिष्ट निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार उक्त नियमावली के नियम 15 के अनुसार एतद्वारा उक्त वचनबद्धता को स्वीकार करते हैं।

5. यह कीमत वचनबद्धता निम्नलिखित उत्पाद विनिर्देशनों के लिए और इस उत्पादक द्वारा केवल प्रत्यक्ष निर्यात के लिए नीचे दर्शायी गई कीमत पर वैध है:

उत्पाद विनिर्देशनवचनबद्धता कीमत

1. एफडीवाई 75/36 एसबीआर : एफओबी कीमत कोरिया गणराज्य : 1.40 अम. डालर प्रति किग्रा.
2. एफडीवाई 75/36 एसडी : एफओबी कीमत कोरिया गणराज्य : 1.46 अम. डालर प्रति किग्रा.
3. एफडीवाई 75/72 एसडी : एफओबी कीमत कोरिया गणराज्य : 1.46 अम. डालर प्रति किग्रा.
6. यदि निर्यातक भविष्य में किसी अन्य उत्पाद का निर्यात करने का इरादा रखता है तो उन पर प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणामों में यथा अनुशंसित सभी अन्य/अवशिष्ट शुल्क लगाए जाएंगे।
7. घरेलू कीमत और/अथवा प्रमुख कच्ची सामग्री की कीमतों में $\pm 5\%$ का उर्ध्वगामी या अधोगामी संशोधन होने की स्थिति में वचनबद्धता की उपर्युक्त कीमतों में संशोधन किया जाएगा। इसके साथ संलग्न वचनबद्धता शर्तों के अनुसार वचनबद्धता की निगरानी करने के लिए निर्यातकों पर अपनी घरेलू बिक्रियों और निर्यात बिक्रियों की आवधिक रिपोर्ट दाखिल करने का दायित्व होगा।
8. निर्यातक द्वारा दी गई कीमत वचनबद्धता को स्वीकार किये जाने पर मै0 एच.के. कार्पोरेशन के विरुद्ध जांच एतद्वारा आस्थगित की जाती है और प्राधिकारी ने प्राधिकारी द्वारा स्वीकार की गई वचनबद्धता के वैध रहने तक इस निर्यातक पर कोई निश्चयात्मक शुल्क लगाने की अनुशंसा नहीं की है।
9. कीमत वचनबद्धता उस अवधि के दौरान वैध रहेगी जिस अवधि में प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणामों में अनुशंसित उपाय लागू रहेगा। तथापि, प्राधिकारी इस वचनबद्धता को जारी रखने की जरूरत की समय-समय पर समीक्षा करेंगे।
10. इस वचनबद्धता की शर्तों के उल्लंघन के किसी मामले में प्राधिकारी इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार ऐसे उल्लंघन की तारीख से अंतिम शुल्क लगाने की अनुशंसा करेंगे।

अनुबंध-2मूल्यों के प्रति वचनबद्धता

यह वचनबद्धता मैसर्स एच. के. कोरपोरेशन, कार्यालय-19एफ, कुंकडोंग, 60-1, 3केए, चुंगमूरो चुंग गो, सियोल, कोरिया फोन नं: 82-775/8866/82-775-6455 के द्वारा मनोनित अधिकारी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। यह प्रस्ताव जमाखेरो के विरुद्ध, पूर्ण आहत और पूर्ण चमकदार सूत/कताई किया हुआ सूत/सामान्य सूत का निर्यात करने के विषय में एच. के. कोरपोरेशन, कोरिया गणराज्य, जांच के संबंध में है।

1. एच. के. कोरपोरेशन, कार्यालय-19एफ, कुंकडोंग, 60-1, 3केए, चुंगमूरो चुंग गो, सियोल, कोरिया को आगे "कम्पनी" के नाम से जाना जाएगा जिस मानोनित अधिकारी को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे आगे "अधिकारी" वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली, के नाम से जाना जाएगा। इस बचनबद्धता का वर्णन निचे किया गया है और उसमें प्रयोग हाने वाले परिशिष्ट ए, बी और सी का वर्णन भी संलग्न है और इस वचनबद्धता का जो भाग पूर्ण आहत और पूर्ण चमकदार सूत/कताई किया हुआ सूत/सामान्य सूत के निर्यात करने के विषय में हैं उसको "संबंधित देश" के नाम से जाना जाएगा जैसा कि अनुच्छेद 2 में परिभाषित किया गया है। सूत के जमाखेरी के विरुद्ध जांच करने के विषय में एक अधिसूचना 12 जून 2005 "अधिकारी" द्वारा किया गया कार्य है। इस संबंध में प्रारम्भिक जांच का कार्य "अधिकारी" द्वारा एक अधिसूचना दिनांक 3 जुलाई 2006 के अन्तर्गत किया गया।

2. यह बचनबद्धता सिर्फ उस माल के लिए है जो आरम्भिक अनुसंधान के अन्तर्गत "अधिकारी" के नाम में है। ये वस्तुएं इस प्रकार हैं :- पूर्ण आहत और पूर्ण चमकदार सूत/कताई किया हुआ सूत/सामान्य सूत।

(यदि आवश्यक है, तो इन वस्तुओं का पूर्ण विवरण वर्गीकरण और विशेषिकरण एच. एस. के पास हैं।)

विवरण: वर्तमान जांच में जो वस्तुएं ली गई हैं वह इस प्रकार हैं सभी प्रकार के पूर्ण आहत और पूर्ण चमकदार सूत/कताई किया हुआ

सूत/सामान्य सूत (बिना संरचना और बिना पी.ओ.वाई वाले) और कोई और अन्य सूत जो ग्राहक की शुल्कसूची 5402.43 द्वारा अनुकूल हों। उपरोक्त उत्पादनों को व्यवसायिक बाजार में सामान्यतः तौर पर "पूर्ण आहत सूत" के नाम से जाना जाएगा।

जिस माल का विवरण ऊपर किया गया है उसे "विषय-वस्तु" के नाम से जाना जाएगा।

3. कम्पनी इस बात पर सहमत है कि वह भारत को इसका निर्यात (जैसा वचनबद्धता में कहा गया है या जो मूल्य एफ. ओ. बी. द्वारा दिया गया, सी.आई.एफ, और निर्धारित दिशा में अनुरूप है) में दिया गया है, से नीचे के मूल्य पर नहीं करेगी। जैसा कि परिशिष्ट "ए" में अनुबंधित है।

- (i) यदि अंतिम जांच में ये पाया जाता है कि अन्य कोरियाई निर्यातकों का मूल्य परिशिष्ट ए में निर्धारित मूल्य से कम है तो इसी कम मूल्य को प्रचलित समझा जाएगा।

- (ii) विभिन्नता की यन्त्र रचना को तभी शामिल किया जाएगा यदि मूल रूप से कच्चे माल के घरेलू मूल्य और निर्यातक मूल्य में 5 प्रतिशत की कमी या वृद्धि पाई जाती है।

- (iii) निर्यात के संबंध में "संबंधित देश" से जमाखोरी के विरुद्ध शुल्क लिया जाना चाहिए।

4. कम्पनी इस बात पर भी सहमत है कि इस वचनबद्धता को बाहर कहीं भी प्रदर्शित नहीं किया जाए जिसमें शामिल हैं छूट द्वारा जहाज से माल को भारत भेजना, शाखा द्वारा, अभिकर्ता द्वारा और किसी अन्य कम्पनी द्वारा और किसी अन्य देश द्वारा भारत को प्रत्यक्ष रूप से माल भेजना आदि शामिल हैं। विषय-वस्तु को एक जहाज से उतार कर दूसरी जगह लंदान के संबंध में जो संबंधित देश के अलावा कम्पनी द्वारा किसी अन्य देश से आया हो, इस संबंध में भी वचनबद्धता की

स्वीकृति ली जाएगा और इसकी घोषण के विषय में अधिकारी की संतुष्टि करनी जरूरी है और घोषणा इस आशय के की जाएगी की इस माल को भारत निर्यात करना है।

5. कम्पनी इस बात पर भी सहमत है कि वह अधिकारी को इन कागजातों की प्रतिलिपि मुहैया कराएगी जैसा कि परिशिष्ट "बी" में वर्णीत है।
6. कम्पनी इस बात पर भी सहमत है कि वह अधिकारी सूचना और संबंधित कागजात भी मुहैया कराएगी जैसा कि परिशिष्ट "सी" में वर्णीत है।
7. कम्पनी इस बात पर भी सहमत है कि कोई भी नया उत्पादन, उसका आकार और मॉडल की बिक्री या उसका निर्यात जो भारत को किया जाना है, के निष्पादन से पहले यह कहना चाहती है कि वह विषय वस्तु अनुच्छेद 2 की परिभाषा की परिधी में आएगा, ना कि इस ब्रिकी की विज्ञप्ति को अधिकारी को बताने के संबंध में, जैसा कि विशेषतयः परिशिष्ट "ए" में वर्णीत किया गया है। यदि उचित मूल्य के निर्धारण के संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना अधिकारी द्वारा मांगी जाती है तो उसे मुहैया करायी जाएगी और नए उत्पादनों, उनके आकार और मॉडल को शामिल करने के संबंध में परिशिष्ट "ए" में संशोधन किया जा सकता है।

8. कम्पनी इस बात पर भी सहमत है कि, कम्पनी इस वचनबद्धता को अनुमति लेने के संबंध में इस वचनबद्धता को प्रदर्शित करेगी या चिपकाएगी, यदि अधिकारी द्वारा इसको आवश्यक समझा जाता है। किसी भी उत्पादन के संबंध में अधिकारी द्वारा सत्यापन मुहैया कराएगी। यदि किसी हालात में किसी घटना में कोई फेरबदल है तो कम्पनी मार्गदर्शन के लिए मनोनित अधिकारी की शरण में जा सकती है।
9. कम्पनी इस बात पर भी सहमत है कि मनोनित अधिकारी की सलाह पर उपरोक्त वचनबद्धता में इसके परिशिष्टों सहित पूरे या इसके किसी हिस्से में बलदाव कर सकती है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि हालातों में फेरबदल के संबंध में जो आखिरी प्रचलन समझा जाएगा और उसी को स्वीकार करना होगा। किसी हालातों के फेरबदल के संबंध में कम्पनी मार्गदर्शन के लिए मनोनित अधिकारी की शरण में जा सकती है।
10. कम्पनी इस बात पर भी सहमत है कि इस वचनबद्धता को उसी दिन से लागू समझा जाएगा जिस दिन से इसको स्वीकृति दी जाएगी और भारत सरकार की अधिसूचना की स्वीकृति मिलेगी। और उसी दिन से जो विषय वस्तु कम्पनी द्वारा निर्यात कि गई है या की जानी है, पर भी लागू होगी।

11. कम्पनी यह भी स्वीकार करती है कि "मनोनित अधिकारी" के अधिकारियों को यह हक होगा कि यदि अधिकारी वो किसी चीज से संतुष्ट नहीं है तो वो इस वचनबद्धता को समाप्त कर सकती है यदि:
- (i) इस वचनबद्धता का या उसके द्वारा किसी और संतुष्टि का उल्लंघन होता है।
 - (ii) यह बात भी विचारणीय है कि यदि वचनबद्धता की स्वीकृति के समय परिणामस्वरूप नई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो वचनबद्धता को स्वीकार नहीं किया जाएगा: और
 - (iii) यह भी विचारणीय है कि परिणामस्वरूप बदले हुए हालात, इस वचनबद्धता के उद्देश्य को लम्बे समय तक पूरा नहीं कर सकेगी।
12. कम्पनी यह भी स्वीकार करती है कि "मनोनित अधिकारी" के अधिकारी यदि इस वचनबद्धता को समाप्त करते हैं तो इस विषय वस्तु के संबंध में उनको एक प्राथमिक निर्णय लेना होगा जैसा कि अनुच्छेद 2 में वर्णीत है और जांच को आरम्भ करना होगा।

13. इस वचनबद्धता को वापिस लेने के संबंध में कम्पनी अधिकरी को अपने इस आशय के तथ्यों की सूचना लिखत रूप में वापसी के दिन 30 दिन पूर्व भेजेगी।
14. यह वचनबद्धता कम्पनी द्वारा नियत किए हुए और उनके उत्तराधिकारीयों पर भी लगू होगी।

कम्पनी साक्ष्यों के समक्ष अपनी सामूहिक मोहर लगाती है और इसको विधिवत अधिकृत अधिकारीयों द्वारा आज दिवस माह..... वर्ष को सत्यापित किया जाता है।

एच. के. कोरपोरेशन

गवाहन:

अधिकृत अधिकारीयों के हस्ताक्षर

गवाहों के नाम और शीर्षक

अधिकृत अधिकारीयों के नाम और शीर्षक

इस वचनबद्धता के साथ जो कागजात और परिशिष्ट ए, बी तथा सी संलग्न हैं वह मुद्रांकित गोपनीय है क्योंकि इसमें हमारे व्यवसाय से संबंधित कुछ अतिसंवेदनशील सूचना हैं।

परिशिष्ट "ए"

यह परिशिष्ट जो संलग्नित है वह इस वचनबद्धता का एक सम्पूर्णसमग्र हिस्सा है जिसको कि मैसर्स एच. के. कोरपोरेशन द्वारा मनोनित अधिकारी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग), भारत सरकार के समक्ष दिनांक (आवेदन की तिथि) को प्रस्तुत किया गया है।

इस वचनबद्धता के अनुच्छेद 3 के अनुसार, कम्पनी इस बात पर सहमत है कि वह माल को भारत में जो मूल्य इसमें निहित है से कम में ना तो बेचेगी और ना ही निर्यात करेगी। अनुबंधन इस प्रकार है:-

वचनबद्ध मूल्य

उत्पादन	उत्पादन	वचनबद्ध
वर्ग श्रेणी/आकार	विवरण	मूल्य
एफडीवाई	(पीसीएन:32बीटी), पूर्ण आहत सूत	US \$ xxx/KG
एफडीवाई	(पीसीएन:32एस आर), पूर्ण आहत सूत	US \$ xxx/KG
एफडीवाई	(पीसीएन:33एस आर), पूर्ण आहत सूत	US \$ xxx/KG

बिक्री की शर्त : एफ ओ बी

दिशा: एनएचएवीए एसएचईवीए

जो मूल्य उद्धृत है वह (प्रचलित मुद्रा समझौते की अवस्था और इकाई की माप यदि उपयुक्त है), (बिक्री की शर्त, उदाहरण नमूना, और यदि एफ ओ बी, सी आई एफ द्वारा उल्लेखित और दिशानिर्देश द्वारा) हैं। यह बिक्री मूल्य उसी माल पर लागू होगा जिस विषय वस्तु/माल को भारत में निर्यात करना है या (उसी समय या उसके बाद उस स्वीकृत दिनांक से जो अधिकारी द्वारा वचनबद्धता के अन्तर्गत स्वीकार की गई है)।

कम्पनी साक्ष्यों के समक्ष अपनी सामूहिक मोहर लगाती है और इसको विधिवत अधिकृत अधिकारीयों द्वारा आज दिवस माह..... वर्ष को सत्यापित किया जाता है।

एच. के. कोरपोरेशन

गवाहन:

अधिकृत अधिकारीयों के हस्ताक्षर

गवाहों के नाम और शीर्षक

अधिकृत अधिकारीयों के नाम और शीर्षक

परिशिष्ट "बी"

यह परिशिष्ट जो संलग्नित है वह इस वचनबद्धता का एक सम्पूर्णसमग्र हिस्सा है जिसको कि मैसर्स एच. के. कोरपोरेशन द्वारा मनोनित अधिकारी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग), भारत सरकार के समक्ष दिनांक (आवेदन की तिथि) को प्रस्तुत किया गया है।

इस वचनबद्धता के अनुच्छेद 5 के अनुसार, कम्पनी इस बात पर सहमत है कि वह विभाग को निम्नलिखित कागजात मुहैया कराएगी।

(i) यदि कम्पनी के घरेलू बाजार के मूल्यों में कोई बदलाव आता है तो अधिसूचना पत्र की एक प्रतिलिपि, यदि कोई है, बदले हुए मूल्यों की सूची के कागजात हर बार ग्राहक को भेज दिए जायेंगे। इन कागजातों को तुरन्त ही कम्पनी द्वारा फैक्स के माध्यम से जमोखरी विरुद्ध, सामान्य सचिवालय के कार्यालय और सहबद्ध कर्तव्य विभाग के ध्यानाकर्षण के लिए भेज दिए जायेंगे। ध्यानाकर्षण: श्री, जांच अधिकारी, वचनबद्धता का व्याख्या पत्र सहित। असली कागजात उस विभाग को अग्रप्रेषित कर दिए जायेंगे जिसके द्वारा माल की सुपुर्दगी होनी है, जिनका जिक्र खण्ड (iii) में नीचे किया गया है।

(ii) संशोधित परिशिष्ट "ए" को भी टेलीफैक्स द्वारा उसी समय उपरोक्त खण्ड (i) के अनुसार संचारित दिया जाएगा। संशोधन वचनबद्धता के संशोधित मूल्य जो गणना किया हुआ है, से परावर्तित हो सकता है (जिस पद्धति से वचनबद्ध मूल्यों में संशोधन किया गया है उसका

विवरण संशोधित परिशिष्ट "ए" में, बिक्री की शर्तों के पुनः-विवरण सहित स्पष्ट है, प्रचलित मुद्रा समझौता और इकाई की माप की आवश्यक है), वर्तमान मूल्य वचनबद्धता में निर्धारित मूल्य को प्रभावित करेगा जैसा कि परिशिष्ट "ए" में वर्णीत है। असली कागजात उस विभाग को अग्रप्रेषित कर दिए जायेंगे जिसके द्वारा कागजातों की सुपुर्दगी होनी है, जिन कागजातों को जिक्र उपरोक्त खण्ड (i) में ऊपर दिया गया है। और

- (iii) (अन्य कागजातों का भी प्रबंध करा दिया जाएगा जब उनके द्वारा उन कागजातों को हमें मुहैया करा दिया जाएगा)। यह कागजात एक व्याख्या पत्र के साथ जिसमें वचनबद्धता का जिक्र है, अग्रप्रेषित कर दिये जायेंगे।

मनोनित अधिकारी, जमाखोरी विरुद्ध सामान्य सचिवालय कार्यालय और सहबद्ध कर्तव्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली, भारत।

कम्पनी साक्ष्यों के समक्ष अपनी सामूहिक मोहर लगाती है और इसको विधिवत अधिकृत अधिकारीयों द्वारा आज दिवस माह..... वर्ष को सत्यापित किया जाता है।

एच. के. कोरपोरशन

गवाहन:

अधिकृत अधिकारीयों के हस्ताक्षर

गवाहों के नाम और शीर्षक

अधिकृत अधिकारीयों के नाम और शीर्षक

परिशिष्ट "सी"

यह परिशिष्ट जो संलग्नित है वह इस वचनबद्धता का एक सम्पूर्णसमग्र हिस्सा है जिसको कि मैसर्स एच. के. कोरपोरेशन द्वारा मनोनित अधिकारी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग), भारत सरकार के समक्ष दिनांक (आवेदन की तिथि) को प्रस्तुत किया गया है।

इस वचनबद्धता के अनुच्छेद 6 के अनुसार, कम्पनी इस बात पर सहमत है कि वह मनोनित अधिकारी को बीजक (बिल) और/या व्यवसायिक बीजक, प्रत्येक माल भेजने के संबंध में, अधिकारियों की आवश्यकता अनुसार मुहैया करायेगी तथा माल के विवरण की सूचना निचे दी गई है:

- ग्राहक आदेश नम्बर और आदेश की दिनांक।
- उत्पादन (वर्ग/श्रेणी/नम्बर/आकार इत्यादि)।
- उत्पादन का विवरण यदि उपयुक्त विवरण की आवश्यकता का मिलान विषय वस्तु के संबंध में वचनबद्धता मूल्य परिशिष्ट "ए" में वर्णीत है।
- बिक्री के नियम व शर्तें।
- उत्पादन की गुणवत्ता (इकाई माप) प्रत्येक के लिए (वर्ग/श्रेणी/नम्बर/आकार इत्यादि) और
- उत्पादन का इकाई मूल्य (मुद्रांक समझौते में) प्रत्येक के लिए (वर्ग/श्रेणी/नम्बर/आकार इत्यादि)।

इसके अलावा, कम्पनी प्रत्येक कागजात के प्रति स्पष्टीकरण देने के लिए सहमत है।

यह मूल्य मैसर्स एच. के. कोरपोरेशन की वर्तमान वचनबद्धता के मुताबिक हैं जिसको मनोनित अधिकारी और सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क, भारत के अधिकारियों द्वारा स्वीकृत है भारत सरकार की स्वीकृति की दिनांक के अनुसार हैं।

कम्पनी साक्ष्यों के समक्ष अपनी सामूहिक मोहर लगाती है और इसको विधिवत अधिकृत अधिकारियों द्वारा आज दिवस माह..... वर्ष को सत्यापित किया जाता है।

एच. के. कोरपोरेशन

गवाहन:

अधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षर

गवाहों के नाम और शीर्षक

अधिकृत अधिकारियों के नाम और शीर्षक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2006

Final Findings

Subject: Antidumping investigation concerning imports of All Fully Drawn or Fully Oriented Yarn/Spin Draw Yarn/Flat Yarn from Indonesia, Korea, Malaysia and Taiwan

NO.14/3/2005-DGAD: - Whereas having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, (hereinafter referred to as the Rules) thereof, the Designated Authority (hereinafter referred to as Authority), initiated an investigation into the alleged dumping of Fully Drawn or Fully Oriented Yarn / Spin Draw Yarn / Flat Yarn of Polyester (herein after referred to as subject goods) from Indonesia, Republic of Korea, Malaysia and Chinese-Taipei (herein after referred to as subject countries), vide notification dated 27th June 2005, on the basis of a fully documented application received from the Association of Synthetic Fibre Industries (hereinafter referred to as the Applicant) on behalf of domestic producers namely M/s Central India Polyesters Ltd., M/s Century Enka Ltd., M/s Garden Silk Mills Ltd., M/s Nova Petrochemicals Ltd., M/s Recron Synthetics Ltd. and M/s Welspun Syntex Ltd., alleging dumping of the subject goods from the subject countries and consequent injury caused to the domestic industry.

2. The Authority notified its preliminary findings vide notification dated 3rd July 2006 and the Department of Revenue, vide its Notification No 82/2006-Customs dated 21st August 2006, imposed provisional duty on the subject goods as recommended by the Authority.

3. In terms of Rule 17 (1) of the Rules, the Central Government has extended the time period for completion of this investigation till 26th December 2006.

A. PROCEDURE

4. The procedure described below has been followed with regard to the investigation after notification of the preliminary findings by the Authority:

i) The Designated Authority sent copies of preliminary finding dated 27th April 2006 to all interested parties to this investigation, including the Embassy of the subject country in India, cooperating exporters from the subject country, domestic industry and the importers participating in the investigation requesting them to make their views known in writing within 40 days of the notification of the preliminary findings.

- ii) The comments of the interested parties in response to the preliminary findings have been taken on record and the Authority has examined the issues raised therein in this disclosure statement.
- iii) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties;
- iv) For the sake brevity the comments of various interested parties and issues raised prior to the preliminary findings and addressed therein have not been repeated in this disclosure statement.
- v) The Authority held a public hearing on 18.08.2006 to provide an opportunity to all interested parties to present their views. The oral submissions made by the parties during the public hearing reproduced in writing have been taken on record for the purpose of this investigation.
- vi) The Authority has examined the confidentiality claims of various interested parties in respect of the data submitted by them. The information, which is by nature confidential or which has been provided on a confidential basis by the interested parties' alongwith non-confidential summary thereof, has been treated confidential. *** in this disclosure represents information furnished by the petitioner on confidential basis and so considered by Authority under the Rules;
- vii) Investigation was carried out for the period starting from 1st January 2004 to 31st December 2004 (12 months) i.e. the period of investigation (POI). The examination of trends in the context of injury analysis covered the period from April 2001 - March 2002, April 2002 – March 2003 and April 2003 – March 2004 and the POI.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION, LIKE ARTICLE AND DOMESTIC INDUSTRY:

B.1 PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

5. The product involved in the present investigation is All Fully Drawn or Fully Oriented Yarn / Spin Draw Yarn / Flat Yarn of Polyester (non-textured and non-POY) and other yarns conforming to the tariff description of customs heading 5402.43 (hereinafter also referred to as subject goods). The above-mentioned product in commercial market parlance is generally known as 'Fully Drawn Yarn'. The subject goods are used for manufacture of apparel / household textiles, and other industrial textiles. Technical specifications of the subject goods are defined in terms of their deniers, tenacities, lustres, colours (like semi dull, bright, super bright, full dull, Dope dyed), cross section and shrinkage. During the course of the investigation it has been noticed that significant quantity of the subject goods have also been imported under customs heading 5402.42. Therefore, for the purpose of this investigation the goods imported under customs heading 5402.43 and 5402.42 have been considered. However, these classifications are indicative only and are no way binding on the scope of this investigation.

6. The exporters from the Republic of Korea have argued that a number of varieties of FDY were not manufactured and sold in India during the POI and

therefore, those grades may be excluded from the Product under consideration. It has been further argued that certain other grades were produced in India in insignificant quantities and therefore, may be excluded for lack of meaningful injury determination and, perhaps, limited market.

7. The domestic industry has argued that the product under consideration is fully drawn yarn and the exporters have exported the subject goods to India during the period of investigation. Therefore, the duties are liable to be imposed for the product under consideration without any exclusion.

8. The Authority notes that the product under consideration is the product that is allegedly being dumped in the importing country by the producers/exporters from the exporting country which injures a like product produced by the domestic industry in the importing country. Therefore, the issue to be decided is whether the domestic industry produces a like article that is being injured by the dumping of the product being investigated.

9. The applicants have claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods. The exporters from the Republic of Korea has argued that the Authority ought to appreciate that there are some differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the imports and the domestically produced Subject Goods. It has been argued that the Authority also ought to note that the market segments served are different. However, no material fact has been placed before the Authority to demonstrate that the goods exported from the subject countries and produced by the domestic industry are not technically and commercially substitutable.

10. As noted in the preliminary findings, the All India Yarn Importers Association and Federation of Indian Art Silk & Weaving Industry have argued that the petitioners have not excluded any yarn of the nomenclature, quality and type that are not produced by the domestic industry. It has also been argued that no meaningful segregation of the data has been done. A huge variety of yarns like polyester high tenacity yarns above 4.5 denier, polyester flame retardant yarns, Teflon treated polyester yarn, is imported which are not manufactured in India. The associations have further argued that the applicants have not differentiated between different processes and cost effectiveness associated with them as the production of this product may start from PTA, MEG, Chips, POY/LOY stages and the cost structure would be different for different routes. It has been further argued that comparison of the subject goods without factoring in aspects of quality and technology and without segregating the data of imports and domestic production would lead to highly skewed results. However, these arguments have not been supported by any data or questionnaire response submissions by these associations. The Authority notes that the comparative advantage of cost and prices are the matter of investigation and determination and has no bearing on the like article determination.

11. As far as the issue of determination of like article for the purpose of determination of the domestic industry and injury determination is concerned, the Authority notes that the starting point of manufacturing the subject goods is the basic polymerization process involving PTA or TPA and MEG or EG. Certain production units start from the basic polymerization stage or buy polyester chips to produce the subject goods using spinning and drawing process. The process of manufacturing is pretty standard and variation in quality and grades are achieved by changing and controlling the spinning and drawing parameters. The Authority notes that the domestic industry in India uses similar production process and the goods manufactured by the domestic industry and exported from the subject countries have similar physical and chemical properties. There is no significant difference in the dumped goods and the product under consideration manufactured by the domestic industry. The imported goods are used by the user industry interchangeably with the goods produced by the domestic industry. The subject goods produced by the domestic industry and produced by the subject countries, being technically and commercially substitutable, are 'like articles' under the Anti Dumping Rules. Therefore, the Authority holds that for the purpose of this investigation, the product under investigation covers all types and grades of All Fully Drawn or Fully Oriented Yarn / Spin Draw Yarn / Flat Yarn of Polyester (non-textured and non-POY) and the subject goods produced by the applicants in India are 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

C. DOMESTIC INDUSTRY

12. The application has been filed by M/s Association of Synthetic Fibre Industries, New Delhi along with the following producers of subject goods in India:

- (i) M/s Central India Polyesters Ltd., Nagpur, Maharashtra.
- (ii) M/s Century Enka Ltd., Raigad, Maharashtra.
- (iii) M/s Garden Silk Mills Ltd., Surat, Gujarat.
- (iv) M/s Nova Petrochemicals Ltd., Ahmedabad, Gujarat.
- (v) M/s Recron Synthetics Ltd., Allahabad, Uttar Pradesh.
- (vi) M/s Welspun Syntex Ltd., Thane, Maharashtra.

13. The Authority notes that there are three other known domestic producers of the subject goods in India. However, collective production of the aforesaid producers constitutes a major proportion of the total domestic production of the domestic like article. Accordingly, in the preliminary findings the Authority determined that aforesaid applicants satisfy the criteria of standing to file the application on behalf of the domestic industry in terms of Rule 5(3)(a) and represent the domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) of the Rules supra. However, the interested parties in their submissions have argued that the Authority must first decide whether it will include or exclude producers that may also be importers from the scope of domestic industry. It is only then that the domestic industry standing of applicants may be determined. It has been argued that there is no material in the Public File to show that such an exercise has been carried out though there are other producers of the subject goods in India. It is also not known whether the Authority has taken up the issues of captive consumption, or imports by affiliated group companies with the Applicants.

14. The domestic industry has argued that it is not open for the interested parties to raise all kinds of issues at all points of time. The interested parties can offer their comments on the issues relating to initiation at that stage itself when specific time was granted in the initiation notification itself. By commenting on the assessment of the Authority with respect to the initiation after few months, the interested parties have merely attempted to impede the investigation.

15. The Authority notes that the investigation was initiated after detailed examination of the standing of the domestic producers who have filed this application and taking into account their collective output, relationship status and volume of imports made by one of the applicants. The interested parties have not placed any material fact before the Authority in respect of the issues raised by them regarding the standing of the applicants. Therefore, the Authority holds that the applicants meet the criteria of standing as laid down under the Rules and constitute the domestic industry for the purpose of this investigation in terms of Rule 2(b) of the Antidumping Rules.

D. Other issues raised by the interested parties

D.1 Importers

16. The Authority notes that none of the importers of the subject goods have filed any questionnaire response. All India Yarn Importers Association and Federation of Indian Art Silk & Weaving Industry had filed certain submissions without any substantiation of the claims made therein. These parties were also asked to substantiate their claim that the importers association is an interested party within the meaning of Rule 2(c) by producing list of members and evidence that majority of the members of this association are importers of the subject goods. However, these associations have failed to file any response. Therefore, for the purpose of this investigation all importers and their associations have been treated as non-cooperative. Notwithstanding this their views were taken on record in the preliminary findings and addressed to the extent they were relevant. These parties have essentially claimed that there is a significant variation between the grades and quality of material produced by the domestic industry and the exporters from the subject countries and certain grades which are not manufactured in India should be excluded. The Authority has examined this issue for determination of product under consideration and like article and hold that the goods exported from the subject countries are like article to the goods manufactured by the domestic industry in view of technical and commercial substitutability of the products.

D.2 Exporters

17. The exporters from the subject countries participating in this investigation, in their post preliminary finding submissions, have inter alia raised the following issues.

18. The Korean exporters have argued that the Authority has not notified the extension of time beyond the 12 months period for completion of the investigation and without such official intimation the Investigations have lapsed in law on 26th June, 2006 as there can be no lawful Investigations without official notice.

19. The domestic Industry, quoting the decision of the Hon'ble Supreme Court in *Designated Authority Vs. Haldor Topsoe 2000 (120) E.L.T. 11 (S.C.)*, has argued that there is no requirement under the law that the Authority is required to give a notice of extension of time of the period for investigation.
20. The Authority notes that Rule 17 of the Antidumping Rules provides that the Authority shall, within one year from the date of initiation of an investigation, determine as to whether or not the article under investigation is being dumped in India and submit to the Central Government its final findings. The said Rule also provides that the Central Government may, in its discretion in special circumstances, extend further the aforesaid period of one year by six months. Neither the Rule nor the Agreement contemplates notification of such extension to any interested party as has been argued by these interested parties. The Hon'ble Supreme Court has held that this decision in question is an administrative decision based on exigencies of the case. Therefore, the arguments of the interested parties in this respect are not valid.
21. The exporters and other interested parties have also argued that there is gross inadequacy and inaccuracy in the non-confidential information furnished by the Applicant and the information furnished is not consistent with the requirements of Indian law. It has been argued that the Applicants have relied on constructed normal value in the subject countries based on estimates of alleged dumping but has not disclosed these estimates which, by definition, cannot be proprietary or business sensitive to the Applicant. It has also been argued that the trade data relied on indicates an adverse volume effect appears to be unreliable. The exporters have further argued that the degree of confidentiality granted to the Applicant is unwarranted as the applicants have withhold information which should otherwise be available in the public domain and the Applicants have not filed their costing information in indexed form for each Producer.
22. The domestic industry in its various submissions has raised the issue of timely submission of information by the exporters from the subject countries. They have argued that these exporters have not raised their objections to various issues relating to the initiation of the investigation within the stipulated time limits and therefore, subsequent objections on these issues should not be entertained. They have also argued that the responses filed by these exporters were incomplete and subsequent submissions by these exporters have been filed very late i.e. closer to the preliminary findings. Therefore, they should be declared non-cooperative. The domestic industry has also raised several issues regarding inadequate non-confidential disclosure by the responding exporters.
23. The Authority has examined the arguments of the exporters, importers, domestic industry and other interested parties on the issues related to initiation and confidentiality. The Authority notes that antidumping investigation is a continuous process and based on the information that flows during the course of the investigation the Authority has to make its determination. The Authority also notes that in the Guatemala – Mexico Cement case the Panel held that *it is however the sufficiency of the evidence, and not its adequacy and accuracy, per se, which represents the legal standard to be applied in the case of a*

determination whether to initiate an investigation. The Panel in the said dispute held that *an anti-dumping investigation is a process where certainty on the existence of all the elements necessary in order to adopt a measure is reached gradually as the investigation moves forward. However, the evidence must be such that an unbiased and objective investigating authority could determine that there was sufficient evidence of dumping within the meaning of Article 2 to justify initiation of an investigation.* In the instant case sufficient evidence was placed by the applicants indicating prima facie existence of dumping, injury and causal link. The investigation was initiated by the Authority after due examination of various aspects of the case including the adequacy and accuracy of data reasonably available to the applicants and submitted by them in the application. Therefore, the arguments of the interested parties in this regard are not valid.

24. As far as the confidentiality and insufficient non-confidential disclosure of information by the parties to the investigation is concerned, the issues raised have been examined. The Authority notes that to the extent possible and practicable the confidentiality claims of various parties submitting the information have been examined and confidentiality claims admitted on the basis of nature of information provided by the parties.

E. DETERMINATION OF DUMPING AND DUMPING MARGIN

25. The Authority note that the following exporters of the subject goods from the subject countries filed their questionnaire responses in this matter:

1. M/s P.T. Mutu Gading Tekstil (Indonesia)
2. M/s H.K. Corporation (Korea)
3. M/s Hyosung Corporation (Korea)
4. M/s Saehan Industry (Korea)
5. M/s Huvis Corporation (Korea)
6. M/s Hualon Corporation (Malaysia)
7. M/s Nan Ya Plastics Corporation (Chinese Taipei)
8. M/s China Man-Made Fiber Corporation, (Chinese Taipei)

26. However, after the preliminary findings were issued by the Authority, M/s China Man-Made Fibre Corporation, Chinese Taipei has not responded to any of the correspondences from the Authority and did not offer itself for verification. Accordingly, this exporter has been treated as non-cooperative for the purpose of this investigation.

27. The Authority also notes that M/s H. K. Corporation, Republic of Korea has offered a voluntary price undertaking and requested for suspension of the investigation against them in terms of Rule 15 of the AD Rules. The Authority has accepted the price undertaking in terms of Rule 15 of the Rules and the same is being notified in terms of Rule 15(4) of the Rules as Annexure -A to this finding.

28. The data submitted by other cooperating exporters to this investigation were verified in accordance with the Rules and reports of such verification carried out by the Authority were made available to the exporters for their comments. The dumping margins in respect of these exporters have been worked out based

on the verified data taking into account the comments of the exporters to the verification reports to the extent they are relevant and valid.

29. The domestic industry, in its post preliminary finding submissions, has raised the issue of export price of the cooperative exporters and it has been submitted that the Authority should not have considered the proceeds claimed to have been realized by the exporters irrespective of whether the same have been received through proper banking channel on account of the concerned importer who has bought the goods. It has been argued that certain export proceeds realized through TT transactions should not be considered for the purpose of computation of export price and for the purpose of export price determination the export price declared to the customs Authorities in India should be taken into account. The domestic industry, in its post disclosure submissions, has reiterated its arguments in this respect.

30. The exporters in their submissions have *inter alia* argued that anti-dumping discipline is not a substitute for the Customs Act or an instrument of enforcement of the Customs Act and thus cannot be invoked for calculation of the export price for the revenue fraud, if any, by the importer. It has been argued that there is no provision in the ADA or the Rules for adjustment of Export Price or to exclude any portion of the payment(s) received by the Exporter in respect of the concerned transaction save in accordance with the Rules. Neither the ADA nor the Rules stipulate that there be only a single payment received for an export transaction. It has also been argued that even if the export price is to be constructed under Article 2.3 of ADA it has to be proved that there is some kind of association or compensatory arrangement between the exporter and importer or a third party, and in such a situation the export price has to be constructed based on the price at which the goods are first resold to an independent buyer. Therefore, adoption of any other price or method for determination of export price in the light of the arguments of the domestic industry will be contrary to the Agreement and Section 9A(b) of the Act. Therefore, all payments that an exporter can satisfy to the Authority that it received in respect of an export transaction must be included in determination of its export price for the concerned transaction. It has been further argued that non-cooperation by importers in an antidumping investigation cannot be a ground to presume that the invoices are over or under invoiced. Therefore, the authority cannot reject the export prices furnished by the exporters for non-cooperation by importers on whom the exporters have no control. If an investigating authority were to insist cooperation by the importer for accepting a response filed by an exporter, then, it would put an unreasonable burden on the exporter. Such a proposition is unheard of in antidumping investigations around the world unless in a situation where the importer and exporter are related. Therefore, the exporters have argued that domestic industry's claim is untenable and is liable to be rejected.

31. The Authority notes that the goods have been exported by the exporters in the subject countries directly as well as through unrelated traders in different countries. The goods are directly shipped to India and invoiced to the trader from whom the orders have been received. The payment is also received from these traders. The exporters directly ship the goods to India and all shipping documents are prepared by the exporter. However, the producer/exporters do

not seem to have any idea about the transactions between the traders and the actual importer in India. The exporters have argued that their price to the traders for the goods actually shipped to India is their export price as per the well established practices in several jurisdictions like USA and the European Union on the subject. It has been argued that the verified price of the producer/exporters to any trader that may be re-exporting to the investigating country, even if such trader has not cooperated, are treated as the concerned producer/exporter's export price provided that the concerned company can satisfy the Authority that the goods against the concerned transaction were in fact exported to the investigating country. The trader will in any case face the adverse consequences of non-cooperation in such a situation. It has been submitted that as per the EU Regulation the export price has been defined as the "price actually paid or payable for the product when sold for exports from the exporting country to the Community". The jurisprudence developed and applied in these countries permits use of the first price charged by the producer to a local trading company as the export price so long as the producer knew of the ultimate destination of the shipment, since such price of the producer was made for exports to the importing country. It has also been argued that the practices in these jurisprudences require the producers/exporters in the exporting country to report all transactions for which they have knowledge of having been exported to these countries. Therefore, it has been argued that the transaction prices reported by the exporters in respect of their direct as well as indirect sales through traders should be accepted as their export prices. The unrelated traders however, may face adverse inference due to their non-cooperation as the producers/exporters do not have any control over them to file the responses in respect of transactions made through them.

32. The Authority has examined the issues raised by the domestic industry in its various submissions, including their post disclosure comments. As far as the issue of transaction value of the exports and mode of payment are concerned, neither the ADA nor the Indian antidumping Rules provide any provision to deal with the subject. There is no evidence on record to prove that the producer/exporters and the traders/importers involved in this case are related and have compensatory arrangement to resort to construction of the export price. Even if a construction is to be resorted to in terms of Section 9A(b) of the Act, it has to be based on the first resale price in the importing country market for which no data has been provided by any interested party. Therefore, the Authority has proceeded with the determination of export price based on the price actually realized by the producer/exporter as per their records.

33. As far as the issue of selling prices to the traders and determination of export price is concerned, the Authority notes that the jurisdiction developed and followed by the major users clearly requires the exporters to report all such transaction and the export price for the exporter/producer is determined based on this data and non-cooperative trader gets an adverse finding. However, examination of the transaction-wise data of the exporters does show significant difference in price structure between the direct sales prices and sales through traders but without any definite pattern. Therefore, all export sales have been considered to determine the export prices for individual exporters

E.2 Methodology of determination

34. The Authority notes that the Hon'ble Supreme Court of India, in the Civil Appeal No. 1294 of 2001, M/s Reliance Industries Ltd Vs Designated Authority & Others, has held that normal value is not exporter specific but exporting country specific.

35. In their post disclosure submissions the domestic industry has argued that that the Authority has proceeded to determine a single country specific normal value on the basis of wrong interpretation of the Supreme Court Judgment in RIL matter. It has been argued that in the Haldor Topsoe case, the Hon'ble Supreme Court's decision was based on the non-cooperation by the exporter seeking determination of his individual normal value and in the present case the Designated Authority has completely misinterpreted the ratio of Reliance case. It has been argued that Hon'ble Supreme Court in the RIL case has simply reiterated the ratio of the Haldor Topsoe case for instances of non-cooperation. Therefore, a plain reading of the RIL judgment would indicate that the observations that normal value is country-specific is correct except in cases where the exporter has cooperated and provided the Designated Authority with full information. The exporters from Korea RP have also argued that that there is no practice of single NV for the exporting country and such a calculation may amount to denial of market access to the exporting country leading to grave consequences.

36. However, the Authority notes that the Supreme Court Judgment cited above does not specifying the situations in which such determination can be made as has been argued by the domestic industry. The Authority also moved a review application before the Hon'ble Court seeking clarification and revision of this judgment. However, the review application has since been rejected by the Hon'ble Court. Therefore, the Authority is of the view that this Judgment of the Hon'ble Court has clearly cast an obligation on the Authority to determine a single country specific Normal Value. Accordingly, the Authority has determined single country specific weighted average Normal value.

37. Normal values of individual Product types (PCNs) have been determined first for the individual cooperating exporters and then a single weighted average normal value has been worked out for each of the product types of the product under consideration at the PCN level for the exporting country as a whole based on the normal values determined for the cooperating exporters. These country specific normal values at the PCN levels have been compared with the export price for the corresponding PCNs of the individual exporters to determine individual dumping margins at PCN levels of the exporters. The weighted

average dumping margin for each exporter has been calculated on the basis of the PCN level dumping margins for that exporter.

38. For the purpose of determination of dumping margin of non-cooperating exporters from the subject countries, weighted average normal value of the cooperating exporters have been compared with the lowest export price of the cooperative exporters in the absence of product type wise export price for non-cooperative exporters.

E.1 Indonesia

a) Normal Values

39. In response to the initiation notification only one exporter of the subject goods from Indonesia i.e., M/s P.T. Mutu Gading Tekstil, Indonesia has furnished the questionnaire response. On the basis of the data submitted by this exporter and verified by the Authority, Normal Value for this cooperating exporter has been determined. Since there is no other cooperating exporter from this country the Normal values determined for this exporter at the PCN-level has been adopted as the normal value for Indonesia as a whole as per the Hon'ble Supreme Court of India judgment quoted above

40. The data submitted by M/s P.T. Mutu Gading Tekstil, Indonesia was verified. This producer-exporter has reported about ***** MT of sales of the subject goods in its domestic market during the POI covering three product types. The sales are to unrelated buyers in the domestic market. The exporter has claimed adjustments towards inland freight and credit cost on account of credit period allowed to the buyers. The net ex-works selling price of individual product types were subjected to ordinary course of trade test on the basis of verified cost of production and accordingly the PCN level Normal values have been determined. The weighted average Normal values at ex-works level worked out to US\$****/ Kg.

41. In the absence of any other data and cooperation from other exporters in Indonesia, the above normal values have been adopted for all exporters in Indonesia in compliance of the Hon'ble Supreme Court orders quoted above.

b) Export Prices and Dumping margin

i) M/s P.T. Mutu Gading Tekstil, Indonesia

42. As per the response filed, this exporter sold ***** MT of the subject good in the Indian market during the POI. Only 4 transactions are on CIF/CFR basis and rest of the transactions are on FOB basis. Inland transport, ocean freight, insurance and credit cost as verified has been deducted from the invoice price to arrive at net ex-works export price for individual PCNs.

43. On the basis of the normal values and export prices determined at PCN level for this exporter the dumping margins for individual PCNs and weighted average dumping margin for this exporter have been worked out. Accordingly, weighted average dumping margin for this exporter works out to US\$****/Kg (1.29%). Thus the dumping margin for this exporter has been found to be de minimis.

ii) All Others

44. Since no response has been received from other producer/exporters in Indonesia the export price for others have been determined based on the lowest transaction price of the cooperating exporter after adjusting the same for direct selling expenses as per the cooperating exporters data. Accordingly, average net ex-works export price for the non-cooperating exporters from Indonesia has been determined as US\$****per Kg.

45. The weighted average normal value determined for the cooperating exporter at the ex-factory level has been compared with the ex-factory export price determined for the non-cooperating exporters. Accordingly, weighted average dumping margin for all non-cooperating exporters has been worked out as to US\$**** per Kg (39%).

E.2 Korea RP

46. It may be noted that in response to the initiation notification the following exporters from Korea RP have filed their questionnaire responses.

1. M/s H.K. Corporation (Korea)
2. M/s Hyosung Corporation (Korea)
3. M/s Saehan Industry (Korea)
4. M/s Huvis Corporation (Korea)

47. As noted earlier M/s H.K Corporation has made an offer of price undertaking and requested for suspension of the investigation in terms of Rule 15 of the Antidumping Rules. The questionnaire responses filed by the other exporters from the subject country have been verified to the extent possible and based on these responses dumping margins have been determined as follows:

a) Normal value

i) M/s Hyosung Corporation, Korea RP

48. The company has sold *****MT of the product concerned in its domestic market during the POI covering a large number of PCNs. However, the company has exported only certain PCNs to India during the POI. Therefore, for the

purpose of like to like comparison the said PCNs, sold in domestic market, have been considered. Most of the domestic sales of the company are on ex-factory basis therefore, the exporter has claimed adjustments only towards credit expenses against domestic transactions, bank charges and packing costs and inland freight expenses, wherever applicable, and an adjustment towards warranty claim expenses against certain transactions. The domestic sales transactions of the PCNs identified as above were subjected to ordinary course of trade test based on their respective verified cost of production and on the basis of the domestic selling prices the Normal value of the individual PCNs have been worked out.

ii) M/s Saehan Industry, Korea RP

49. The company has sold ***** MT of the product concerned in its domestic market during the POI covering a large number of PCNs. However, the company has exported FDY covered under only certain product codes to India during the POI. Therefore, for the purpose of like to like comparison the said PCNs, sold in domestic market, have been considered. The domestic sales are to unrelated buyers including end users and traders except one related customer M/s Toray Saehan. However, the sale to the related customer is only *** MT, which is insignificant in total domestic sales volume.

50. The domestic sales are mostly on delivered basis though few transactions are on ex-works basis. The payments have been realized through local LC or through open account system maintained by the Company for its regular customers. Adjustments towards inland freight, credit expenses against domestic transactions and packing costs have been allowed to determine the normal value at ex-factory level. The domestic sales transactions of the PCNs identified as above were subjected to ordinary course of trade test based on their respective verified cost of production and on the basis of the domestic selling prices the Normal value of the individual PCNs have been worked out.

III) M/s Huvis Corporation, Korea RP

51. As per records of the company and as per the information supplied by them in various appendices Huvis had ***** domestic sales transactions of subject goods with a total quantity of ***** MT covering several PCNs. However, only FDY covered under certain PCNs have been exported to India during the POI. Therefore, for the purpose of fair comparison the normal value is required to be determined based on these PCNs. The exporter has claimed adjustments towards inland freight, credit expenses against domestic transactions, bank charges and packing costs. Since there is no difference between the domestic and export packing, total packing expenses have been allocated to the total production and average packing expenses worked out to ***** per Kg. Domestic sales of the above PCNs were subjected to ordinary course of trade test on the

basis of the cost of production of individual PCNs and the Normal values of individual PCNs have been determined at ex-works level.

iv) Normal Value: Korea RP

52. In accordance with the Hon'ble Supreme Court judgment quoted above a single normal value has been worked out for Korea as a whole as the weighted average of the individual Normal values determined above. On the basis of the normal values determined for the cooperating exporters at PCN level weighted average normal values have been worked out for all exporters in Korea at PCN level.

b) Export Prices and Dumping Margins:

i) M/s Hyosung Corporation, Korea RP

53. The company has exported ***** MT of the subject goods to India during the POI. However, only **** MTs have been exported by them directly to India and rest of the transactions is through traders in Singapore, Hong Kong, and Korea. The direct exports to India and through traders in Singapore and Hong Kong are on LC at Sight terms. The transactions between Hyosung and the Korean trader are on TT term. The traders involved have not filed any response in respect of the goods exported by Housung through them and therefore, their actual export prices of these transactions are not known. However, for the purpose of determination of export price for Hyosung their prices have been considered and the traders would face adverse facts available and attract residual dumping margin.

54. The export transactions to India are in FOB/CIF and CNF terms adjustments towards inland and ocean freight, credit expenses, overseas insurance expenses; handling fee and bank expenses, packing cost for export shipments and drawback on the export transactions, have been allowed to arrive at the net ex-factory export prices for individual PCNs.

55. On the basis of the above ex-works weighted average normal values for Korea RP and net ex-works export prices determined at PCN levels for this exporter the dumping margins for this exporter has been worked out at PCN level. Accordingly, weighted average dumping margin for this exporter works out to US\$*****/Kg (17.42%)

ii) M/s Saehan Industry, Korea RP

56. The company has exported ***** MT of the subject goods to India during the POI. However, only **** MT have been exported by them directly to India and rest of the transactions is through traders in Singapore, Hong Kong, and Korea.

The direct exports to India and through traders in Singapore and Hong Kong are on LC terms. The transactions between Saehan and the Korean trader are against local LC. The traders involved have not filed any response in respect of the goods exported by Saehan through them and therefore, their actual export prices of these transactions are not known. However, for the purpose of determination of export price for Hyosung their prices have been considered and the traders would face adverse facts available and attract residual dumping margin.

57. The export transactions to India are in FOB and CIF terms. The exporter has also paid commission on certain transactions. Accordingly, adjustments towards, inland and ocean freight, insurance expenses, handling fee and bank expenses documents, packing cost for export shipments, credit expenses, and duty drawback has been allowed as verified. Accordingly, the average net ex-works export price for individual PCNs has been worked out.

58. On the basis of the above ex-works weighted average normal values for Korea RP and net ex-works export prices determined at PCN levels for this exporter the dumping margin for this exporter has been worked out PCN level. Accordingly, weighted average dumping margin for this exporter works out to US\$**** (4.2%).

iii) **M/s Huvis Corporation, Korea RP**

59. Records of the company shows that they have exported **** MT of Subject Goods to India during the investigation period covering several PCNs. Out of the total exports to India, **** MT was direct exports to India and exports are against LC at sight. Balance exports are through traders in Korea and third countries. The goods against these transactions were directly shipped by the producer/exporter on the basis of instructions of their buyers/traders for which payment has been received by them from these traders against LC at sight except for the Korean trader to whom the goods are supplied on approval basis and the payment is received against their open accounts. The traders involved have not filed any response in respect of the goods exported by Saehan through them and therefore, their actual export prices of these transactions are not known. However, for the purpose of determination of export price for Hyosung their prices have been considered and the traders would face adverse facts available and attract residual dumping margin.

60. Adjustment towards ocean freight, inland and ocean insurance, packing expenses, handling and documentation expenses, bank charges, credit expenses and duty drawback received by the exporter against such exports have been considered to work out PCN-wise average net export price at the ex-factory level.

On the basis of the above ex-works weighted average normal values for Korea RP and net ex-works export prices determined at PCN levels for this exporter the dumping margin for this exporter has been worked out at PCN levels. Accordingly, weighted average dumping margin for this exporter works out to US\$****/Kg (0.7%). The dumping margin of this exporter has been found to be de minimis.

iv) Other Exporters from Korea RP

61. Export prices for the other non-cooperative exporters from the subject country has been determined based on the lowest transaction prices of the cooperating exporters for the PCNs exported to India by them.

62. The weighted average normal value determined for Korea has been compared with the net export prices determined for the non-cooperating exporters from the subject country to arrive at the weighted average dumping margin for non-cooperating exporters which works out to US\$****/Kg (73%).

63. The exporters from Korea, in their post disclosure comments, have argued that apart from question of legal validity of single normal value, PCN wise calculation might have also distorted the single normal value because of difference in grades and costs and prices of such grades. In the process regular grades of some exporters have got clubbed with value added grades of some other exporters to distort the over all normal values and also dumping margins.

64. In this connection the Authority notes the PCNs were devised and notified to all exporters well in advance and data was also obtained in the same format. Therefore, the determination, based on the PCNs, has been duly carried out as per the data submitted by the exporters, including the exporters from Korea RP. The Normal value and export price determination was also disclosed to these exporters through the verification report along with entire calculation sheets. The exporters pointed out certain discrepancies and requested for a meeting for reconciliation of the same. The exporters were given an opportunity of meeting and they availed this opportunity along with their lawyers and chartered accountants. The method of determination and calculations were checked and reconciled in their presence to their full satisfaction before the same was adopted in the disclosure statement. Therefore, the additional arguments of the exporters in respect of normal value and dumping margin determinations based on product code-wise segregation have not been accepted.

E.3 Malaysia

a) Normal Value

65. Only one exporter from Malaysia i.e., M/s Hualon Corporation has cooperated in this investigation and has filed a detailed questionnaire response.

The data filed by this cooperating exporter was also verified to the extent possible. The normal value of the subject goods in Malaysia has been determined on the basis of the verified data of this cooperating exporter.

66. During the period under investigation total domestic sale of this company was only *****MT, which was insignificant compared to the total sales of the company of the product under consideration. Therefore, the domestic sales did not satisfy the sufficiency test to be considered for determination of Normal Value. The claim of the exporter for consideration of the export price to a third country for determination of Normal Value was examined on the basis of volume of exports to other countries. It was found that export to Turkey was the highest among the other third countries. Therefore, export transactions in respect of exports to turkey were verified for normal value determination purpose. Though most of the PCNs exported to India are also exported to Turkey certain PCNs exported to India were not exported to Turkey during the POI. For such PCNs the normal value has been determined based on the cost of production of the subject goods plus reasonable profit as per the records of the company. Adjustments towards commission and rebates, inland and ocean freights, insurance and handling charges have been applied to arrive at net ex-works price of the subject goods. The export sales transactions to third country have been subjected to ordinary course of trade test based on the cost of production of the respective PCNs and normal values at PCN levels have been worked out. The normal value so worked out has been adopted as the normal value for the subject country. Accordingly, net ex-factory weighted average normal value for all exporters in Malaysia have been worked out.

b) Export Price and Dumping Margins

i) M/s Hualon Corporation

67. This exporter has exported about *****MT of the subject goods to India during the POI covering several PCNs. Out of this only ***** MT has been exported directly to India and rest of the exports are through different traders. The exporters has argued that the Authority may determine their export price based on the direct exports as the traders have not cooperated and would in any case face adverse consequence of non-cooperation. However, examination of the entire export data shows that the average sales prices of exports including sales through the traders are lower than the direct sales. Therefore, it is appropriate to consider all sales to India for the purpose of determination of the export price of this exporter. Adjustments towards, inland and ocean freights and insurance, credit costs, discounts and rebates, packing costs have been made to arrive at net ex-works export price for individual PCNs based on verified data of the exporter. Accordingly, ex-factory net export prices have been worked out.

68. On the basis of the above ex-works normal values and net ex-works export prices determined at PCN levels the weighted average dumping margin for this exporter has been worked out as US\$*****/Kg (12.38%).

ii) Other exporters from Malaysia

69. Export price for the other non-cooperative exporters from the subject country has been determined based on the lowest transaction prices of the cooperating exporters.

70. The weighted average normal value determined for the subject country has been compared with the net export prices determined for the non-cooperating exporters from the subject country to arrive at the dumping margin for non-cooperating exporters which works out as US\$*****/Kg (44%).

71. M/s Hualon Corporation, in its post disclosure submissions, has argued that that the fair comparison should have been carried out product code wise and not based on PCNs decided by the Authority as PCNs cover several product codes which vary in cost and prices. In this connection the Authority notes that in view of the fact that there is a very wide range of the product available in the market PCNs were devised and notified to all interested parties for the purpose of fair comparison and the exporters have provided their cost as well as price information based on these PCNs. Therefore, comparison has also been carried out based on these PCNs which is a standard practice followed for fair comparison purpose.

E.4 Chinese Taipei

72. Only two exporters of the subject goods in Chinese Taipei, namely M/s Nan Ya Plastics Corporation, and M/s China Man-Made Fiber Corporation, Chinese Taipei, have filed their questionnaire response to this investigation. However, M/s China Man-Made Fiber Corporation has withdrawn itself from the investigation after initial cooperation. Therefore, this company has been treated as a non-cooperating exporter for the purpose of this investigation.

a) Normal value

73. As per the records of the cooperating exporter from the subject country, i.e. M/s Nanya Plastics Corporation, the producer has sold *****MT of the goods in the domestic market covering several types of the product under consideration. The sales are to unrelated customers except for 650 MTs sold to its affiliated Company M/s Formosa Chemical Fibre Corporation. The sales to the related company account for little over ***% of the total sales and therefore, do not affect the general price structure. Therefore, the entire domestic sales transactions have been considered for determination of normal value. It was also noted that the company produces and sales a large variety FDY in the domestic

market. However, for the purpose of like to like comparison only those product types exported to India have been considered for determination of normal value.

74. The goods have been sold in the domestic market on delivered basis and the company has claimed adjustment towards direct selling expenses in respect of inland transportation, rebates and packing expenses. The domestic sales transactions were subjected to the ordinary course of trade test based on their respective cost of production and on the basis of the above data the net ex-factory normal values at PCN levels have been worked out. The normal value determined at the PCN levels for the cooperative exporter has been adopted as the normal value for the subject country.

b) Export Price and Dumping Margin

i) M/s Nan Ya Plastics Corporation

75. This Company has exported ***** MT of the subject goods to India during the POI. However, the entire export sales transaction has been through two distributors in Hong Kong/Korea and Thailand. There has been no direct export of the commodity to India during the POI. It was noticed that the goods are directly exported to India from their factory though the invoice is sent to the distributor from whom the payment is received. However, these distributors have not participated in the investigation and provided any details of their actual export price to India and their SGA expenses, if any. Therefore, the export price from these traders to India is not known. The exporter has argued that since the goods have been directly shipped by them to India and they are the exports made by them and the payment realized by them against these transactions is their export price. Since the traders have not cooperated in the investigation, the Authority need not determine a dumping margin for such traders in combination with them. But for the purpose of determining the dumping margin of Nanya entire transactions should be considered without linking them with any traders. Non-cooperating exporters/traders may attract an adverse finding and residual duty that may be determined by the Authority if they wish to continue to export Nanya's product to Indian market, as they have not provided their data. Nanya should not be penalized for the non-cooperation of unrelated traders on whom they have no control.

76. The export transactions to India are in FOB terms except for 5 transactions, which are in CIF terms. Adjustments towards commissions, inland and ocean freight; credit expenses; overseas insurance expenses; handling fee and bank expenses; packing costs; Customs administration fee, trade promotion fee and harbour construction fee paid to the government were verified from the records of the company and applied for arriving at the net ex-factory export price for individual PCNs.

77. On the basis of the above ex-works normal values and net ex-works export prices determined at PCN levels the weighted average dumping margin for this exporter has been worked out as US\$****per Kg (2.89%).

ii) Other Exporters from Chinese Taipei

78. Export prices for the other non-cooperative exporters from the subject country has been determined based on the lowest transaction prices of the cooperating exporters.

79. The weighted average normal value determined for the subject country has been compared with the net export prices determined for the non-cooperating exporters from the subject country to arrive at the dumping margin for non-cooperating exporters which works out as US\$****/Kg (37%).

80. The exporter in its post disclosure submissions has requested for certain modification in the method of conducting the ordinary course test and expressing the dumping margin as a percentage of the aggregate CIF price of all exports from the company. However, the Authority did not find any merit in these arguments and therefore, the findings in these respects are confirmed.

E.5 Dumping Margin Summary

81. On the basis of the above determination the dumping margin for the exporters in the subject countries works out as under:

Country/Territory	Exporters/Manufacturers	Dumping Margins US\$/ MT	Dumping Margin (%)
Indonesia	M/s P.T. Mutu Gading Tekstil	****	1.29%
Indonesia	All Others	****	39%
Korea RP	M/s H.K. Corporation	Price Undertaking	
Korea RP	M/s Hyosung Corporation	****	17.42%
Korea RP	M/s Saehan Industry	****	4.2%
Korea RP	M/s Huvis Corporation	****	0.7%
Korea RP	All Others	****	73%
Malaysia	M/s Hualon Corporation	****	12.38%
Malaysia	All Others	****	44%
Chinese Taipei	M/s Nan Ya Plastics Corporation	****	2.89%
Chinese Taipei	All Others	****	37%

F INJURY AND CAUSAL LINK EXAMINATION

F.1 VIEWS OF THE INTERESTED PARTIES

82. The exporters from Korea in their post preliminary submissions have argued that subject Goods from Indonesia and Malaysia compete most strongly with the subject Goods manufactured in India which is also reflected in the wider range of PCN exported to India by these countries. It has been argued that there are significant differences and the market segments served are substantially different. It has also been argued that degree of competition varies for each Subject Country and thus injury determination may be done separately for each Subject Country as cumulating will negate the impact of injury caused by these countries, which will unfairly penalise Korean exporters and inadequately defend Indian Producers from more closely competing Indonesian and Malaysian Subject Goods in case of dumping. Therefore the Authority may carry out injury analysis separately for each Subject Country.

83. The Korean exporters have also argued that DGCIS import data is incorrect which suggests that the allegedly adverse volume effect may be based on erroneous data. It has been argued that there is a healthy increase in capacity, production and utilization in India throughout the injury period considered and the performance of domestic sales remains much better than the base year. Marginal decline in domestic sales by the Producers is accounted for by almost the same increase in sales of other domestic producers indicating high domestic competition. It has been further argued that the problems with price are not unique to the POI but precede it even when imports from the Subject Countries were low. The prices have improved during the POI in some parameters contra-indicating dumping, despite increase in imports. The decline in landed prices from the base year is clearly less than the decline in Indian tariffs.

84. The exporters from Indonesia and Malaysia have argued that Price undercutting and Price underselling and entire injury analysis as well as NIP are also to be examined on the basis of product control numbers.

85. It has been argued by the interested parties that all the domestic producers may be examined and not just the applicant producers. The domestic industry has argued that each and every domestic producer is not similarly placed and it is not necessary that all non-applicant producers may also be examined as long as the applicant producers represent the domestic industry as per the definition of the domestic industry as laid down in Rule 2 (b). Moreover, the definition of the domestic industry would become redundant if the majority of the domestic producers are not granted protection because of the minority producers who are placed differently.

86. As regards the performance of the domestic industry in certain parameters the domestic industry has argued that it is well settled that no one or several of these factors can necessarily give decisive guidance. The Designated Authority would be justified to record a finding of injury based on one or more of parameters and is under no obligation to record a finding of injury only if majority of the factors show injury. Therefore, it has been argued that the statements of the exporters with respect to these factors are also required to be ignored.

F.2 EXAMINATION BY THE AUTHORITY

87. Article 3.1 of the ADA and Annexure II of the AD Rules provide for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products, with regard to the volume effect of the dumped imports. The authorities are required to examine whether there has been a significant increase in imports, either in absolute term or relative to production or consumption in the importing member. With regard to the price effect of the dumped imports, the authorities are required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in the importing country, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree, or prevent price increase, which would have otherwise occurred to a significant degree.

88. The Authority has taken note of the arguments of the interested parties on injury examination aspect and addressed the issues raised at appropriate places in this disclosure statement to the extent these arguments are valid. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts before it and the arguments of the interested parties.

F.2.1 Cumulative assessment of injury

89. As per annexure-II (iii), in cases where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to Anti-dumping investigation, the Authority is required to cumulatively assess effect of such imports, only when it determines that (a) the margin of dumping established in relation to imports from each country is more than 2% expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is 3% of the imports of like article and (b) cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic article.

90. The Authority notes that the margin of dumping in respect of each of the subject country is more than 2% and the volume of imports from each country is also more than 3%.

91. As far as the conditions of competition between imported products and the conditions of competition between the imported products and the like domestic product, the Authority notes that:

- (i) The subject goods have been imported from the subject countries under the same tariff classifications;
- (ii) The imported subject goods are commercial and technical substitutes of the domestically produced fully drawn yarn.
- (ii) The subject goods have been imported by the end users and other importers and the goods have entered the commerce of the country through similar channels;

92. Therefore, the Authority is of the view that the exports made from the subject countries compete in the same market, as these are similar products and the arguments of exporters from Korea RP for a de-cumulated injury examination are not valid.

93. In view of the above, the Authority hold that it is appropriate to cumulatively assess the effect of dumped imports of the subject goods from the subject countries, on the domestically produced like article in the light of conditions of competition between the imported products and the like domestic product. Therefore, for the purpose of injury and causal link analysis, as discussed above, the dumped imports from the subject countries have been cumulated for examination of volume and price effects of dumped imports of the subject goods from the subject countries on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any. The Rules provide for examination of the impact of dumped imports on the domestic industry on the basis of evaluation of all relevant economic factors and indices having bearing on the state of domestic industry. For the purpose of this examination the applicants constitute the domestic industry within the meaning of the term as defined under Rule 2(b) of the Rules.

94. The Authority also notes that the Hon'ble Supreme Court, in the Reliance Industries Vs Designated Authority held that the Authority is required to carry out the determination of the injury and NIP for the 'domestic industry as whole' and not in respect of any particular company or enterprise. The Hon'ble Supreme Court has also underlined that the domestic industry means "domestic producers as a whole". Therefore, in compliance with the above orders, the Authority called for cost and injury information from all the other known domestic producers. However, these producers have declined to provide any information on the above subject on the basis of their interpretation of the said judgment. It has been argued by the domestic industry and other known producers that the said judgment of the Hon'ble Court does not require inclusion of all domestic producers in the NIP and injury determination.

95. In its post disclosure submission the domestic industry has argued that the Designated Authority is interpreting the words "domestic industry as a whole" used by the Hon'ble Supreme Court in its judgment to mean the "domestic producers as a whole". In this connection, it was also submitted that the Hon'ble Court in that judgment has held that the injury as well as NIP has to be determined for the "domestic industry as a whole" and not in respect of any particular company or enterprise. In the same paragraph, the Hon'ble Supreme Court refers to the definition of domestic industry under Rule 2(b). Throughout the discussions, the Supreme Court has used the words "domestic industry as a whole" and not "domestic producers as a whole". Further, at no stage has the Supreme Court held that the term "domestic industry" has to be interpreted in any manner different from the definition provided in Rule 2(b). On the other hand, as stated earlier, the Court has clearly referred to the definition of "domestic industry" in the same paragraph.

96. The Authority notes that the Hon'ble Supreme Court has observed that the Authority is required to carry out the determination of injury and computation of NIP for the 'domestic industry as a whole and not in respect of any particular company or enterprise. The Hon'ble Supreme Court in their observation have emphasized that "domestic industry" means the "domestic producers as a whole". Therefore, the Authority is of the view that the interpretation of the applicants may not be in conformity with the said judgment. Therefore, the Authority has proceeded with the determination of the injury and NIP for the domestic industry as a whole to include all domestic producers of the subject goods to the extent the same was relevant and reasonably available. The cost and injury information of two major producers of the subject goods i.e. M/s Reliance Industries Ltd. and M/s Indorama have been examined with reference to their cost audit reports as available with the cost audit branch of the Ministry of Company Affairs. The cost and injury information of the third known producer of the subject goods i.e. M/s Paras Petrofils, are not available in the form of cost audit reports or in any other form. However, the Authority notes that as per the information supplied by this company in their support letter they had a production of about 2000 MT during the POI, which constitutes less than 3% of total domestic production of the subject goods. Therefore, the impact on account of this producer would not be significant. Accordingly, the injury examination has been carried out taking into account the information in respect of 8 known producers of the subject goods accounting for about 97% of the total domestic production and sales of the subject goods.

F.3.2 VOLUME EFFECT: Volume Effect of dumped imports and Impact on domestic Industry

97. The effects of the volume of dumped imports from the subject countries, as well as dumped imports from other countries have been examined as follows:

1) Import Volumes and share of subject countries:

98. For the purpose of injury examination the Authority has examined the DGCI&S import data, cooperating exporters export data and data from other secondary sources provided by the domestic industry. The Authority noted in the preliminary findings that there is a significant difference between the

volumes of imports reported in the DGCIS data under Customs head 5402.43 and the data submitted by the responding exporters from the subject countries. In view of this import reported under other customs heads were also examined and it has been noticed that substantial quantity of the subject goods have been imported under customs head 5402.42. Therefore, import data for the purpose of volume analysis has been reconciled taking into DGCIS import data under the above two heads and data submitted by the cooperating exporters. On the basis of this data the import volume of the subject countries are as follows:

				Qty In MT
Country	2001-02	2002-03	2003-04	POI
Indonesia	2697	8169	8243	6035
Korea RP	1454	4775	13359	13359
Malaysia	14314	18612	22360	36883
Taipei	3358	4495	5128	5128
Total Subject countries	21824	36052	49090	61405
Trend	100	165	225	281
Others	4235	4693	3335	2013
Trend	100	111	79	48
Total	26059	40745	52425	63418
Trend	100	156	201	243
Share	83.75%	88.48%	93.64%	96.83%

99. The above data indicates that the volume of imports from the subject countries has increased by 181% compared to the base year while the total imports have increased by 143%. The share of import from the subject countries in the total imports has increased by over 13% compared to the base year and about 3%, compared to the previous year.

ii) Domestic capacities and Capacity utilization

100. On the basis of the data available with the Authority the total capacity, production and capacity utilization of the domestic industry and the domestic industry as a whole work out as follows:

	2001-02	2002-03	2003-04	Qty in MT POI
Capacity of Domestic Industry	40340	61430	61490	64170
Trend	100	152	152	159
Capacity of other producers	21300	21300	32971	34754
Trend	100	100	155	163
Total Capacity	61640	82730	94461	98924
Trend	100	134	153	160
Production of DI	27141	48986	50666	46780
Trend	100	180	187	172
Capacity Utilization of DI	67%	80%	82%	73%
Production of others	13830	18495	29184	29896
Trend	100	134	211	216

Capacity Utilization others	65%	87%	89%	86%
Total domestic production	40971	67481	79850	76676
Trend	100	165	195	187
Overall capacity Utilization	66%	82%	85%	78%

101. The above data shows that capacity in the country has significantly increased by about 60% compared to the base year. However, domestic production of the subject goods, as well as the capacity utilization has declined after showing a significant increase in the previous years. Total domestic production has declined by about 4% compared to the previous year. Capacity utilization of the domestic industry as a whole has fallen by about 8% compared to the previous year after reaching a level of 85% in 2003-04. However, the Authority also notes that total domestic capacity has also increased by about 3000 MT during the POI and about 60% increase in capacity compared to the base year. Authority also notes that capacity and capacity utilization needs to be seen along with the demand and other parameters.

III) Demand, Output and Market shares

102. The increase in volume of imports has also been analyzed with respect to the growth in demand and market shares.

a) Sales

103. Domestic sales of the subject goods by the domestic industry as a whole have been examined as follows:

				Qty in MT
Sales	2001-02	2002-03	2003-04	POI
Sales of Domestic Industry	23586	39481	46653	44674
Trend	100	167	198	189
Other Domestic producers	12776	17906	26408	31416
Trend	100	140	207	246
Total Domestic Sales	36362	57387	73061	76090
Trend	100	158	201	209
Captive Consumption	396	847	1423	1281
Total Demand	62818	98979	126909	140789
Trend	100	158	202	224

104. The above data shows that the sale of the subject goods by the domestic industry as whole has increased significantly by over 100%. However, the Authority also notes that the demand of the subject goods in the domestic market has increased much more than the increase in the sales by the domestic industry as a whole.

105. The Authority notes that the demand has increased by about 124% compared to the base year and about 11% compared to previous year. The sales of the domestic industry as a whole has increased by 109% compared to the base year and also by about 4% compared to the previous year.

b) Demand and Market Share

Share in Demand	2001-02	2002-03	2003-04	POI
Domestic Industry	38%	40%	37%	32%
Trend	100	106	98	85
Other Domestic Producers	20%	18%	21%	22%
Trend	100	89	102	110
Total Domestic sales	58%	58%	58%	54%
Trend	100	100	99	93
Subject countries	35%	36%	39%	44%
Trend	100	105	111	126
Other Countries	7%	6%	4%	2%
Trend	100	76	51	32

106. The share of the domestic industry has declined from 38% to 32% and the share of all domestic producers in the total demand has also declined from 58% to 54%. The market share of imports from the subject countries has risen from about 35% in 2001-02 to 44% during the period of investigation. Share of other countries in the total demand has significantly declined from 7% to 2%. Therefore, the Authority also notes that the imports from subject countries over the investigation period have, not only increased in absolute terms but have also increased in relation to total imports, total demand and the domestic production in India.

F.2.3 Price Effect of the Dumped imports on the Domestic Industry

107. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject countries has been examined with reference to the price undercutting, 'price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis the weighted average cost of production, weighted average Net Sales Realization (NSR) and the Non-Injurious Price (NIP) of the Domestic industry determined in compliance with the judgment of the Hon'ble Supreme Court, have been compared with the landed cost of imports from the subject countries.

(i) Price undercutting and underselling effects

Rs/MT

	2001-02	2002-03	2003-04	POI
Domestic Selling Price	*****	*****	*****	*****
Trend	100	94	98	101
Cost to Make and Sale	*****	*****	*****	*****
Trend	100	98	100	109
Landed values				
Indonesia	83280	78776	65780	62251
Korea RP	93564	85308	65839	64580
Malaysia	81834	79177	61834	58399

Taipei	81877	74169	61599	60310
Subject countries	82801	79274	63562	60588
Trend	100	96	77	73
Price Undercutting				
Indonesia				30-40%
Korea RP				25-35%
Malaysia				40-50%
Taipei				35-45%
Subject countries				35-45%
Price Underselling				
Indonesia				45-55%
Korea RP				40-50%
Malaysia				50-60%
Taipei				50-60%
Subject countries				45-55%

108. The cost to make and sale as well as the selling price (net sales realization) have been determined for the domestic industry as a whole based on the information provided by the domestic industry and data available in the cost audit reports of other known producers as recorded earlier. The above data shows significant increase in cost of sales compared to the base year and the previous year. However, the net sales realization of the domestic industry as a whole has increased by only 1%. The Authority notes that the landed value of imports from the subject countries shows significant decline.

109. Price undercutting effect of dumped imports from the subject countries has been determined by comparing the weighted average landed value of dumped imports from the subject countries over the entire period of investigation with the weighted average net sales realization of the domestic industry as observed by the Hon'ble Supreme Court. For this purpose landed value of imports has been calculated by adding 1% handling charge and applicable basic customs duty to the CIF value of imports from the subject countries.

110. In determining the net sales realization of the domestic industry, the rebates, discounts and commissions offered by the domestic industry and the central excise duty paid have been rebated. For the purpose of price underselling determination the weighted average landed prices of imports from subject countries have been compared with the Non-injurious selling price of the domestic industry as observed by the Hon'ble Supreme Court determined for the POI.

111. As far as price undercutting is concerned, the imports from the subject countries show significant price undercutting. The landed value of imports from all the subject countries, individually and cumulatively, have been found to be significantly below the non-injurious price of the domestic industry determined by the Authority indicating significant price underselling effect on the domestic industry.

(ii) Price suppression and depression effects of the dumped imports:

112. The price suppression/depression effects of the dumped imports have also been examined with reference to the cost of production, net sales realization of the domestic industry and the landed values from the subject countries. The trend of cost of production of the domestic industry as a whole shows an increase of about 9% during the injury investigation period. However, the selling price of the domestic industry as a whole shows a marginal increase of 1% only. The cost of sales and selling price compared to the trend of import prices indicate that the domestic industry has been prevented from increasing its prices commensurate to rise in the cost of production due to the price effects of dumped imports from the subject country, indicating significant price suppression.

F.2.4 Examination of other Injury Parameters

113. After having examined the effect of dumped imports on the volumes and prices of the domestic industry and major injury indicators like volume and value of imports, capacity, output, capacity utilization and sales of the domestic industry, as well as demand pattern with market shares of various segments, other economic parameters which could indicate existence of injury to the domestic industry have been analysed by the Authority. However, the Authority notes that precise information on all the injury parameters in respect of the product under consideration for the non-participating domestic industry are not available in the cost audit reports or any other public/confidential document to make an objective examination of all injury parameters for the domestic industry as a whole. Therefore, to the extent possible, data of the participating domestic industry has been taken into account for examination of the following parameters.

i) Actual and potential effect on productivity

114. The Authority notes that total production of the subject goods as well as production of the applicant domestic industry has increased by about 87% and 72% respectively, compared to the base year. However, there is a significant reduction in number of employees of the participating domestic industry indicating significant improvement in productivity of the domestic industry over the injury investigation period.

ii) Actual and potential effects on Profits

115. Based on the data of cost and prices of the subject goods of the domestic industry as a whole profitability of the industry has been worked out as follows:

Profitability	2001-02	2002-03	2003-04	POI
Weighted average NSR of DI as a whole	*****	*****	*****	*****
Trend	100	94	98	101
Weighted average Cost of sales of DI as a whole	*****	*****	*****	*****
Trend	100	98	100	109
Profit/Loss Per MT	*****	*****	*****	(*****)
Trend	100	20	59	-33

116. The above data indicates that the profitability of the domestic industry as a whole has significantly declined and at the aggregate level the performance of the domestic industry has deteriorated from the level of significant profit to loss during the injury investigation period in spite increase in production and sales. The cause of decline in the profit is the decline in the landed value of the subject goods from the subject countries.

iii) Actual and potential effects on cash flow

117. Cash flow position in respect of non-participating domestic producers is not available. However, the data of the participating domestic industry shows the cash flow position of the domestic industry has deteriorated over the injury investigation period.

iv) Employment and wages

118. Effects of dumped imports on the employment and wages have been examined with reference to the participating domestic industry. The data indicates that number of employees have been reduced while the wages has increased during the same period.

	2001-02	2002-03	2003-04	POI
No of Employees of DI	556	596	575	476
Index	100	107	103	86
Wages Total (Rs. Lacs)	*****	*****	*****	*****
Index	100	148	160	182

v) Return on investment and ability to raise capital

119. Examination of the financial performance of the participating domestic industry in terms of its cash profits and return on investment shows significant deterioration. From positive return of about 5% the domestic industry has dipped into negative return on its investments. While capital employed in the domestic operation has increased, the profits and return on investments show significant decline compared to the base year due to pressure of dumped imports from the subject countries.

Return on Investment	2001-02	2002-03	2003-04	POI
Profit/Loss (Rs. Lacs)	*****	*****	*****	*****
Add: Interest	*****	*****	*****	*****
Profit/Loss Before Interest	*****	*****	*****	*****
Capital Employed	*****	*****	*****	*****
Return on Investment	4.67%	4.23%	-0.64%	-8.49%

v) Investment and Ability to raise Capital Investments

120. The Authority notes that there is a marginal addition of capacity during the POI and domestic industry has not invested any major capital in this business. The Authority finds that the ability of the domestic industry to raise capital investment for any further expansion of capacity is likely to be adversely affected in view of the negative returns during the period of investigation.

v) Magnitude of Dumping

121. Magnitude of dumping, as an indicator of the extent to which the dumped imports can injure the domestic industry, shows that the dumping margins determined for the subject countries have been found to be significant.

vi) Factors affecting prices

122. The Authority notes that apart from the applicants there are few other domestic producers of the subject goods in the domestic market in India catering to about 22% of the total market demand. The data of these producers show significant cost and price difference between the domestic producers. However, the injury investigation has been carried out for the domestic industry as a whole, including the other known producers. The Authority also notes that the dumped imports from the subject countries have been found to have significant price undercutting and underselling effect on the domestic industries prices indicating that the dumped imports have significantly affected the domestic prices in India.

vii) Inventories

Inventory	2001-02	2002-03	2003-04	POI
Domestic Industry	*****	*****	*****	*****
Trend	100	125	103	73

123. The inventory data of the domestic industry indicates significant decline in inventory holding.

viii) Growth

124. The Authority finds that capacity, production, sales and demand of the subject goods in the country has increased significantly in the injury investigation period and shows positive growth. However, production and sales have not kept pace with the growing demand. In spite of rise in demand market share of the domestic industry as a whole has declined by over 4% during the same period.

G OTHER FACTORS AND CAUSAL LINK

125. The Authority notes that there is a significant rise in the dumped imports from the subject countries during the investigation period resulting in significant erosion in the market share of the domestic industry as a whole. The dumped imports have increased both in absolute term and in relation to the volume of imports, production and sales of the subject goods in India.

126. The dumped imports have also significantly undercut the domestic industries prices causing significant price suppression in the domestic market which has resulted in loss to the domestic industry as a whole.

127. Therefore, the Authority holds that the dumped imports have significant volume and price effects on the domestic industry.

128. Having examined the state of the domestic industry and the effect of dumped imports in terms of the Rules, the Authority has also examined other factors other than the dumped imports that might have significantly affected the domestic industry. The Authority notes that none of the interested parties have brought any other factor that might have affected the domestic industry to the notice of the Authority. Therefore, in this connection the following mandatory factors have been examined.

i) Imports from other countries

129. The Authority notes that imports from the subject countries constitute about 97% of total imports of the subject goods and between 2001-02 and the POI, the dumped imports from subject countries have increased significantly from 82% to 97% as a proportion of total imports. Import from the other sources is a very small proportion of the total imports and demand in the market. Therefore, the imports from other sources do not appear to have any significant impact on the domestic industry.

ii) Trade restrictive practice and competition between the foreign and domestic producers

130. The Authority notes that the subject goods are freely importable and there is no trade restrictive practices followed by the Indian producers and other competing industries. The Authority also notes that the injury has been examined for the domestic industry as a whole taking into account cost and prices of all domestic producers at aggregate level. Therefore, the competition between various domestic producers cannot be attributed as the cause of injury to the domestic industry.

iii) Contraction of demand or Changes in the pattern of consumption

131. It is noted that there is no contraction in the overall demand during the period under consideration. On the contrary, the overall demand has increased by 124% during the POI. Therefore, the possible decline in demand is not a factor which could have caused injury to the domestic industry

iv) Technology

132. The interested parties have raised the issue regarding the difference in technology being adopted by the domestic industry and the exporters in the subject countries resulting into cost efficiency for the exporters. However, in the absence of sufficient evidence, the Authority is of the opinion that difference in technology, if any, has not been demonstrated to have any adverse effect on the performance of the domestic industry.

v) Export performance

133. The Domestic Industry has very negligible export of the subject goods during the period of investigation as well as during previous years. The Authority

notes that the export performance of the domestic industry has shown improvement.

vi) Productivity

134. As regards the productivity of the domestic industry, the authority notes that the productivity has improved during the POI.

135. The above examination shows that there is no other significant factor that might have affected the performance of the domestic industry and caused injury to the domestic industry. Therefore, the Authority concluded that the dumped imports, through volume and price effects have caused material injury to the domestic industry.

H. CONCLUSION ON INJURY AND CAUSAL LINKS

136. On the basis of the examination of the conditions of the domestic industry and non-attribution factors in the previous section the Authority finds that

- a. the quantum of imports from the subject countries have increased in absolute terms as well as in relation to total demand and domestic production in India;
- b. the market share of the domestic industry as a whole has declined after healthy growth in the previous years while that of imports has increased;
- c. the profitability, return on investment and cash flows become negative in the period of investigation from a positive level in the base year;
- d. Since the ROCE for the domestic industry is negative, their ability to raise capital investment is adversely affected.
- e. The capacity utilization and sales volume of the domestic industry has declined after healthy growth in the previous years;
- f. There is severe price undercutting as well as price underselling;
- g. No other factor, other than the dumped imports, have been brought to the notice of the Authority, that could have caused injury to the domestic industry

137. In view of the above the Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury and the injury has been caused by the dumped imports from the subject countries.

H. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

H.1 Determination of Non-injurious price

138. The Authority determined the non-injurious price for the domestic industry as a whole in accordance with the judgment of the Hon'ble Supreme Court of India as quoted earlier and a detailed disclosure of the methodology of

determination of the NIP was made to the domestic industry. The domestic industry has argued that the determination of the NIP is not in accordance with the principles and law laid down by the Hon'ble Court. The comments of the domestic industry on the methodology adopted by the Authority on determination of the non-injurious price have been taken on record.

139. The Authority notes that the Non-injurious price of the domestic industry as a whole has been determined in accordance with the judgment of the Hon'ble Supreme Court of India taking into account the guidelines and methodology set by the Hon'ble Supreme Court of India and the weighted average NIP for the domestic industry as a whole as been determines as Rs*****/per MT.

140. The non-injurious price determined by the Authority is the weighted average of all types of the subject goods produced by the domestic industry and the same has been compared with the weighted average landed values of the exports from the subject countries for determination of injury margins. The weighted average landed price of the exports from the subject countries and the injury margins have been worked out as follows:

Injury Margin Calculations		
Name of company	Injury Margin US\$/Kg	Injury Margin %
M/s P.T. Mutu Gading Tekstil, Indonesia	*****	-5 to 15%
Other Exporters, Indonesia	*****	40-50%
M/s H.K. Corporation, Korea	Price undertaking	
M/s Hyosung Corporation, Korea	*****	0-10%
M/s Saehan Industry, Korea	*****	-20-30%
M/s Huvis Corporation, Korea	*****	-15-25%
Other Exporters, Korea	*****	40-50%
M/s Hualon Corporation, Malaysia	*****	20-30%
Other Exporters, Malaysia	*****	50-60%
M/s Nan Ya Plastics Corporation, Chinese Taipei	*****	20-30%
Other Exporters, Chinese Taipei	*****	45-55%

I INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

141. The Authority holds that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition.

142. The Authority also recognizes that though the imposition of anti dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products, however, fair competition in the Indian market will not be reduced by these anti-dumping measures. On the contrary, imposition

of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by the dumping practices and would prevent the decline of the domestic industry and would help in maintaining availability of wider choice of the subject goods to the consumers.

J. CONCLUSIONS

143. The Authority has, after considering the foregoing, come to the conclusion that:

- a. Subject goods originating in or exported from subject countries have been exported to India below their normal values.
- b. The domestic industry has suffered material injury.
- c. The injury has been caused to the domestic industry by dumped imports of subject goods originating in or exported from the subject countries.

K. Recommendations

144. Having initiated and conducted investigation into dumping, injury and causal links between dumping and injury to the domestic industry in terms of the Rules laid down and having established positive dumping margin against the subject country, as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of definitive duty is required to offset dumping and injury to the domestic industry.

145. Therefore, Authority considers it necessary and recommends imposition of definitive anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries in the form and manner described hereunder except for the exporter from whom the Authority has accepted a voluntary price undertaking.

146. Having regard to the lesser duty rule followed by the authority, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends that definitive anti dumping duties be imposed on all imports of Fully Drawn Yarn falling under chapter 54 of Custom Tariff Classification Act 1975, originating in or exported from Indonesia, Korea RP, Malaysia and Chinese Taipei. The anti-dumping duty shall be the amount mentioned in Column No. 9 of the following table.

Duty Table

Sl. No	Sub-heading	Description of goods	Specification	Country of origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit of Measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	5402.43 & 5402.42	Fully Drawn Yarn**	Any	Indonesia	Any	M/s P.T. Mutu Gading Tekstil, Indonesia	M/s P.T. Mutu Gading Tekstil, Indonesia	NIL	MT	US\$

2.	-Do-	-Do-	Any	Indonesia	Any	M/s P.T. Mutu Gading Tekstil, Indonesia	Any other than above	490	MT	US\$
3.	-Do-	-Do-	Any	Indonesia	Any	Any other than above	Any	490	MT	US\$
4.	-Do-	-Do-	Any	Any other than Indonesia	Indonesia	Any	Any	490	MT	US\$
5.	-Do-	-Do-	Any	Korea RP	Any	M/s H.K. Corporation, Korea	M/s H.K. Corporation, Korea	Price Undertaking		
6.	-Do-	-Do-	Any	Korea RP	Any	M/s H.K. Corporation, Korea	Any other than above	588	MT	US\$
7.	-Do-	-Do-	Any	Korea RP	Any	M/s Hyosung Corporation, Korea	M/s Hyosung Corporation, Korea	64	MT	US\$
8.	-Do-	-Do-	Any	Korea RP	Any	M/s Hyosung Corporation, Korea	Any other than above	588	MT	US\$
9.	-Do-	-Do-	Any	Korea RP	Any	M/s Saehan Industries Inc, Korea	M/s Saehan Industries Inc, Korea	Nil	MT	US\$
10.	-Do-	-Do-	Any	Korea RP	Any	M/s Saehan Industries Inc, Korea	Any other than above	588	MT	US\$
11.	-Do-	-Do-	Any	Korea RP	Any	M/s Huvis Corporation, Korea	M/s Huvis Corporation, Korea	Nil	MT	US\$
12.	-Do-	-Do-	Any	Korea RP	Any	M/s Huvis Corporation, Korea	Any other than above	588	MT	US\$
13.	-Do-	-Do-	Any	Korea RP	Any	Any other than the Korean producers named above	Any	588	MT	US\$
14.	-Do-	-Do-	Any	Any other than Korea RP	Korea RP	Any	Any	588	MT	US\$
15.	-Do-	-Do-	Any	Malaysia	Any	M/s Hualon Corporation,	M/s Hualon Corporation,	163	MT	US\$
16.	-Do-	-Do-	Any	Malaysia	Any	M/s Hualon Corporation,	Any other than above	456	MT	US\$
17.	-Do-	-Do-	Any	Malaysia	Any	Any other than above	Any	456	MT	US\$
18.	-Do-	-Do-	Any	Any other than Malaysia	Malaysia	Any	Any	456	MT	US\$
19.	-Do-	-Do-	Any	Chinese Taipei	Any	M/s Nan Ya Plastics Corporation	M/s Nan Ya Plastics Corporation	40	MT	US\$

20.	-Do-	-Do-	Any	Chinese Taipei	Any	M/s Nan Ya Plastics Corporation	Any other than above	390	MT	US\$
21.	-Do-	-Do-	Any	Chinese Taipei	Any	Any other than above	Any	390	MT	US\$
22.	-Do-	-Do-	Any	Any other than Chinese Taipei	Chinese Taipei	Any	Any	390	MT	US\$

****Fully Drawn or Fully Oriented Yarn / Spin Draw Yarn / Flat Yarn of Polyester**

L FURTHER PROCEDURE

147. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

148. The Authority may review the need for continuation, modification or termination of the definitive measure as recommended herein from time to time as per the relevant provisions of the Act and public notices issued in this respect from time to time. No request for such a review shall be entertained by the Authority unless the same is filed by an interested party as per the time limit stipulated for this purpose.

CHRISTY FERNANDEZ, Designated Authority

Annexure-I

Price Undertaking

Sub: Price Undertaking by M/s H. K. Corporation, Korea, in the antidumping investigation concerning import of FDY from Korea RP, Chinese Taipei, Malaysia and Indonesia.

NO.14/3/2005-DGAD: - Whereas having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, (hereinafter referred to as the Rules) thereof, the Designated Authority (hereinafter referred to as Authority), initiated an investigation into the alleged dumping of Fully Drawn or Fully Oriented Yarn / Spin Draw Yarn / Flat Yarn of Polyester (herein after referred to as subject goods) from Indonesia, Republic of Korea, Malaysia and Chinese Taipei (herein after referred to as subject countries), vide notification dated 27th June 2005, on the basis of a fully documented application received from the Association of Synthetic Fibre Industries (hereinafter referred to as the Applicant) on behalf of domestic producers namely M/s Central India Polyesters Ltd., M/s Century Enka Ltd., M/s Garden Silk Mills Ltd., M/s Nova Petrochemicals Ltd., M/s Recron Synthetics Ltd. and M/s Welspun Syntex Ltd., alleging dumping of the subject goods from the subject countries and consequent injury caused to the domestic industry.

2. The Authority notified its preliminary findings vide notification dated 3rd July 2006 and the Department of Revenue, vide its Notification No 82/2006-Customs dated 21st August 2006, imposed provisional duty on the subject goods as recommended by the Authority.

3. And Whereas M/s H. K. Corporation, 19F Kukdong B/D 60-1, 3ka, Chungmuru Chung Gu, Deoul, Korea, has given a voluntary price undertaking in terms of Rule 15 of the said Rules as per the terms and conditions set out in the non-confidential version of the price undertaking annexed herewith.

4. The Designated Authority hereby accepts the said undertaking in terms of Rule 15 of the said Rules as per the terms and conditions set out in the said undertaking.

5. The Price undertaking is valid for the following product specifications and at the price indicated hereunder for direct export by this producer only:

<u>Product specification</u>	<u>Undertaking Price</u>
1. FDY 75/36 SBR : FOB Price Korea RP : US\$ 1.40 per Kg	
2. FDY 75/36 SD : FOB Price Korea RP : US\$ 1.46 per Kg	
3. FDY 75/72 SD : FOB Price Korea RP : US\$ 1.46 per Kg	

6. If the exporter intends to export any other product in future they would attract the all other/residual duty as recommended in the final findings of the Authority.

7. The above undertaking prices have to be revised in the event of any upward or downward revision of the domestic price and/or main raw material prices by +/- 5%. The exporters shall be under obligation to file periodic reports of its domestic sales and exports sales for monitoring the undertaking as per the conditions of the undertaking annexed herewith.

8. Upon acceptance of the price undertaking offered by the exporter the investigation against M/s H. K. Corporation is hereby suspended and the Authority has not recommended imposition of any definitive duty on this exporter till the undertaking accepted by the Authority remains valid.

9. The price undertaking shall remain valid during for the period for which the measure recommended in the final findings of the Authority remains in force. However, the Authority shall review the need for continuance of this undertaking from time to time.

10. In case of any violation of the conditions of this undertaking the Authority shall recommend imposition of provisional duty from the date of such violation in accordance with the provisions of these Rules.

Annexure-II**PRICE UNDERTAKING**

Undertaking offered by M/s HK Corporation Address 19F Kukdong B/D, 60-1, 3ka, Chungmuro Chung Gu, Seoul, Korea Phone/Fax# 82-775-8866 / 82-775-6455 to the Designated Authority, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, Government of India, New Delhi, in the matter relating to Anti-dumping investigation concerning exports of Fully Drawn or Fully Oriented Yarn/Spin Draw Yarn/Flat Yarn from HK Corporation, Republic of Korea.

1. M/s HK Corporation Address 19F Kukdong B/D, 60-1, 3ka, Chungmuro Chung Gu, Seoul, Korea, hereinafter also referred to as "the company", offers to the Designated Authority (hereinafter referred to as Authority) of Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce), Government of India, the undertaking described below and in appendices A, B & C which are attached to and form an integral part of this undertaking concerning export of Fully Drawn or Fully Oriented Yarn/Spin Draw Yarn/Flat Yarn from HK Corporation, Republic of Korea, (hereinafter referred to as subject country), as defined in paragraph 2, which are the subject of a dumping investigation initiated by the Authority vide Notification dated 27th June, 2005 and preliminary findings, in respect of which was notified by the Authority, vide Notification dated on 3th July, 2006.

2. This undertaking pertains only to those goods named by the Authority in the above-noted preliminary findings. Such goods are defined as:
Fully Drawn or Fully Oriented Yarn/Spin Draw Yarn/Flat Yarn.

(Full Description of the goods with HS classification and specification, if required).

Description : The product involved in the present investigation is All Fully Drawn or Fully Oriented Yarn / Spin Draw Yarn / Flat Yarn of Polyester (non-textured and non-POY) and other yarns conforming to the tariff description of customs heading 5402.43 The above-mentioned product in commercial market parlance is generally known as 'Fully Drawn Yarn'.

The goods described herein are hereinafter referred to as "the subject goods".

3. The company agrees not to sell the subject goods for export to India at prices lower than (*state terms of undertaking, for example, specify whether prices are FOB, CIF, etc. and indicate location*) prices stipulated in the grid in Appendix "A".

i) If final findings reference price on other Korean exporters is lower than the price in Appendix A, the lower price will prevail.

ii) variation mechanism to be inserted in case of variation in main raw material price, domestic or export prices by $\pm 5\%$.

- iii) Anti-dumping duty must be in force in respect of imports from the subject countries.
4. The company agrees not to circumvent this undertaking in any way, including shipment of the subject goods to India through a subsidiary, branch, agent or other company, or by the direct shipment of the subject goods to India from a country other than the subject country. In the event of transshipment of subject goods from a country other than the subject country by the company, the price would be in compliance of this undertaking and to the satisfaction of the Authority and declaration to this effect shall be made on the export to India.
 5. The company agrees to provide to the Authority copies of documents as described in Appendix "B".
 6. The Company agrees to provide to the Authority information and associated documents as described in Appendix "C".
 7. The Company agrees that prior to the execution of any sale for export to India of new products, models or sizes which fall within the definition of the subject goods in paragraph 2, but are not referred to specifically in Appendix "A" to notify the Authority of such a sale; provide any information that may be requested by the Authority to determine an appropriate undertaking price at that time; and to amend Appendix "A" of this undertaking to include such new products, models or sizes.
 8. The Company agrees to provide information, which may be required by the Authority to demonstrate adherence to this undertaking and to permit, upon request, verification by the Authority of any such information provided. The company could also approach the Designated Authority for review in the event of change in the circumstances.
 9. The Company agrees to, on the advice of the Designated Authority, amend this undertaking, including its appendices, in whole or in part, to take into account any changes in circumstances from those which prevailed at the time this undertaking was accepted. The company could also approach the Designated Authority to seek review on account of a change in circumstances.
 10. The Company agrees that this undertaking shall take effect on the date of its acceptance by the Authority and Notification by the Government of India and shall apply to all subject goods exported by the company on or after this date.
 11. The Company acknowledges the authority of the Designated Authority to terminate this undertaking at any time after its acceptance where the Authority:
 - (a) is satisfied that the undertaking has been or is being violated;
 - (b) is of the opinion that, as a result of new information not available at the time of the acceptance of the undertaking, the undertaking would have not been accepted; or

- (c) is of the opinion that, as a result of changing circumstances, the undertaking no longer fulfils its objectives.
12. The Company further acknowledges the authority of the Designated Authority, upon termination of this undertaking, to make a preliminary determination with respect to the goods, as defined in paragraph 2, and to resume the investigation.
13. The Company shall give the Authority written notice of its intention to withdraw from this undertaking at least 30 days prior to the date of such withdrawal.
14. This undertaking shall be binding upon all successors and assigns of the Company.

In witness whereof the Company has hereto affixed its corporate seal, attested by its duly authorized officer(s) on this 26th date of Dec, 2006.

HK Corporation

Signature of witness

Signature of authorised officer(s)

Name and title of witness

Name and title(s) of authorised officer(s)

경북 구미시 공단동 291-22

주식회사 H K

관리인 김용대 . 박노철

This undertaking document and the attached appendices A, B and C are stamped **CONFIDENTIAL** as they contain sensitive commercial information relating to our business operations

APPENDIX "A"

This Appendix is attached to and forms an integral part of the undertaking submitted by M/s HK Corporation to the Designated Authority, Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce), Government of India, on 26th Dec (Date of Submission) 2006

In accordance with paragraph 3 of the undertaking, the Company agrees not to sell the subject goods to importers in India at prices lower than the prices stipulated in the following grid:

UNDERTAKING PRICE GRID

PRODUCT (CLASS GRADE/SIZE)	PRODUCT DESCRIPTION	UNDERTAKING PRICE
FDY	(PCN: 32BT), Fully Drawn Yarn	US \$ xxx/KG
FDY	(PCN: 32SR), Fully Drawn Yarn	US \$ xxx /KG
FDY	(PCN: 33SR), Fully Drawn Yarn	US \$ xxx /KG
<u>Sales Term: FOB</u>		

Location: NHAVA SHEVA

All prices are quoted in (state the currency of settlement and the unit of measure if appropriate), (state terms of sale, for example, specify whether prices are FOB, CIF, etc. and indicate location). The selling prices in the undertaking price grid shall apply to shipments of the subject goods that are imported into India (on or after the date of acceptance of this undertaking by the Authority).

In witness whereof the Company has hereto affixed its corporate seal, attested by its duly authorised officer (s) on this 26th date of Dec, 2006.

HK Corporation

Signature of witness

Signature of authorised officer(s)

Name and title of witness

Name and title(s) of authorised officer(s)

경북 구미시 공단동 291-22

주식회사 H K

관리인 김용대 . 박노철

APPENDIX "B"

This Appendix is attached to and forms an integral part of the undertaking submitted by M/s. HK Corporation to the Designated Authority, Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce), Government of India on 26-12-2006 (Date of Submission).

In accordance with paragraph 5 of the undertaking, the Company agrees to provide the Department with the following documents:

- (i) Each time there is a price change in the Company's domestic market, a copy of the notification letter, if any, sent to customers, along with the revised price lists. These documents will be faxed immediately to the attention of the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties Division, Attention: Mr. Investigating Officer, accompanied by a covering letter referring to this undertaking. The original documents will be forwarded to the Department by express delivery to the address in section (iii) below;
- (ii) An amended Appendix "A" will also be telefaxed at the same time as the transmittal being made in accordance with section (i) above. The amendment will reflect the revised undertaking prices calculated (details regarding methodology used in amending appendix 'A' including an explicit re-statement of the terms of sale, currency of settlement and unit measure where required), to the current prices in effect as stipulated in the undertaking price grid contained in Appendix "A". The original document will be forwarded to the Department by express delivery in conjunction with the documents noted in section (i) above; and
- (iii) *(state other documents which will be provided and when they will be provided).* These documents will be forwarded under a covering letter referring to this undertaking to:

The Designated Authority, Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry (Department of Commerce) Udyog Bhavan,
New Delhi, India

In witness whereof the Company has hereto affixed its corporate seal, attested by its duly authorized officer(s) on this 26th day of Dec, 2006.

HK Corporation

Signature of witness
Name and title of witness

Signature of authorised officer(s)
Name and title(s) of authorised officer(s)

경북 구미시 공단동 291-22
주식회사 H K
관리인 김용대 . 박노철

APPENDIX "C"

This Appendix is attached to and forms an integral part of the undertaking submitted by M/s HK Corporation to the Designated Authority, Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce), Government of India on 26-12-06 (Date of Submission).

In accordance with paragraph 6 of the undertaking, the Company agrees to provide to the Designated Authority Invoice and/or the commercial invoice submitted to meet Authority's invoicing requirements with respect to each shipment of the subject goods the following information:

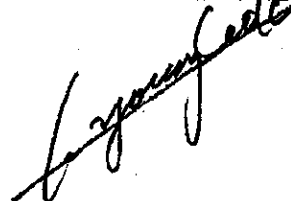
- Customer's order number and date of order;
- Product (CLASS/GRADE/NUMBER/SIZE ETC.);
- Product description in sufficient detail to match the applicable description of the subject good(s) found in the undertaking price grid in Appendix A;
- Terms and conditions of sale;
- Quantity of (product) in (unit of measurement) for each (class/grade/number/size etc.); and
- Unit price of the (product) in (currency of settlement) for (class/grade/number/size etc.).

In addition, the Company agrees to certify on each document:

"These prices are in accordance with M/s HK Corporation current undertaking accepted by the Designated Authority and the Authority for Customs and Excise, India, on the date of acceptance by the Government of India.

In witness whereof the Company has hereto affixed its corporate seal, attested by its duly authorized officer(s) on this 26th date of Dec, 2001.

HK Corporation



Signature of witness
Name and title of witness

Signature of authorised officer(s)
Name and title(s) of authorised officer(s)

경북 구마시 공단동 291-22

주식회사 H K

관리인 김용대 박노철

8